BLM Academy

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, C.B.S.E. Affiliation No.: 3530343
ISO 9001:2015 (QMS) Certified School

पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीताल-356-2021-2023

Wish You all a Very Happy New Year

"The Best Way To Predict Your Future Is To Create It With BLM Academy."

Vision -
To prepare the children empowered with Indian ethical and spiritual values to face the global challenges.

Mission-
To produce enriched and enlightened human resource for the country.

Pillars -
SATYA, PURUSHARTH & PARAMARTH

Goal-
ब्रह्म तत् लक्ष्यम्

Admission Open
For The Academic Session 2024-25
(Classes Nursery to IX & XI)

LIMITED SEATS
APPLY NOW

Streams: Science, Commerce & Humanities

Celebrate The Gift of Life

+91 7055515681
+91 7055515683
www.blmacademy.com

Padampur Devaliya, Gora Parao,
Haldwani (Nainital), Uttarakhand

blma.principal@gmail.com

प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।। (मुण्डक उपनिषद)

दिसंबर 2024

उत्तरांचल दीप

यशस्वी पत्रकार वेदप्रकाश गुप्ता को समर्पित

पत्रिका

ई-मेल: uttranchaldeepatrika@gmail.com

Web: uttaranchaldeep.com

एआई इंजीनियर सुसाइड

₹:40

सोनिया व सोरोस का रिश्ता क्या ?

सोनिया गांधी पर जॉर्ज सोरोस से संबंध होने का आरोप है, यह आरोप सोनिया गांधी के राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा दाग है, यदि जांच में ये साबित होता है कि सोनिया गांधी के संबंध देश विरोधी ताकत यानी जॉर्ज सोरोस से हैं तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है।

Nupur Creations

Jute Hand Bags, Craft & Many More

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
वोकल फॉर लोकल नीति से प्रेरित
उत्तराखंड के हस्तकला के क्षेत्र में
उभरता नाम

नुपूर

उत्तराखंड की हस्तकला को राष्ट्रीय
पहचान दिलाना हमारा लक्ष्य
उत्तराखंड की महिलाओं को
आत्मनिर्भर बनाना हमारा प्रयास
जूट से बने फेंसी आइटम, होम
डेकोरेशन की फेंसी सामग्री,
गिफ्ट आइटम की बड़ी रेंज ऑन
लाइन उपलब्ध

VOCAL FOR लोकल

SHAKTI PURAM GALI,
NAWABI ROAD, HALDWANI
(NAINITAL), Uttarakhand

CALL:
05946 220841, +91 9410334041
Paytm +91 9760590897

www.facebook.com/nupurnrityakalakendra
You Tube: Search: nupurnrityakalakendra
nupurnritya99@gmail.com
www.nupurcreations.co.in

Log in for purchase Items ONLINE:

मासिक **उत्तरांचल दीप** पत्रिका
वर्ष:7, अंक 8, दिसंबर 2024

संस्थापक संपादक
स्व.वेदप्रकाश गुप्ता
प्रधान संपादक
साकेत अग्रवाल
संपादक
श्रीमती आदेश अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी संपादक
केके चौहान
मुख्य उप संपादक
उदयभान सिंह
मार्केटिंग हेड
तारु तिवारी
प्रबंधक
दीपक तिवारी
वरिष्ठ संवाददाता
रवि दुर्गापाल

उत्तरांचल दीप ब्यूरो
दिल्ली : शालिनी चौहान
लखनऊ : पारस अमरोही
रुद्रप्रयाग : हिमांशु पुरोहित
नैनीताल : अफजल फौजी
अल्मोड़ा : कमल कपूर
पिथौरागढ़ : ललित जोशी
बागेश्वर : नरेंद्र बिष्ट
चंपावत : मनोज राय
बरेली : अनुज सक्सेना
मुरादाबाद : आशेंद्र कुमार अग्रवाल
डोईवाला : चंद्रमोहन कोठियाल
किच्छा : राजकुमार राज
रामनगर : एचसी भट्ट
थत्यूड़ : मुकेश रावत
रुद्रपुर : मुकेश गुप्ता
बाजपुर : इंद्रजीत सिंह
ग्राफिक्स डिजाइन: देवेंद्र सिंह बिष्ट
सभी पद अवैतनिक एवं परिवर्तनीय

मुख्यालय
हल्द्वानी: चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने
नैनीताल रोड, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक श्रीमती आदेश अग्रवाल द्वारा उत्तरांचल दीप, चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने नैनीताल रोड हल्द्वानी से मुद्रित व प्रकाशित।
आरएनआई नंबर: UTTHIN/2018/77440
पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीताल-356-2021-2023

उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित लेख, पत्र व अन्य कालम में लेखकों के विचार होते हैं, उनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होंगे।

www.uttaranchaldeep.com
uttranchaldeepatrika@gmail.com
+91 8881788066 @uttranchaldeep

अंदर

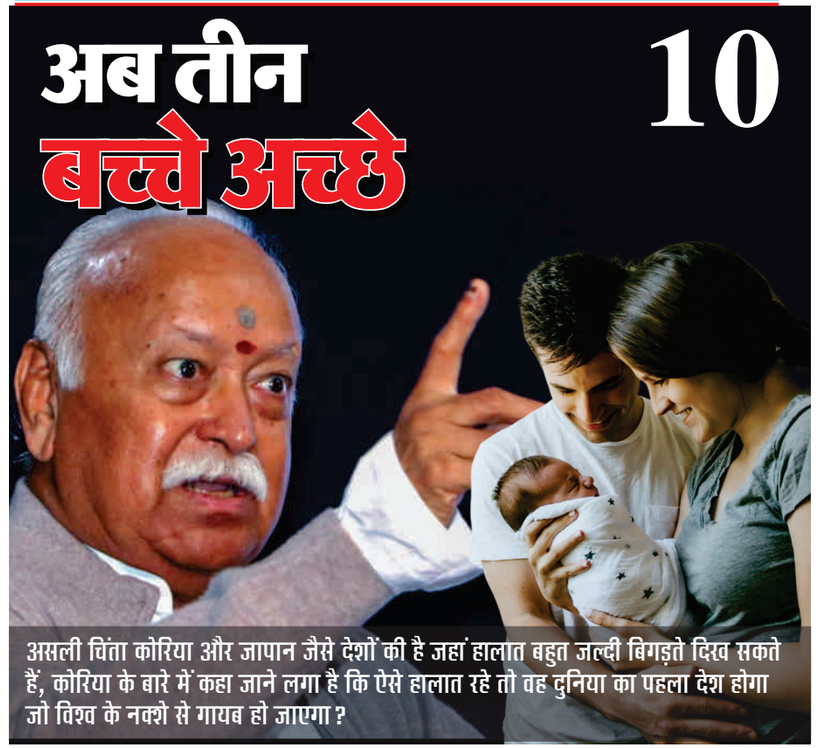

अब तीन बच्चे अच्छे — 10

असली चिंता कोरिया और जापान जैसे देशों की है जहां हालात बहुत जल्दी बिगड़ते दिख सकते हैं, कोरिया के बारे में कहा जाने लगा है कि ऐसे हालात रहे तो वह दुनिया का पहला देश होगा जो विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा?

12
प्रदूषण
उत्तराखंड की आबोहवा बिगड़ी
एक दौर था जब क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को भवाली के अस्पताल में भर्ती कराया जाता था...

16
उत्तर प्रदेश
वर्चस्व के झगड़े में संभल सुलगा
वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन का दावा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद पर 1991 का ...

14
राज्य
उत्तराखंड में मिशन धर्मांतरण
ईसाई मिशनरी छोटे बच्चों को निशुल्क पढ़ाने के नाम पर शिक्षण संस्थान चला रही हैं, जिनमें छोटे बच्चों को ...

शख्सियत

18
कौन है हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन
हरि शंकर जैन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्होंने 1978-79 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ...

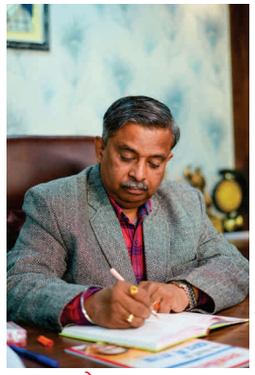

साकेत अग्रवाल

मुस्लिम वोटों के लिए दौड़

सर्दियों के इस मौसम में संसद का शीतकालीन सत्र गर्म रहा, विपक्षी दल के सांसद, राहुल गांधी के अडाणी मुद्दे को छोड़कर अपने-अपने फायदे के मुद्दे संसद में उठाना चाहते है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा का मसला संसद में उठाना चाहती है तो सत्ता पक्ष वक्फ वोर्ड संसोधन विधेयक को पास कराने की जुगत में है, लेकिन संसद में नेता प्रतिपक्ष की सुई अडाणी पर ही अटकी हुई है। जबकि टीएमसी और समाजवादी पार्टी नेता अडाणी मुद्दे को जनता से जुड़ा मुद्दा मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन का कहना है कि हम बांग्लादेश, संभल हिंसा, अजमेर दरगाह, और मणिपुर जैसे बहुत सारे मुद्दे, संसद में उठाना चाहते हैं। लेकिन सरकार हमें इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करने दे रही है। जैसे ही हम अडाणी का नाम लेते हैं, वे कार्यवाही स्थगित कर देते हैं। सांसदों का काम संसद में जनहित के मुद्दे उठाना है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि संभल की शाही जामा मस्जिद, अजमेर की दरगाह, जैसे मुद्दे मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से जुड़े हैं। विपक्ष के एक भी कथित धर्मनिरपेक्ष सांसद के एजेंडे में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज की 100 एकड़ भूमि को वक्फ संपत्ति बताने वाले सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं है। विपक्ष के एजेंडे में वक्फ बोर्ड हो भी नहीं सकता। क्योंकि कांग्रेस ने ही वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी हैं। उदय प्रताप कॉलेज की 100 एकड़ भूमि पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया तो कॉलेज परिसर में बनी मस्जिद जिसमें 20-25 छात्र नमाज पढ़ते थे वहां 500 के करीब बाहरी मुस्लिम नमाज पढ़ने पहुंच गए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि वक्फ बोर्ड उदय प्रताप कॉलेज की 100 एकड़ भूमि बिना किसी प्रमाण के अपनी बता दे तो ठीक, लेकिन मस्जिद और दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर होने के प्रमाण सहित कोर्ट से सर्वे की मांग करने वाला हिंदू पक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की नजर ने सांप्रदायिक हो जाता है। विपक्षी दलों का यही दौरहा चरित्र उनके अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है, जिसे कुछ राजनीतिक दल समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि हाल ही में उदय प्रताप कॉलेज की भूमि से वक्फ बोर्ड ने अपना दावा छोड़ दिया है और कॉलेज को दिया गया नोटिस भी वापस ले लिया है।

सर्दियों के इस मौसम में संभल की सिविल कोर्ट ने शाही जमा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। जिसके बाद 19 और 24 नवंबर को सर्वे टीम मस्जिद गई थी। 24 नवंबर को जिस समय टीम संभल की शाही जामा मस्जिद में थी ठीक उसी समय मुस्लिम पक्ष ने पुलिस पर पथराव कर दिया। निजी संपत्ति को आग के हवाले किया, फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोग संभल विधायक के समर्थक बताए गए। पुलिस की फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं। इस सबके बावजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए बेचैन कही। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि स्थल का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निपट गया। इसके बाद मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी का मुद्दा उठा। फिलहाल ये मसले शांत थे, लेकिन संभल के हरिहर मंदिर का मुद्दा उठ गया। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद सपा और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के लिए दौड़ रही है। सर्वे को 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया जा रहा है। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क भ्रम फैला रहे है कि कोर्ट ने संभल की सिविल कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सुने बिना ही सर्वे का आदेश कैसे दे दिया? जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकील और संभल की सिविल कोर्ट में सर्वे की मांग की याचिका दायर करने वाले विष्णु शंकर जैन का कहना है कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही सर्वे का आदेश दिया है। उनका कहना है कि मुस्लिम पक्ष तो इसमें पार्टी ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी का सर्वे कराया गया वो दस्तावेजों में एएसआई के संरक्षण में है। इसलिए मुस्लिम पक्ष का उस पर कोई अधिकार नहीं है। खैर संभल का यह कोई अकेला मामला नहीं है जहां धार्मिक स्थल का चरित्र जानने के लिए सर्वे कराया गया है।

देश की विभिन्न अदालतों में ऐसे करीब एक दर्जन से अधिक केस लंबित हैं जो धार्मिक स्थलों के चरित्र को विवादित बनाए हुए हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि संभल की शाही जामा मस्जिद, अजमेर की दरगाह, कांशी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार दिल्ली, कमाल मौला मस्जिद, भोजशाला परिसर, मध्य प्रदेश, अत्ताला मस्जिद, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश और शम्सी शाही मस्जिद बदायूं उत्तर प्रदेश उनके प्राचीन धर्म स्थल है और उन्हें मुगल शासकों ने मंदिर से मस्जिद में नहीं बदला है तो फिर सर्वे से परेशान क्यों हैं? मुसलमानों को क्या खुद के प्राचीन धर्म स्थलों के चरित्र पर यकीन नहीं है? क्या उन्हें पता है कि उनके धर्म स्थलों के नीचे मंदिर दफन है, इसलिए वो सर्वे तक का विरोध कर रहे हैं? आम मुसलमान को भले ही इससे कोई लेना देना न हो, लेकिन कट्टपंथी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस जैसे सियासी दलों को चिंता है। इन्हें चिंता मस्जिद या दरगाह की नहीं बल्कि वोट बैंक की है, जिसके दम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसलिए संभल का मुद्दा संसद में उठाया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करने वाले वक्फ बोर्ड के खिलाफ सपा, कांग्रेस या बाकी कथित धर्मनिरपेक्ष दलों की आवाज को लकवा मार जाता है। पर संभल के उपद्रवियों से मिलने के लिए सपा नेता जेल तक पहुंच जाते हैं।

निर्दलीय ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल!

उपचुनाव का एक दिलचस्प पहलू ये रहा कि चुनाव जीतने वाली भाजपा उम्मीदवार आशा नौटियाल और चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत से ज्यादा चर्चा निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान की हो रही है, जिन्होंने 9,300 वोट हासिल किए हैं।

केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत और निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान मीडिया में हाथ आजमा चुके हैं, 2017 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने मनोज रावत प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं।

उत्तरांचल दीप डेस्क

उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया और भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को 5,622 वोटों से हरा दिया। भाजपा की आशा नौटियाल को 23,814 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के मनोज रावत को 18,191 वोट पड़े। इस चुनाव में निर्दलीय त्रिभुवन चौहान ने दोनों दलों को परेशान करते हुए अपनी ताकत का अहसास भी कराया। चौहान 9,311 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी 5,622 वोटों से हारे। इस उपचुनाव का दिलचस्प पहलू ये है कि दो प्रत्याशियों को तो नोटा से भी कम वोट मिले। नोटा का बटन दबाने वालों की संख्या 834 रही। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने 9,311 मत हासिल कर सबको चौंका दिया। यदि वो भाजपा के मददगार बने तो कांग्रेस के लिए नसीहत दे गए। क्योंकि उपचुनाव से पहले केदारघाटी की जनता भाजपा एवं सरकार से नाराज थी। इसकी वजह थी केदारनाथ यात्रा का डायवर्जन करना। स्थानीय युवाओं को अतिक्रमण के नाम पर बेरोजगार करना। कांग्रेस प्रत्याशी केदारघाटी में इन मुख्य मुद्दों को जोर शोर से रखा, लेकिन वे इसे वोट में तब्दील नहीं कर पाए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने भी जनता के बीच जाकर इन्हीं मुद्दों को उठाया। जिसका उन्हें फायदा हुआ और केदारघाटी के भाजपा से नाराज वोट को समेटने में सफल रहे। हालांकि कांग्रेस समझ रही थी कि त्रिभुवन चौहान भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। इससे ये तो साबित हो गया कि यदि जनता के मुद्दों पर जनता के बीच जाकर संघर्ष किया जाए तो बिना किसी धनबल और दल के भी अच्छा चुनाव लड़ा जा सकता है। चुनाव परिणाम के बाद त्रिभुवन चौहान ने साफ कर दिया कि वो जनता की यह लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित करने के बाद आशा नौटियाल ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह जीत भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है। सनातन की जीत है और विकास की जीत है। जनता ने भाजपा के विकास के मॉडल को सराहा और उसे अपना अमूल्य समर्थन दिया। उन्होंने स्वीकारा कि इस वर्ष चारधाम यात्रा संचालन में कुछ कमियां रह गई थी। किंतु अगली चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी कमियों को दूर कर लिया जाएगा।

भाजपा की प्रतिष्ठा दाव पर थी

कांग्रेस सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का नैरेटिव सेट करती रही और खेल निर्दलीय प्रत्याशी ने कर दिया। बदलते दौर की चुनावी राजनीति में मतदाता अब नकारात्मक प्रचार के बजाय काम करने वाली सरकार को दोबारा जनादेश देने से नहीं हिचक रहा है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में थे। ये महज एक संयोग ही था कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत और निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान पत्रकारिता में हाथ आजमा चुके हैं। 2017 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे मनोज रावत प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। उनकी कई खोजी रिपोर्ट्स प्रमुख मैगजींस में छप चुकी हैं। त्रिभुवन चौहान का यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से वो जनता के बीच रिपोर्टिंग करते रहे है। दोनों उम्मीदवारों को राजनीति में आने से पहले अपनी पत्रकारिता वाली बैकग्राउंड का फायदा भी मिला। इस उपचुनाव का एक दिलचस्प पहलू ये रहा कि चुनाव जीतने वाली भाजपा उम्मीदवार आशा नौटियाल और चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत से ज्यादा चर्चा निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान की हो रही है, जिन्होंने 9,300 वोट हासिल किए। चुनावी राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि निर्दलीय प्रत्याशी उपचुनाव में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने वाले साबित हुए। हालांकि केदारनाथ उपचुनाव भाजपा के लिए नाक की लड़ाई थी। क्योंकि यह यूपी में अयोध्या और उत्तराखंड में बदरीनाथ के बाद महत्वपूर्ण धार्मिक-राजनीतिक क्षेत्र है। इसलिए भी भाजपा की प्रतिष्ठा दाव पर लगी थी। क्योंकि बदरीनाथ सीट हारने के बाद उसके सामने केदारनाथ जीतना महत्वपूर्ण हो गया था। भाजपा को लगा कि बदरीनाथ सीट हारने का मुख्य कारण उनका वोटर मतदान करने घर से नहीं निकला। इसलिए केदारनाथ में यह गलती न हो, इसके लिए भाजपा ने संगठन के साथ ही मंत्रियों एवं संगठन के बड़े पदाधिकारियों की फौज को मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए गांव-गांव में प्रवास कराया। जबकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन केदारनाथ की जीत उसे 2027 के आम चुनाव में संजीवनी जरूर देती इसलिए दोनों दलों में केदारनाथ जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी के वोटों में सैंध लगाने से भाजपा की जीत हो गई।

सुर्खियां

नए साल में होंगे
निकाय चुनाव

उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों में भी चुनाव को लेकर मंथन होने लगा है। उम्मीद है कि मकर संक्रांति के बाद निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। राजधानी देहरादून में बड़े-बड़े नेताओं के घरों पर और पार्टी मुख्यालयों में टिकट के दावेदारों ने परेड शुरू कर दी है। दावेदार शक्ति प्रदर्शन भी करने की तैयारी में है। सरकार और भाजपा में स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। निकाय व पंचायतों आरक्षण व्यवस्था को लेकर रणनीति बन गई है। राज्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में भी हलचल तेज है। राज्य निर्वाचन आयोग जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की तैयारी में है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि निकाय और पंचायत चुनाव जल्द ही करा लिए जाएंगे। स्थानीय निकाय में कौन-कौन सी सीटें आरक्षित होंगी? आरक्षण का आधार क्या होगा? इस संबंध में जल्द ही घोषणा हो सकती है, उसके बाद दो सप्तह का समय आपत्तियों के लिए रहेगा। जिसके बाद चुनावों की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि दिसंबर में स्थानीय चुनावों को लेकर मंथन का दौर चलेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने निगम चुनाव के प्रत्याशी चयन के लिए पर्यवेक्षकों को भेजने की तैयारी पूरी कर ली है, जबकि पालिका परिषद में चुनाव प्रभारी ही तय कर लिए हैं। बहरहाल राज्य में अगले दो माह एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियों के रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे राज्य में विकास संबंधी समीक्षाएं करने के लिए विभिन्न शहरों के अपने दौरे भी शुरू कर दिए हैं। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी नगर निगम पहुंच कर पेयजल और स्ट्रीट लाइट को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। जिसके बाद दोनों महकमें तेजी से काम में जुट गए हैं। हल्द्वानी शहर में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम तेजी से होने लगा है।

उत्तराखंड में योग
पॉलिसी लागू होगी

उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां योग पॉलिसी लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार देश की 'प्रथम योग नीति' लागू करने की दिशा में काम कर रही है। यह आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर साथ लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड में हुई 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो-2024 में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को आयुर्वेद और औषधीय संपदा की प्रज्ञाभूमि बताया। धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में आयुष आधारित 300 'आयुष्मान आरोग्य केंद्रों' का संचालन हो रहा है जबकि ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयुष परामर्श दिया जा रहा है। प्रत्येक जिले में 50 बिस्तरों वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना की जा रही है जबकि हर जिले के एक गांव को मॉडल आयुष गांव के रूप में स्थापित कर आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आयुष निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधीय पौधों के उत्पादन को गति देने के लिए 'आयुष नीति' लागू कर चुकी है। इसके साथ ही राज्य सरकार आने वाले वर्षों में आयुष 'टेली-कंसल्टेशन' शुरू करने के अलावा 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय से अनुरोध किया है जो आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने विशेषज्ञों से जड़ी-बूटियों के हिंदी नामों के साथ ही अंग्रेजी नामों को भी प्रचारित करने का अनुरोध किया जिससे स्थानीय जड़ी बूटियों की वैश्विक बाजार तक पहुंच आसान हो सके। इस संबंध में उन्होंने पहाड़ में पाए जाने वाले 'किलमोड़े' का उदाहरण दिया जिससे दवाएं बनती हैं। इसके अंग्रेजी नाम 'बेरीबेरीज' को पूरा विश्व जानता है लेकिन अधिकतर स्थानीय लोग इसे नहीं जानते।

धूम मचा रही धरती म्यर कुमाऊं की

अपने खूबसूरत प्राकृतिक नजारों से सैलानियों को लुभाते पहाड़ों की पीड़ा भी पहाड़ जैसी है। नए जमाने की सुविधाओं से दूर और निरंतर प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलते पहाड़ों में अब लोगों को अपनी जड़ों से उखड़ने के लिए विवश कर दिया है। पलायन का पहाड़ से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। पुराने समय से ही यहां के लोग रोजगार की तलाश में मैदानी शहरों की ओर रूख करते रहे हैं, लेकिन उस समय अपने गांव व माटी से उनका रिश्ता जुड़ा रहता था। नौकरी पूरी करने के बाद वे अपने घर लौट आते थे। पिछले कुछ दशकों से शिक्षा के प्रचार-प्रसार और संचार के साधनों की पहुंच ने नई पीढ़ी को आधुनिक जीवन शैली की ओर आकर्षित किया है जिससे पहाड़ के आबाद गांव वीरान हो गए। पहाड़ के अधिकतर युवा जिन शहरों में नौकरी करते हैं, वहीं के होकर रह जाते हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार के अभाव में पहाड़ से पलायन लगातार बढ़ता गया। भौतिकवाद और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं ने पलायन की गति को और अधिक तेज किया है। पहाड़ में करीब 90 फीसदी युवा इंटर पास हैं, इससे आगे की पढ़ाई व व्यावसायिक शिक्षा के लिए उनके पास संसाधनों का अभाव है। कमजोर आर्थिक कारणों से कुछ युवा सेना में भर्ती हो जाते हैं और बाकी रोजगार की खातिर निराशा की हालत में शहरों की ओर निकल पड़ते हैं। पहाड़ और अपने गांव में रहकर बकरी चराना या खेतों में हल लगाना इन्हें रास नहीं आता। इन युवाओं को होटलों, दुकानों व मॉल में छोटीमोटी नौकरी करते हुए देखा जा सकता है।

स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फोन और ब्रांडेड कपड़ों के इस युग में पहाड़ का युवा भी कहीं खो गया है। एक बार गांव से निकलने के बाद दोबारा लौटने का उनका मन ही नहीं करता। सरकारों की उदासीनता से कहीं न कहीं उनको लगता है कि पहाड़ में रहकर भविष्य के सपने नहीं बुने जा सकते हैं। पहाड़ की इन पीड़ा और समस्याओं पर बनी फिल्म 'धरती म्यर कुमाऊं की' उत्तराखंड के सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म के डायरेक्टर ने हल्द्वानी में मीडिया से कहा कि उनकी ये फिल्म पहाड़ की समस्याओं पर फोकस करती है। फिल्म रोजगार व स्वास्थ्य, शिक्षा खासकर महिलाओं को प्रसव के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की व्यवस्था ना होने के कारण लाने लेजाने की समस्या को उजागर किया गया है। इसलिए दर्शक भी इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। फिल्म की कहानी शिक्षाप्रद है। पूरी फिल्म कुमाऊंनी भाषा में बनाई गई है। देवभूमि फिल्मस प्रोडक्शन के बैनर तले इसे बनाया गया है। कुमाऊंनी फिल्म 'धरती म्यर कुमाऊं की' की पटकथा अच्छी है। रोजी-रोटी गीत में 'पहाड़ में पलायन का सवाल...' विषयवस्तु है। यह उन सवालों में से एक है जो पहाड़ के सामाजिक जनजीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। पलायन पहाड़ के निवासियों के लिए एक निजी भावनात्मक और मानवीय सवाल है ही, साथ ही रिवर्स पलायन और प्रवासियों व 'बाहरी' लोगोंका आगमन यहां की डेमाग्राफी, सामाजिकता, राजनीति और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। ये उन चंद सवालों में से एक है जिन पर सबसे अधिक चर्चा, बहस, बातचीत, विमर्श, बौद्धिक, सांस्कृतिक, सक्रियता, अक्सर अलग-अलग मंचों पर होती दिखाई देती हैं। अगर पहाड़ आधारित यूट्यूब चैनल या वेब पोर्टल ही देख लें तो पलायन के सवाल से संबंधित काफी सामग्री मिल जाएगी। मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों में भी पहाड़ के कई गांव पूरी तरह खाली होने की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। पलायन आयोग की रिपोर्ट चौकाने वाली है। इसलिए सरकारों से लेकर असल सरोकार रखने वाले राजनीतिक संगठनों तक सरकारी महकमों से लेकर धार्मिक संगठनों तक, पलायन की चर्चा होती है। पलायन ऐसा मुद्दा है जिससे पहाड़ का कोई भी सार्वजनिक मंच अछूता नहीं है। पलायन पर गंभीर शोध-पत्र भी मिल जाएंगे। जिनमें सरकारों और सिस्टम को दोष देने के साथ स्थानीय संकीर्णता की सीमा तक पहुंचे असंतुलित आग्रह और पहाड़ में आने वाले 'बाहरी' लोगों के प्रति पर्याप्त कटुता दिखाई देगी। स्वभाविक ही है कि साहित्य की दुनिया में भी पलायन का विमर्श उचित जगह घेरता है।

मोदी का
स्वास्थ्य मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने 26 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच एक करोड़ से अधिक नागरिकों की प्रकृत्ति का निर्धारण आयुर्वेद पद्धति के सिद्धांतों के आधार पर कराने का लक्ष्य रखा है। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ के आधार पर सभी मनुष्यों की अलग अलग प्रकृति होती है। यदि एक बार व्यक्ति की प्रकृति तय हो जाए तो यह पता चल जाता है कि उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस मौसम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वह स्वस्थ रह सके? चिकित्सक को भी उसकी पकृत्ति के अनुसार उसकी चिकित्सा में सुविधा रहेगी। आज के दौर में ज्यादातर बीमारियां जीवन शैली से संबंधित हैं। अधिकांश लोगों को यही पता नहीं होता है कि उनका खानपान, व्यवहार अथवा जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। प्रकृत्ति निर्धारण के बाद व्यक्ति को समय समय पर आयुष विभाग द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से परामर्श दिया जाएगा कि उसके लिए क्या भोजन करना उचित रहेगा। उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, यदि लोग इसका पालन करेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। इससे स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च बचेगा। नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो देश निश्चित ही प्रगति करेगा। उत्तराखंड में भारतीय चिकित्सा पारिषद को इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। सभी जिला आयुर्वेद अधिकारी जिले के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। हर जिले में निजी चिकित्सकों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अनुभव और कार्यक्षमता के आधार पर एक-एक जिला समन्वयक भी बनाया गया है। नैनीताल जिले के लिए यह दायित्व पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. आशुतोष पंत को दिया गया है। नैनीताल जिले में 293 पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जिनके माध्यम से अधिक से अधिक नागरिकों की प्रकृत्ति का परीक्षण किया जाएगा।

सोनिया व सोरोस का रिश्ता क्या?

सोनिया गांधी पर जॉर्ज सोरोस से संबंध होने का आरोप है, यह आरोप सोनिया गांधी के राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा दाग है, यदि जांच में ये साबित होता है कि सोनिया गांधी के संबंध देश विरोधी ताकत यानी जॉर्ज सोरोस से हैं तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है।

सो

केके चौहान

निया गांधी, जॉज सोरोस और डीप स्टेट के आपस में क्या संबंध हैं? क्या सच में सोनिया गांधी और जॉज सोरोस के बीच कोई रिश्ता है? क्योंकि सोनिया गांधी पर भाजपा ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। भाजपा ने आरोप लगाने से पहले निश्चित रूप से कुछ तो प्रमाण इकट्ठा किए होंगे। क्योंकि आरोप लगाने वाले भाजपा के शीर्ष नेता राज्यसभा सांसद व पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। डीप स्टेट का मोहरा जॉज सोरोस है और जॉज सोरोस के ताल्लुक सोनिया से हैं। ये डीप स्टेट क्या है जिसे लेकर अमेरिका सहित पूरी दुनिया में चर्चा पहले से ही है? डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इस बहस ने तेजी पकड़ी है। डीप स्टेट की थ्योरी में विश्वास रखने वाले कहते हैं कि ये चुने हुए प्रतिनिधियों के समानांतर चलने वाला एक सिस्टम है। जिसमें मल्टीनेशनल हाउस, मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी शामिल होते हैं। ये लोग सरकार से अलग अपनी खुद की नीतियां लागू करते हैं और विदेश नीति के साथ दूसरी नीतियों को प्रभावित करते हैं। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका में डीप स्टेट जैसा कुछ नहीं है। मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के लोग अमेरिका के संविधान और कानून व्यवस्था के मुताबिक ही काम करते हैं। क्योंकि कई बार चुनी हुई सरकारों को इन प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का काम पसंद नहीं आता। इसलिए वो आरोप लगाती है कि डीप स्टेट उन्हें काम नहीं करने दे रहा है। ऐसे ही आरोप ट्रंप भी लगाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि उदारवादी और वामपंथी विचारधारा के लोग प्रशासनिक पदों पर काबिज हैं, जो उनकी नीतियों को ढंग से लागू नहीं होने देते। यही आरोप उनका समर्थन करने वाला दक्षिणपंथी तबका भी लगाता है। क्रैंब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक डीप स्टेट ऐसे समूह को कहा जाता है जो गुप्त तरीके से विशेष हितों की रक्षा के लिए और बिना किसी चुनाव के देश पर राज करने के लिए काम करता है।

जॉज सोरोस के हाथ में रिमोट

जहां तक इस शब्द के आने का सवाल है तो डीप स्टेट संभवतः तुर्की डेरिन डिलेट (गहरा, गहन राज्य) का अनुवाद है। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल आता होगा कि क्या वाकई में किसी देश में डीप स्टेट काम करता है और इतना असर डाल सकता है कि वहां की सत्ता हिल जाए? जैसे बंग्लादेश में हुआ। डीप स्टेट क्या भारत में भी सक्रिय है? इस सवाल का जवाब किसान आंदोलन, सीएए जैसे आंदोलनों से समझा जा सकता है। इन आंदोलनों के विदेशों से ऑपरेट होने के आरोप यूं ही नहीं लगते रहे हैं। ऐसे ही आंदोलनों के जरिये डीप स्टेट भारत में उथल-पुथल और अशांति पैदा करना चाहता है। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत कभी किसी देश में देखने को नहीं मिले हैं। डीप स्टेट अमेरिकी कारोबारी जॉज सोरोस के जरिये भारत को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से दुनिया की तीसरी अर्थ व्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में सबसे आगे हैं, लिहाजा डीप स्टेट को भारत की यह ताकत और तरक्की खटक रही है। डीप स्टेट के इशारे पर ही जॉज सोरोस खुलेआम भारत में नरेंद्र मोदी विरोधी एजेंडा चलाता हैं। जो बातें जॉज सोरोस चाहता है वही देश की सबसे बूढ़ी पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं। एक तरह से राहुल गांधी का रिमोट जॉज सोरोस के हाथ में बताया जाता है।

सोनिया व सोरोस के संबंध?

अमेरिका का बड़ा कारोबारी जॉज सोरोस डीप स्टेट का मोहरा है। सोरोस का अमेरिका के 30 से अधिक मीडिया आउटलेट्स में डायरेक्ट निवेश है, इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, एपी, सीएनएन और एबीसी शामिल हैं। शेयर बाजार में भी जॉर्ज सोरोस का बड़ा नाम है। जॉज सोरोस सटोरिया, निवेशक और कारोबारी हैं, लेकिन खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता बताने पर ज्यादा जोर देता है। उन पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाजिक ताने-बाने को प्रभावित करने के लिए एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहा है। कई देशों में भारी-भरकम फंडिंग देकर चुनाव प्रभावित करने का भी सोरोस पर आरोप है। यूरोप और अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर मोटा जुर्माना लगाया गया और बैन कर दिया गया। 94 साल के सोरोस पर ये आरोप

डीप स्टेट के इशारे पर ही जॉज सोरोस खुलेआम भारत में नरेंद्र मोदी विरोधी एजेंडा चलाता हैं, जो बातें जॉज सोरोस चाहता है वही देश की सबसे बूढ़ी पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का रिमोट जॉज सोरोस के हाथ में है।

आम है कि वे दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाजिक ताने-बाने को प्रभावित करने के लिए एजेंडा चलाते है। संभवतः यह एजेंडा सोरोस का नहीं बल्कि डीप स्टेट का ही होता है। 2022 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय राजनीति पर डीप स्टेट का प्रभाव है। भारत में बोलने की इजाजत देने वाली संस्थाओं संसद, चुनाव आयोग और लोकतंत्र के मूल स्ट्रक्टर पर एक संगठन का कब्जा हो रहा है। डीप स्टेट इन स्थानों में घुस रहा है। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के पास इसे लेकर कोई पुख्ता इनपुट हैं। अब भाजपा ने कांग्रेस लीडर और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी पर जॉर्ज सोरोस से संबंध होने का आरोप लगाया है। यह आरोप सोनिया गांधी के राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा दाग साबित हो सकता है। क्योंकि जांच में यदि ये साबित होता है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी के संबंध देश विरोधी ताकत यानी जॉर्ज सोरोस से हैं तो दोनों की मुश्किल बढ़ सकती है।

सोनिया पर भाजपा का अटैक

9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन था। उसी दिन भाजपा ने संसद में सोनिया गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के संगठन से करीबी रिश्ते हैं। जॉर्ज सोरोस कांग्रेस के साथ मिलकर खुलेआम भारत विरोधी एजेंडा चलाता है, सोरोस कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। वह मोदी सरकार को हटाने और भारत में अस्थिरता पैदा करने का काम करता है। भाजपा का आरोप है कि सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठन फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन एशिया पैसिफिक की सह-अध्यक्ष हैं। लिहाजा कांग्रेस के सोरोस के फाउंडेशन के साथ रिश्तों की जांच के लिए जेपीसी का गठन और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। भाजपा नेताओं ने ये मांग उठाई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता उत्तेजित हो गए। लेकिन किसी ने सोनिया गांधी पर लगे आरोपों का खंडन नहीं किया। न ही सोनिया गांधी ने जॉर्ज सोरोस से संबंध होने पर कोई सफाई दी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जॉर्ज सोरोस के नाम से

जॉर्ज सोरोस राहुल को अग्रिम सूचना देते हैं, जिसके आधार पर वो संसद के अंदर और बाहर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, इससे दो बातें साफ है, वो ये कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का सोरोस से और उसके फाउंडेशन व उसके सिस्टम से कोई तो संबंध है।

कांग्रेस के नेता इतने परेशान क्यों हैं? जॉर्ज सोरोस का संगठन दुनिया के सौ से ज्यादा देशों में काम करता है। फोरम फॉर डेमोक्रेडिट लीडर्स फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस से फंडिग मिलती है। इस संगठन के चार सह-अध्यक्ष हैं जिनमें राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी भी सह-अध्यक्ष हैं। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन का एजेंडा भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक रहा है। भाजपा प्रवक्ता सुधाशुं त्रिवेदी का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस के संगठन से जुड़े लोग राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल थे। अब कांग्रेस को साफ करना पड़ेगा कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी भारत में जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स की स्थापना तीस साल पहले दिसंबर 1994 में की गई थी। इसका गठन साउथ कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति किम डेई जंग की पहल पर हुआ, जो अब भी इसके चार सह-अध्यक्षों में से एक हैं। सोनिया गांधी 1994 में राजनीति में नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त वो राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष थी, इसलिए सोनिया गांधी को फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स का सह-अध्यक्ष बनाया गया था। जॉर्ज सोरोस की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को भी फंड दिए गए हैं। इसलिए मोदी सरकार ने विदेशी चंदे से जुड़े एफसीआरए कानून में संशोधन किया तो फोर्ड फाउंडेशन, ग्रीन पीस, एमनेस्टी जैसे सैंकड़ों संगठन सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए। वस्तुतः यह भद्रलोक के रूप में स्लीपर सेल ही है जो जॉर्ज सोरोस के एजेंट के रूप में सक्रिय हैं। किसान आंदोलन, नागरिकता संशोधन कानून और अग्निवीर योजना के विरुद्ध जिस तरह से देश में एक प्रायोजित माहौल बनाया गया उसे देखकर श्रीलंकाई तस्वीरों से मिलान किया जाए तो सब कुछ आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे एक पूरा सिंडिकेट भारत के विरुद्ध खड़ा है। जॉर्ज सोरोस पीएम नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं, इसलिए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के संगठन के साथ सोनिया गांधी के रिश्तों पर कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता देशद्रोह जैसा है।

राहुल पर भाजपा का हमला

राहुल गांधी को लेकर भाजपा का आरोप है कि वो जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत विरोधी साजिश करते हैं। जॉर्ज सोरोस राहुल को अग्रिम सूचना देते हैं। जिसके आधार पर वो संसद के अंदर और बाहर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। इससे दो बातें साफ है, वो ये कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का सोरोस से और उसके फाउंडेशन व उसके सिस्टम से पूरा संबंध है। जॉर्ज सोरोस के इशारे पर ही राहुल गांधी भी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर इल्जाम लगाते हैं और मोदी सरकार व देश की अर्थ व्यवस्था को कमजोर करने में लगे रहते हैं। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी, गौतम अडानी के पीछे क्यों पड़े हैं? राहुल का मानना है कि सोरोस और उसके संगठनों ने ही गौतम अडानी को एक्सपोज किया है। इस पूरे मामले में जॉर्ज सोरोस का रोल बहुत दिलचस्प है। लंदन के आखबार 'फायनेंशियल टाइम्स' से जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन है। 2020 में 'फाइनेंशियल टाइम्स' ने ही लिखा था कि अगर मोदी को कमजोर करना है तो गौतम अडानी को टारगेट करना होगा। राहुल गांधी बिल्कुल इसी राह पर चल रहे हैं और इसकी कई मिसाल हैं। जी-20 समिट से पहले राहुल ने अडानी का नाम लेकर मोदी पर हमला किया था। उसके बाद चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या अमेरिका में अडानी के खिलाफ जांच की खबर, सोरोस खबर बनाते हैं और राहुल, मोदी के खिलाफ उसका शिद्दत से प्रचार करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि राहुल गांधी जब इंग्लैंड या अमेरिका जाते हैं तो उनकी यात्रा की प्लानिंग जॉर्ज सोरोस के सिस्टम द्वारा ही की जाती है। राहुल ये तो कहते हैं कि अडानी-मोदी एक हैं। वह ये तो कहते हैं कि मोदी-अडानी के लिए काम करते हैं लेकिन राहुल गांधी ने भाजपा के इस सवाल का जवाब कभी नहीं दिया कि अगर अडानी इतने खराब हैं तो कांग्रेस की सरकारों ने अडानी को प्रोजेक्ट्स क्यों दिए? अडानी को लेकर राहुल का ये डबल रोल, सोरोस से उनका कनेक्शन शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं। इसलिए उन्होंने अडानी के मुद्दे पर राहुल से दूरी बना ली है।

अब तीन बच्चे अच्छे

असली चिंता कोरिया और जापान जैसे देशों की है जहां हालात बहुत जल्दी बिगड़ते दिख सकते हैं, कोरिया के बारे में कहा जाने लगा है कि ऐसे हालात रहे तो वह दुनिया का पहला देश होगा जो विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा?

बाबू सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत में हाल ही में कहा कि हर भारतीय परिवार में तीन बच्चे होने चाहिए। उन्होंने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि अगर देश में जन्मदर 2.1 प्रतिशत से कम हुई तो परिवार नष्ट हो जाएगें वे पहले भी कह चुके हैं कि भारत को एक बहुत ही सोची समझी जनसंख्या नीति चाहिए जो हर समुदाय पर समान रूप से लागू हो। अब सवाल उठ रहा है कि मोहन भागवत ने आखिर ऐसा बयान क्या हिंदुओं के लिए दिया है? क्या वाकई दुनिया में इतनी कम जन्मदर चिंता का विषय है? क्योंक हिंदू समाज में ही एक या अधिकतम दो बच्चे पैदा करने पर ज्यादा जोर रहता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश को आज के हिसाब से जनसंख्या नीति की जरूरत है। जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जन्म दर 2.1 प्रतिशत से नीचे चली जाती है, तो वह समाज खत्म हो जाता है। वह समाज तब भी खत्म हो जाता है जब कोई संकट नहीं होता। इस तरह से कई समाज और भाषाएं खत्म हो चुकी हैं। जनसंख्या जन्म दर 2.1 फीसदी से नीचे नहीं जानी चाहिए यदि हम इससे अधिक दर चाहते है तो हमें हर परिवार में दो से अधिक बच्चों की जरूरत है। ऐसे में हर परिवार को तीन बच्चों पर विचार करना चाहिए। 2011 के जनसंख्या के औपचारिक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की जन्मदर 2.18 फीसदी है। जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022 में यह दर करीब 1.63 फीसदी हो गई थी, जो कि पिछले कई सालों से लगातार गिरती हुई बताई जा रही है। यहां यह भी देखने की बात है कि 2021 में भारत की जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से टाल दी गई थी जो अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे में सबसे पहले यह समझने वाली बात है कि दुनिया के कुछ ऐसे देश भी है जहां जन्मदर 1 प्रतिशत से भी कम है। इनमें दक्षिण कोरिया, जापान और चीन प्रमुख हैं। दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन में तो इस समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि वहां भविष्य में हालात चिंताजनक हो सकते हैं। लेकिन असली चिंता कोरिया और जापान जैसे देशों की है जहां हालात बहुत जल्दी बिगड़ते दिख सकते हैं, कोरिया के बारे में कहा जाने लगा है कि ऐसा ही रहा तो वह दुनिया का पहला देश होगा जो गायब हो जाएगा? मोहन भागवत से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी दो से अधिक बच्चे पैदा करने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत के राज्यों के लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है। क्योंकि दक्षिण में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.1 प्रतिशत है। जबकि दक्षिण के राज्यों में यह 1.6 फीसदी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले दंपति को प्रोत्साहन राशि देने पर भी विचार किया है।

2.1 फीसदी से कम जन्मदर देश के लिए चिंता

हैरानी की बात ये है कि अभी दुनिया की इंसानी आबादी अब तक की सबसे ज्यादा है। दुनिया की जनसंख्या 8 अरब के पार हो चुकी है। ऐसे में कम जन्मदर को समस्या मानना हैरान कर सकता है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन भी गिरती जन्मदर से परेशान है, लेकिन असल सवाल आज का नहीं बल्कि आज से कई दशकों के बाद का है। जब हमारे बच्चे युवा होंगे और युवा आबादी बूढ़ी हो जाएगी। तब हालात बिगड़ जाएंगे। भविष्य में देश के युवा तेजी से कम होते जाएंगे और हमारा वर्क फोर्स यानी श्रमशक्ति में बड़ी गिरावट होने लगेगी जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर होगा। ऐसे में हमें 20 से 40 साल के बाद की स्थिति के लिए कारगर जनसंख्या नीति अभी से बनानी होगी। चीन में वर्ल्ड बैंक के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक चीन में जन्मदर 0.68, जापान में 0.63, कोरिया में जन्मदर 0.49 जबकि भारत में जन्मदर 1.63 फीसदी है। लेसेंट सहित दुनिया की कई स्टडी यही बताती है कि जन्मदर अगर 2.1 से कम हो तो यह देश के लिए चिंता की बात हो जाती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी यही चिंता है। ऐसे में देश को एक नई जनसंख्या नीति की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि हमारे देश में जनसंख्या नीति 1998 या 2002 में बनाई गई थी। उसमें साफ कहा गया था कि जन्मदर 2.1 प्रतिशत से नीचे नहीं होनी चाहिए, इसलिए हर दंपति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि हमारे देश में जनसंख्या नीति 1998 या 2002 में बनाई गई थी, उसमें साफ कहा गया था कि जन्मदर 2.1 प्रतिशत से नीचे नहीं होनी चाहिए, इसलिए हर दंपति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए।

2050 में भारत बुजुर्गो का देश होगा?

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस-5) के मुताबिक भारत में जन्मदर 2.2 फीसदी से घटकर 2.0 पर आ गई है। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों के अनुसार, जन्मदर 2.1 फीसदी होनी चाहिए। वो इसलिए ताकि पीढ़ियां बढ़ सके। जब 1990-92 में पहली बार सर्वे हुआ था, तब देश में जन्मदर 3.4 फीसदी थी। यानी उस वक्त एक दंपति औसतन 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, लेकिन उसके बाद से जन्मदर प्रतिशत में लगाातर गिरावट आई है। घटते जन्मदर प्रतिशत का प्रभाव यह होता है कि बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ती है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट-2023' जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2050 तक भारत की आबादी में 20.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बुजुर्गों की होगी। बुजुर्ग यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2010 के बाद से भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसके मुकाबले 15 साल से कम उम्र के किशोरों की आबादी में हिस्सेदारी घट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक जुलाई 2022 तक देश में बुजुर्गों की आबादी 14.9 करोड़ थी। तब आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत थी, लेकिन 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 34.7 करोड़ होने का अनुमान है। यदि ऐसा हुआ तो 2050 में भारत की आबादी में 20.8 फीसदी बुजुर्ग होंगे। जबकि इस सदी के अंत तक यानी 2100 तक भारत की 36 फीसदी से ज्यादा आबादी बुजुर्ग हो चुकी होगी। इसी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 2022 से 2050 के दरमियान भारत की आबादी 18 प्रतिशत बढ़ जाएगी। जबकि, बुजुर्गों की आबादी 134 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी 279 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 1950 के दशक में भारत में हर दंपति औसतन 6 बच्चें पैदा करता था। 2019 से 21 के बीच हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में पता चला कि भारत में जन्मदर 2 प्रतिशत हो गई है। यानी अब भारतीय दंपति औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रहा है। इससे 2050 तक जन्मदर 1.7 फीसदी पहुंचने का अनुमान है।

आसान नहीं है बच्चों का पालन

आरएसएस प्रमुख मोहन ने भले ही ये संकेत हिंदुओं के संदर्भ में दिया हो, मगर सच यह है कि आज महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रहे आम आदमी के लिए 3-3 बच्चे पैदा करना और उनका पालन-पोषण करना कितना मुश्किल हो सकता है? भारत में बच्चे के पालन-पोषण का बजट जगह, लाइफ स्टाइल और व्यक्तिगत पसंद आदि पर निर्भर करता है। 'द लॉजिक स्टिक' के एक अध्ययन के अनुसार एक बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल तक के पालन-पोषण की अनुमानित लागत 30 लाख रुपये से लेकर 1.2 करोड़ रुपये तक आती है। यह शहरों, महानगरों, कस्बों और गांवों की परिस्थितियों के मुताबिक अलग-अलग हो सकती है। भारत में बच्चों की देखभाल की लागत माता-पिता के लिए वित्तीय चुनौती होती है। डे-केयर सुविधाओं, प्री-स्कूल फीस और स्कूल के बाद की गतिविधियों पर ये खर्च अलग-अलग होते हैं। यानी एक बच्चे की देखभाल की लागत औसतन 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है।

- **पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट-2023' जारी की थी, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2050 तक भारत की आबादी में 20.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बुजुर्गों की होगी, बुजुर्ग यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होगी।**
- **एक बच्चे की देखभाल की लागत औसतन 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है, महानगरों के मुकाबले छोटे शहरों और गांवों में यह लागत कम हो सकती है, इसमें एक बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कपड़े, भोजन और बाकी दूसरी गतिविधियां शामिल हैं।**

महानगरों के मुकाबले छोटे शहरों और गांवों में यह लागत कम हो सकती है। इसमें एक बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कपड़े, भोजन और बाकी दूसरी गतिविधियां शामिल हैं। महंगाई और बदलती हाई-फाई जीवनशैली की वजह से ये खर्च बढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए ही अगर विदेश भेजना पड़े तो यह रकम औसतन 25 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। भारत में अच्छी लाइफस्टाइल की लागत शहर, परिवार के आकार और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर अलग-अलग होती है। यानी 4 लोगों के परिवार के बेहतर रहन-सहन के लिए 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपये महीना खर्च हो सकता है। अगर परिवार में बच्चे हैं तो यह रकम और बढ़ सकती है।

कमर तोड़ती बच्चों की शिक्षा

हर माता-पिता के लिए बच्चे के पालन-पोषण में शिक्षा सबसे बड़ा खर्च है। प्री-स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक, शिक्षा की लागत पिछले कुछ वर्षों में सुरसा की तरह बढ़ी है। बेहतरीन शिक्षा हर भारतीय माता-पिता के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, जिससे वे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च करते हैं। लॉजिक स्टिक के शोध से पता चलता है कि भारत में एक बच्चे की अच्छी शिक्षा पर माता-पिता की कुल कमाई का 40 से 50 प्रतिशत खर्च हो जाता है। शिक्षा के अलावा, स्वास्थ्य देखभाल बच्चा पैदा करने से जुड़ा एक और खर्च है। प्रसव पूर्व देखभाल से लेकर टीकाकरण तक बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्षों के दौरान मेडिकल बजट काफी हो जाता है। अगर कोई अचानक दिक्कत आ गई तो ये खर्चे और कहां तक होगा इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि अप्रत्याशित चिकित्सा लागत को देखते हुए बच्चे और परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज कराना भी आवश्यक हो जाता है। भोजन और पोषण बच्चों के लिए बहुत जरूरी हैं। माता-पिता के लिए इसका मासिक औसत खर्च 2,500 से 3,500 रुपये के बीच हो सकता है। यानी यह रकम सालाना 30,000 से 42,000 रुपये तक हो सकती है। बच्चे के विकास के लिए पोषक तत्वों युक्त भोजन आवश्यक है, जिससे भारत में बच्चे के पालन-पोषण की लागत में भोजन भी जरूरी कंपोनेंट हो जाता है। बच्चों का विकास बहुत तेजी से होता है, इसलिए वे बहुत ही कम समय में अपने कपड़ों से बड़े हो जाते हैं। अध्ययन से पता चला है कि माता-पिता बच्चों के पहनावे पर हर महीने लगभग 2000 से 3000 रुपये औसतन खर्च करने को तैयार रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 24000 से 36000 रुपये सालाना तक कपड़ों पर ही खर्च हो सकता है। फिर भी 2024 में भारत की बढ़ती आबादी लंबी छलांग लगाते हुए चीन को पछाड़ कर दुनिया में नंबर एक हो गई है। हालांकि भारत में बहुसंख्यक हिंदू पिछली जनगणना में 80 प्रतिशत थे। जो अब घटकर 78.9 प्रतिशत हो गए हैं।

उत्तराखंड की आबोहवा बिगड़ी

एक दौर था जब क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को भवाली के अस्पताल में भर्ती कराया जाता था, कहा जाता था कि यहां की दवा और हवा से रोगी जल्दी क्षय रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए लोग स्वास्थ लाभ के लिए पहाड़ों के शुद्ध वातावरण में सैर करते हैं, क्योंकि पहाड़ों की हवा और पानी शुद्ध माने जाते हैं।

डॉ.हरीश चंद्र अंडोला
दून यूनिवर्सिटी

मूमन बड़े शहरों के प्रदूषण से राहत पाने के लिए लोग उत्तराखंड की हरी भरी और शांत वादियों में आना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि पहाड़ों पर हरियाली होने की वजह से प्रदूषण नहीं होता, लेकिन अब यह धारणा दम तोड़ रही है। क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ियों की आबोहवा भी अब शुद्ध नहीं रही है। इसकी एक वजह बढ़ता पर्यटन भी है, हालांकि पर्यटन बढ़ने से जहां एक ओर पहाड़ के लोगों को रोजगार मिल रहा है तो वहीं प्रकृति को नुकसान भी पहुंच रहा है। यानी शुद्ध हवा की गुणवत्ता में कमी आ रही है। पर्वतीय राज्य के वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड गैस कार्बन के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली हो गई है। जो 300 गुना ज्यादा गर्मी देती है। पहाड़ी इलाकों में गाड़ियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जो नाइट्रस ऑक्साइड की प्रति किलोमीटर 60 एमजी तक प्रभावित कर रही है। एक तरह से कहा जाए तो पहाड़ के वातावरण में हो रही ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव से अब पहाड़ भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। लिहाजा पहाड़ों की शुद्ध हवा अब पर्यावरण प्रदूषण के कारण दूषित हो रही है। एक दौर था जब क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को भवाली के अस्पताल में भर्ती कराया जाता था, कहा जाता था कि यहां की दवा और आबोहवा से रोगी जल्दी क्षय रोग मुक्त हो जाता है। इसलिए भी लोग स्वास्थ लाभ के लिए पहाड़ों के शुद्ध वातावरण में सैर करना पसंद करते हैं, क्योंकि पहाड़ों की हवा और पानी शुद्ध माने जाते हैं। लेकिन बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण पहाड़ों की हवा भी अब दूषित हो गई है। क्योंकि वातावरण में जहरीली गैसों की मात्रा निरंतर बढ़ रही है।

चेंज हो रहा पहाड़ का क्लाइमेट

2006 से हिमालयी रीजन में ग्रीन हाउस गैसों और शॉर्ट लिफ्ट गैसों का प्रेक्षण शुरू किया। यह प्रेक्षण हिमालयी इलाकों का पहला प्रेक्षण था। इस प्रेक्षण में पाया गया कि सभी तरह की गैसों में वृद्धि हुई है। कार्बन डाईऑक्साइड गैस साल 2006 में 360 पीपीएम थी। जबकि 2024 में कार्बन डाईऑक्साइड गैस की मात्रा 410 से 420 पीपीएम तक मापी गई थी। यानी 2006 से अभी तक 50 से 60 पीपीएम कार्बन डाईऑक्साइड गैस की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। वायुमंडल में सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस सल्फर हैक्सा फ्लोराइड है। हालांकि इसकी मात्रा उत्तराखंड के वायुमंडल में काफी कम होती है, लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है। इसकी मात्रा पहले 5 पीपीएम थी जो अब 7 से 8 पीपीएम हो चुकी है। जिससे क्लाइमेट चेंज जैसे असर देखने को मिल रहे हैं। पर्यावरण एक्सपर्ट कहते हैं कि हिमालयी इलाकों में कार्बन डाईऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में तेजी से इजाफा हुआ है। जो पहले 40 से 50 पीपीएम होती थी वो अब 100 से 110 पीपीएम तक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण को लेकर इस वर्ष अप्रैल तक के आंकड़े जारी किए हैं। हवा की गुणवत्ता की जांच के लिए बोर्ड के पास सिर्फ देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर में ही मॉनीटरिंग की व्यवस्था है। पर्वतीय जिलों में हवा की गुणवत्ता की जांच की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। बोर्ड के मुताबिक देहरादून के घंटाघर क्षेत्र में पीएम-10 का स्तर जनवरी में 165.25, फरवरी में 182.59, मार्च में 159.28 और अप्रैल में 171.59 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सेहत के लिए हानिकारक है। देहरादून के ही आईएसबीटी क्षेत्र में पीएम-10 की मात्रा जनवरी में सबसे अधिक 243.12 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स के मुताबिक ये सेहत के लिए अति हानिकार की श्रेणी में आती है।

दून घाटी सबसे ज्यादा प्रदूषित

एक्सपर्ट का कहना है कि जंगलों की आग और पहाड़ों में बढ़ता वाहनों का दबाव इसका मुख्य कारण है। अंग्रेजों ने अपने दौर में मसूरी, नैनीताल जैसे पहाड़ी स्थलों और देहरादून जैसी शिवालिक तथा मध्य हिमालय से घिरी घाटी में एक स्वप्निल पर्यावरण को देखते हुए बसेरे बनाए थे। ये स्थान अब अलग-अलग किस्म के प्रदूषणों का शिकार हो चुके हैं। अपने गुलाबी मौसम के लिए विख्यात दून घाटी अब धूल, धुएं और शोर की घाटी बन चुकी है। फिर भी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की मुहिम से जोड़ने के लिए नेतागण जीजान एक किए हुए हैं। करीब दो साल पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,

अपने गुलाबी मौसम के लिए विख्यात दून घाटी अब धूल, धुएं और शोर की घाटी बन चुकी है, यानी यहां हर किस्म का प्रदूषण है, फिर भी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की मुहिम से जोड़ने के लिए नेतागण जीजान एक किए हुए हैं।

एनजीटी, उत्तराखंड सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को औद्योगिक इकाइयों से उठने वाले प्रदूषण के खतरनाक स्तरों को लेकर फटकार लगा चुके हैं। विशेषज्ञ और निगरानी समितियां बनाने की बातें भी वो कर चुका हैं, लेकिन निवेश, मुनाफा और जीडीपी का आकर्षण अब प्रकृति में घुले प्रदूषण के समांतर एक मानव निर्मित प्रदूषण की तरह हो गया है। जंगलों का कटान और पहाड़ी इलाकों में अंधाधुंध निर्माण ने हवा, पानी और मिट्टी के रास्ते उलट पुलट कर रख दिए हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि अप्रत्याशित रूप से भूस्खलन और अतिवृष्टि की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। बाढ़ से तबाही का दायरा फैलता जा रहा है और इनसे जुड़े आर्थिक सामाजिक नुकसान तो जो हैं सो हैं। इस बीच पहाड़ों में जंगल की आग एक नया पर्यावरणीय संकट बनकर उभरा है जो किसी स्मॉग से कम नहीं है। जंगलों की कुछ आग दुर्घटनावश लगती हैं तो कुछ आग जानबूझ कर लगाई जाती हैं। जिससे पहाड़ बर्बाद हो रहा है।

शांत पहाड़ अब अशांत हो रहे

विशेषज्ञ ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। हालांकि इस बारे में विद्वानों और विशेषज्ञों में मतभेद भी हैं। कुछ कहते हैं कि ये कोई असाधारण बात नहीं है और प्रकृति के सैकड़ों हजारों साल के बदलावों में ग्लेशियरों का बनना बिगड़ना स्वाभाविक है, लेकिन पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की एक बिरादरी पुरजोर तौर पर मानती है कि ग्लेशियरों का पिघलना एक सामान्य घटना नहीं है और ये जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े सूचकों में से एक है। इस बहस से अलग एक सच्चाई यह भी है कि पहाड़ों का मौसम अब पहले जैसे नहीं रह गया है। फसल की पैदावार का पैटर्न भी बदला है। गुणात्मक और मात्रात्मक गिरावट दोनों देखने को मिल रही है। पलायन के कारण बड़े पैमाने पर पहाड़ी जमीन बंजर हो रही है। जीवन की इस वीरानगी में एक नया माफिया पनप गया है जो निर्माण से लेकर पलायन तक एक बहुत ही संगठित, लेकिन अदृश्य रूप से सक्रिय है। पारिस्थितिकीय परिवर्तनों ने भी उत्तराखंड को स्तब्ध स्थिति में पहुंचा दिया है। बेशक अभी भी पहाड़ों में लोग स्वच्छ हवा पा लेते हैं, लेकिन ऐसे इलाके सिकुड़ रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर भी निर्माण, वाहनों का आना जाना, प्लास्टिक का कचरा बढ़ने के साथ आबादी का बोझ बढ़ गया है। गर्मियों में जब लोग पहाड़ों की रानी मसूरी या नैनीताल की शांत वादियों की तरफ निकलते हैं तो देहरादून अथवा हल्द्वानी पहुंचते ही उनके रोमांच को झटके लगने लगते हैं। क्योंकि मशहूर पर्यटन स्थलों के रास्तों में वाहनों की भीड़, चिल्लपो (शोर) और वायु प्रदूषण अब एक नई समस्या बन गए हैं। पर्यटनीय अतिवाद का मसूरी या नैनीताल ही पीड़ित नहीं है, जहां कमाई की हड़बड़ी और पर्यटन के आंकड़ों को सुधारने की होड़ में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा

- **जंगलों का कटान और पहाड़ी इलाकों में अंधाधुंध निर्माण ने हवा, पानी और मिट्टी के रास्ते उलट पुलट कर रख दिए हैं, इसका परिणाम ये हो रहा है कि अप्रत्याशित रूप से पहाड़ों पर भूस्खलन और अतिवृष्टि की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं।**
- **विशेषज्ञ ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने को लेकर चिंता जता रहे हैं, हालांकि इस बारे में विद्वानों और विशेषज्ञों में मतभेद है, कुछ कहते हैं कि ये कोई असाधारण नहीं है, प्रकृति के सैकड़ों हजारों साल के बदलावों में ग्लेशियरों का बनना बिगड़ना स्वाभाविक है।**

रहा है, कि सड़कों पर वाहनों की इतनी आमद और बेशुमार प्लास्टिक का इस्तेमाल, पहाड़ की सेहत के लिए अच्छी नहीं है।

डायनमाइट के विस्फोट भी जिम्मेदार

हिमालय नया पहाड़ है, मध्य हिमालय तो वैसे भी कच्चा पहाड़ है, लेकिन उसमें से काटकर बांध बनाए जा रहे हैं। कनेक्टिविटी बढ़ाने के नाम विस्फोट से पहाड़ को काटकर सड़कें बनाई जा रही हैं। डायनमाइट के विस्फोट कर पहाड़ों को उड़ाकर तैयार की गई सड़कों पर बारिश के दिनों में भूस्खलन बढ़ गया है। मिट्टी जगह छोड़ रही है, क्योंकि जंगल कट रहे हैं और सड़कें बन रही हैं। विकास से जुड़ी ये एक विडंबना भी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि यातायात और अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए कमोबेश मनमाने तरीके से निर्माण के रास्ते निकाले जाएं। भौगोलिक और भूगर्भीय आकलन और कुशल प्रबंधन के साथ विशेष तकनीकी कौशल भी जरूरी है। ताकि नाजुक पहाड़ियों और चट्टानों को कम से कम नुकसान पहुंचे और अगर नुकसान होता है तो फौरन उसकी भरपाई की जाए। जिसका एक तरीका सुनियोजित और कारगर वृक्षारोपण भी है। वृक्षारोपण के नाम पर चीड़ के जंगलों से पहाड़ों को पाट देने की नीति को तो विशेषज्ञ भी गलत और नुकसानदेह ठहरा चुके हैं। जल प्रदूषण ने भी उत्तराखंड के पर्यावरण में असंतुलन पैदा किया है। गंगा का प्रदूषण समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की करोड़ों रुपये की परियोजनाएं भी लगता है नाकाम साबित हुई हैं, क्योंकि पानी की गंदगी जस की तस है। कुल मिलाकर तस्वीर निराशाजनक दिखती है। लगता है कि उत्तराखंड जैसा पहाड़ी राज्य भी उस दुष्चक्र का शिकार बन चुका है जो विकास का एक बेडौल और विवादग्रस्त मॉडल निर्मित करता है।

वाहनों की संख्या नियंत्रित हो

पर्यावरणीय चेतना के अभाव ने रही-सही कसर पूरी कर दी है। जवाबदेही की अनुपस्थिति, प्रशासनिक और शासकीय अनदेखी और आम लोगों का इसे अपनी नियति मान लेने का यथास्थितिवाद-पहाड़ की पर्यावरणीय दुर्दशा के अंदरूनी कारण हैं। पहाड़ पर वाहनों का दबाव बढ़ा जिससे पेट्रोल गाड़ी 4.5 जीएम प्रति किलोमीटर और डीजल गाड़ी 80 जीएम प्रति किलोमीटर तक नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कर रही हैं। वहीं वाहनों द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों का 170 जीएम प्रति किलोमीटर उत्सर्जन हो रहा है जो वातावरण में प्रदूषण फैलाने का काम कर रहा है। भारत में 1 अप्रैल 2020 से वाहनों में वीएस 6 लागू हुआ था, उसके बाद भी प्रति गाड़ी 300 जीएम प्रति किलोमीटर तक का प्रदूषण वातावरण में फैला रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) की बात की जाए तो 160 तक का एक्यूआई लेवल हमारे वातावरण में अच्छा माना जाता है, तो वहीं पहाड़ों में एक्यूआई लेवल 300 तक पहुंच चुका है, जो चिंता की बात है। बात सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण की नहीं है, बात हमारे जल जंगल की भी है आज प्रदेश में जल स्रोतों के क्या हालात हैं यह किसी से छिपा नहीं है। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर पहाड़ों पर गाड़ियों के दबाव को रोकने के लिए काम करना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों के लिए आगे आना चाहिए। असल में पर्यावरण के इन खतरों से निपटने के लिए जरूरत है सामूहिकता की लेकिन लगता है कि इसके लिए कोई भागीरथ प्रयत्न ही करने होंगे।

उत्तराखंड में मिशन धर्मांतरण

ईसाई मिशनरी छोटे बच्चों को निशुल्क पढ़ाने के नाम पर शिक्षण संस्थान चला रही हैं, जिनमें छोटे बच्चों को ईसा मसीह के जीवन के साथ बाइबल की जानकारी दी जाती है, बचपन से ही ईसा मसीह के किस्से सुनकर जब बच्चा बड़ा होकर उच्च शिक्षा में जाता है तो वो पूरी तरह से चर्च के रंग में रंगा होता है।

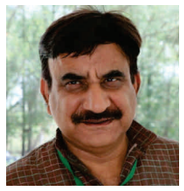

दिनेश मानसेरा
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड के मैदानी जिले ऊधमसिंह नगर के खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता, विधानसभा क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का जाल बिछा हुआ है, ईसाई मिशनरियां न सिर्फ यहां बसी महाराणा प्रताप के वंशज कहने वाली थारू बुक्सा जनजाति को ईसाई बना रही है बल्कि सिखों और जौनसारी जनजाति में भी धर्म परिवर्तन का काम करने में लगी है। 2000 से पहले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब से लेकर अब तक या कहें आजादी के कुछ समय बाद से ही ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण का खेल शुरू कर दिया था। चिकित्सा और शिक्षा के बहाने सेवा कार्य करने वाले मिशनरियों ने जनजाति क्षेत्रों में पहले अपना जाल बिछाया। नदी किनारे मलिन बस्तियों में रहने वाले थारू बुक्सा जनजाति में ईसाई मिशनरी ने अपने स्थानीय नेटवर्क से पहुंच बनाई। खास बात यह है कि नेपाल से सटे इस सीमांत राज्य में चर्च और मिशनरियां इसलिए भी सक्रिय हुई क्योंकि ये इलाका अत्यंत पिछड़ा हुआ था। थारू बुक्सा जो अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज कहलाते हैं, मुगलों के आतंक से यहां तराई के जंगलों में आकर बस गए थे। आजादी के बाद इन्हें यहां कानूनी रूप से जनजाति का दर्जा दिया गया, इन्हें नौकरियों में आरक्षण जैसी सुविधाएं भी दी गई। ईसाई सिस्टम ने यहीं से अपना खेल शुरू किया, कि कैसे सरकारी पदों पर काबिज हो? इसके लिए चर्च मिशनरियों ने यहां मिशनरी कांवेंट स्कूल खोले और अच्छी शिक्षा के लिए जनजाति के बच्चों और उनके परिवारों को प्रलोभन देकर ईसाई बनाने का ताना बाना बुना। तभी से धर्मांतरण का यह षड्यंत्र आजतक निरंतर चला आ रहा है।

धर्मांतरण का तरीका बदला

महाराणा प्रताप के वशंज, सिखों में रायसिख और मजबी जाति जो कभी कट्टर हिंदू थे, वो भी हिंदू धर्म से विमुख होने लगे। विदेशों से मिशनरियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता से धर्मांतरण का अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जो अभी भी बिना किसी रोकटोक के चल रहा है। थारू बुक्सा जनजाति की 40 प्रतिशत आबादी चर्च के चंगुल में फंस कर ईसाई बन चुकी है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से मिशनरियों की विदेशी फंडिंग पर किसी हद तक लगाम लगी है। लेकिन चर्च मिशनरी द्वारा संचालित स्कूलों ने अपने यहां पढ़ने वाले संपन्न परिवार के हिंदू बच्चों की फीस में वृद्धि करके इस पैसे को धर्मांतरण में लगाने का रास्ता निकाल लिया है। यानी संपन्न हिंदू परिवारों के पैसों से ही धर्मांतरण कराया जा रहा है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया तो मिशनरियों ने भी धर्मांतरण का सिस्टम फुलप्रूफ कर लिया। अब ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां केरल से आई नन या सफेद चौला पहने पादरी नहीं चलाते हैं। बल्कि अब इनके द्वारा ईसाई बनाए गए हिंदू पुरुष व महिलाए ही उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, चर्च की जगह प्रार्थना भवन या मंदिर, आश्रम, संत जैसे शब्दों को इस्तेमाल करने वाले ईसाई प्रचारक भी अब भगवा वस्त्र धारण करते है। सिखों में काम करने वाले पादरी प्रचारक सिखों की वेशभूषा में बकायदा पगड़ी कृपाण धारण करके रायसिखों में धर्मांतरण का काम कर रहे है। इनके नाम भी हिंदू है, लेकिन काम हिंदू विरोधी है। जौनसार क्षेत्र के चकराता में स्थानीय युवक सुंदर सिंह चौहान को मिशनरियों ने ईसाई बनाया फिर उसे चर्च का पादरी बनाते हुए स्थानीय लोगों के धर्मांतरण के काम में लगा दिया। जौनसार क्षेत्र में कई फोक सिंगर भी चर्च के प्रभाव में काम कर रहे है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार हरबर्टपुर का एक नामी हॉस्पिटल और हल्द्वानी ग्रामीण क्षेत्र का एक अस्पताल ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। नैनीताल जिले का मैथोडिस्ट चर्च जिसे अब सात ताल आश्रम के नाम से जाना जाता है, मिशनरियों द्वारा संचालित है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसे ही सितारगंज क्षेत्र में रमेश कुमार को रमेश मैसी बनाकर उसे पास्टर का पद दे दिया। रमेश मैसी ने तो विधायक का चुनाव भी लड़ा। इस समय वो धर्मांतरण अभियान का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है। राणा जनजाति समुदाय में दान सिंह राणा, गोपाल राणा को ईसाई धर्म के प्रचार में लगा दिया। झांझरा क्षेत्र में पास्टर डा. चांदना का नाम ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में लिया जाता है।

उत्तराखंड में 2018 के धर्मांतरण कानून में सख्त धाराएं जोड़कर 2024 में धर्मांतरण विधेयक को कानून का रूप दिया है, अब कोई धर्मांतरण कराता है तो उसे जनजाति श्रेणी की सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है, धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों पर जुर्माने व कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

स्कूलों में बच्चों का ईसाईकरण

पंजाब के बाद सबसे ज्यादा सिख उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में बसते है और इनमें अनुसूचित जाति के राय सिखों की बड़ी संख्या है। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है लिहाजा लालच देकर इन्हें आसानी से ईसाई बनाने का काम मिशनरियां कर रही हैं। चर्च की प्रार्थना सभाओं में पगड़ीधारी सिखों को देख कर हैरानी तब होती है जब सिखों के पवित्र तीर्थस्थल श्री नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा यहां स्थापित है और सिख कौम हमेशा गुरु घर के प्रति कट्टर आस्था रखती आई है। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों के सबसे बड़े धर्मांतरण केंद्र अनुग्रह आश्रम में प्रत्येक रविवार को भक्ति पाठ के नाम पर थारू समाज व रायसिख समाज के अनेक लोग यहां फादर से बात कर अपनी परेशानियां जाहिर कर समाधान पाते हैं। फादर इन्हीं से कहते हैं कि ईसा मसीह का गुणगान करने से सबके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दूरदराज से आए लोग प्रत्येक रविवार को लगभग चार घंटे की प्रार्थना के बाद चर्च के फादर से मिलते हैं। फादर इनके आर्थिक रूप से कमजोर होने का फायदा उठाकर उन्हें धन, घरेलू समान इत्यादि उपलब्ध कराकर लुभाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही सितारगंज में खटीमा रोड स्थित अराधलय केंद्र में धर्मांतरण का खुला खेल चलता है। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए ऑनलाइन ईसा मसीह के वीडियो यहां से जारी किए जाते है। इसमें आसपास के गांव थारू, बाघोरी, पैरपुरा, पिंडारी, सजनी आदि गांव के थारू समाज के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। ईसाइयत का प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मिशनरी छोटे बच्चों को निशुल्क पढ़ाने के नाम पर विभिन्न शिक्षण संस्थान भी चला रही हैं। जिनमें छोटे बच्चों को ईसा मसीह के जीवन परिचय के साथ बाइबल के बारे में जानकारी दी जाती है। छोटे बच्चों को जरूरत का सामान जैसे कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, खिलौने और अब ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन तक मिशनरी शिक्षण संस्थानों से निशुल्क दिए जाते हैं। बचपन से ही चर्च ईसा मसीह के किस्से सुनकर जब बच्चा बड़ा होकर उच्च शिक्षा में जाता है तो वो पूरी तरह से चर्च के रंग में रंगा होता है।

नेपाल तक फैलाया नेटवर्क

खटीमा विधानसभा क्षेत्र नेपाल सीमा से सटा हुआ है। यहां चर्च मिशनरी खुलकर धर्मांतरण का काम करती है। इनके वाहन नेपाल में बेरोकटोक आते जाते देखे जा सकते हैं। नेपाल में माओवादी आंदोलन चला और उसी दौर में भारत के नेपाल सीमा से लगे रंसाली, कड़ापानी के जंगलों के वन ग्रामों तक ईसाई मिशनरियां पहुंच गई। ईसाई मिशनरियों के चर्च मोहम्मदपुर भुड़िया, लोहियापुल, उमरकला, फुलईयां, मझोला, पोलीगंज में बने हुए हैं। इनका इतना बड़ा नेटवर्क स्थापित हो चुका है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मलिन बस्तियों में अब ये मिशनरियां कहीं भी प्रार्थना केंद्र बनाकर अपने लक्ष्य साध रही हैं। खास बात ये भी है कि

- **विदेशों से मिशनरियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता से धर्मांतरण का अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, जो बिना किसी रोकटोक के चल रहा है, खटीमा क्षेत्र में थारू बुक्सा जनजाति की 40 प्रतिशत आबादी चर्च के चंगुल में फंस कर ईसाई बन चुकी है।**
- **'ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां केरल से आई नन या सफेद चौला पहने पादरी नहीं चलाते हैं, बल्कि अब इनके द्वारा ईसाई बनाए गए हिंदू पुरुष व महिलाए ही उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, चर्च की जगह प्रार्थना भवन या मंदिर, आश्रम, संत जैसे शब्दों को इस्तेमाल करने वाले ईसाई प्रचारक भी अब भगवा वस्त्र धारण करते हैं, सिखों के बीच काम करने वाले पादरी प्रचारक सिखों की वेशभूषा में बकायदा पगड़ी कृपाण धारण करके रायसिखों में धर्मांतरण का काम कर रहे है।'**

धर्मांतरण कराने वाले ऐसा कोई साक्ष्य नहीं छोड़ते जिससे ये साबित हो कि यहां किसी का धर्म परिवर्तन कराया गया है। अब धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई नाम नहीं बदला जाता। पुख्ता जानकारी ये भी है कि ईसाई मिशनरियों ने उत्तराखंड में रहने वाले गरीब नेपाली मूल के लोगों का भी धर्मांतरण शुरू कर दिया है। धर्म परिवर्तन करने वाले नेपाली लोगों के जरिए अब मिशनरियां पड़ोसी देश नेपाल के भीतर भी घुस गई हैं। जबकि इनका नेटवर्क मुख्यालय खटीमा, सितारगंज से ही संचालित हो रहा है। एडवोकेट अमित रस्तोगी कहते है कि थारू बुक्सा जनजाति दर्जा प्राप्त है और ये ईसाई बन जाने के बाद अल्पसंख्यक होने का भी फायदा उठा रहे हैं जबकि उत्तराखंड में 2018 के धर्मांतरण कानून में और सख्त धाराएं ला कर 2024 में धर्मांतरण विधेयक को कानून का रूप दिया है। जिसके मुताबिक यदि कोई धर्मांतरण कर अल्पसंख्यक बन जाता है तो उसे जनजाति श्रेणी की सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों पर भारी जुर्माना और कठोर कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में धर्मांतरण की घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने कठोर धर्मांतरण कानून लागू किया है, धर्म परिवर्तन करने वाले और करवाने वाले दोनों बक्शे नहीं जाएंगे। उनसे उनके आरक्षण संबंधी सभी अधिकार भी छीन लिए जाएंगे।

गढ़वाल में भी धर्मांतरण

उत्तराखंड के पुरोला में भी ईसाई मिशनरी धर्मांतरण का खेल कर रही हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग गरीब परिवारों की शादी कराने और शादी का खर्च उठाने का लालच देकर नेपाल मूल की महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों नेपाली मूल की एक महिला ने पुलिस को बयान दिया कि गांव का जगदीश ठाकुर और मिशनरी से जुड़े लोग कई दिनों से उसकी शादी का खर्च उठाने और उसे उपहार देने की पेशकश कर रहे थे। महिला उन लोगों के दबाव और प्रलोभन में आई तो उसे मिशनरी के कार्यक्रम में बुलाया गया। इसी कार्यक्रम में उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। उत्तरकाशी जिले के देवढंग में हुए इस कार्यक्रम में धर्मांतरण की जानकारी मिलने पर ग्रामीण वहां पहुंच गए जिसकी आयोजकों के साथ झड़प हुई। झड़प में चर्च का पादरी भी शामिल था। पुरोला पुलिस ने आशा और जीवन केंद्र नामक एक मिशनरी संगठन से जुड़े लोगों के साथ पांच ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पांच ग्रामीण वो थे जो धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों का आरोप है कि ईसाई मिशनरी काम के लिए नेपाल से उत्तरकाशी आने वाले लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रही हैं। पुरोला क्षेत्र के स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने धर्मांतरण के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश

वर्चस्व के झगड़े में संभल सुलगा

वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन का दावा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद पर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता, क्योंकि यह मस्जिद 1920 से एएसआई द्वारा संरक्षित है, लिहाजा जिन इमारतों को संरक्षित किया गया है वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आती।

उ

कृष्ण कुमार चौहान

त्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर संभल सुलग उठा। विवाद की जड़ संभल की शाही जामा मस्जिद थी। मुरादाबाद मंडल के संभल में 16वीं शताब्दी की शाही जामा मस्जिद के सर्वे कराने का संभल जिले की अदालत ने आदेश दिया था। कोर्ट की कार्रवाई पर कट्टरपंथी और राजनीतिज्ञ भड़क गए। वोट बैंक और अपने वर्चस्व को साबित करने की होड़ में राजनीतिज्ञों ने स्थानीय लोगों को भड़काया गया। इसके बाद जो हुआ वह हर अखबार, मीडिया चैनलों की सुर्खियां बन गया। वर्चस्व की इस आग में पुलिस अधिकारी घायल हुए, चार उपद्रवियों की मौत हुई और हिंसा के बाद आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, लेकिन जिस मस्जिद को लेकर इतना बवाल हुआ है, उसका इतिहास क्या है? ये राजनीतिज्ञ और कट्टरपंथी ही नहीं बल्कि संभल के अधिकांश बुद्धिजीवि, साहित्यकार, इतिहासकार, पत्रकार तथा इतिहास पढ़ने में रूचि रखने वाले सब जानते हैं। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण पहले मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल में 1526 से 1530 के बीच कराया गया था। यानी संभल की यह मस्जिद बाबार के संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली शासनकाल के दौरान बनाई गई तीन प्रमुख मस्जिदों में से एक थी। अन्य दो मस्जिदों में एक पानीपत में और दूसरी अयोध्या में थीं। अयोध्या वाली मस्जिद की जगह अब भव्य और दिव्य श्रीराम जन्म भूमि मंदिर का निर्माण हो चुका है। संभल के इतिहास पर नजर डालें तो इस शाही जामा मस्जिद का निर्माण दिसंबर 1526 में बाबर के विश्वासपात्र सिपाहसालार हिंदू बेग कुचिन की देखरेख में श्रीहरिहर मंदिर को तोड़कर किया गया था। इसकी स्थापत्य शैली उस दौर के विकसित हो रहे मुगलकालीन डिजाइन को दर्शाती है, जिसमें एक बड़ा चौकोर हॉल और बीच में एक गुंबद है। मस्जिद के अंदर फारसी शिलालेख मुगल उत्पत्ति की पुष्टि करते हैं, हालांकि इतिहासकारों का दावा है कि इसके निर्माण में पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के अवशेषों को भी शामिल किया गया था। वैसे ऐतिहासिक शहर संभल खुद हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व रखता है, क्योंकि यह विष्णु के दसवें और अंतिम अवतार कल्कि का जन्मस्थान है। ऐसा धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक कल्कि अवतार कलयुग यानी अंधकार के युग को समाप्त करने के लिए संभल में प्रकट होने वाला है। इसी साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल जिले के ही एचोड़ा कम्बोह में आचार्य प्रमोद कृष्णम के आग्रह पर भव्य कल्कि धाम का शिलान्यास कर राम राष्ट्र का आह्वान किया था। पीएम ने दावा किया था कि कल्कि का अवतार हजारों वर्षों के भविष्य का निर्धारण करेगा।

कानूनी विवाद क्या है?

संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाले केलादेवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी का दावा है कि उनके पास एक नक्शा है, जो विक्रम संवत 987 का है। इस नक्शे में पूरे संभल जिले को अंकित किया गया है। इस नक्शे में संभल के 68 तीर्थ स्थलों का उल्लेख है। इसके साथ ही 19 कूप यानी कुओं का जिक्र है। महंत ऋषिराज गिरी का दावा है कि इन 19 कुओं में से एक कुआं मौजूदा समय की शाही जामा मस्जिद के अंदर है, जो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। 2012 तक हिंदू इस कुए पर पूजा आदि करते थे। महंत ऋषिराज गिरी का दावा है कि मस्जिद के अंदर अभी भी ऐसे सबूत मौजूद हैं, जिनसे यह साबित होता है कि शाही जामा मस्जिद पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। महंत ऋषिराज गिरी का दावा है कि बाबरनामा और अकबरनामा किताब में भी यहां मंदिर होने का जिक्र है। इन्हीं किताबों को आधार बनाकर उन्होंने दावा किया है कि यहां पहले श्री हरिहर मंदिर होता था। महंत ऋषिराज गिरी का कहना है कि उन्होंने संभल की अदालत में याचिका दायर कर दरख्वास्त की कि शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगाई जाए और हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाजत दी जाए। याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील पैरवी के लिए संभल आए थे। वकील विष्णु शंकर जैन और अन्य लोगों ने संभल की अदालत में याचिका दायर की। अयोध्या में श्रीराम जन्मस्थल,

संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाले केलादेवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी का दावा है कि उनके पास एक नक्शा है, जो विक्रम संवत 987 का है, इस नक्शे में पूरे संभल जिले को अंकित किया गया है, नक्शे में संभल के 68 तीर्थस्थलों के साथ 19 कुओं का जिक्र है।

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुकदमों की पैरवी करने वाले विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि जामा मस्जिद भगवान कल्कि को समर्पित मंदिर के खंडहर पर बनाई गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 1526 में बाबर के आक्रमण के दौरान मंदिर को नष्ट करने के बाद मस्जिद का निर्माण किया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बाबरनामा और अकबरनामा जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ बाबर की ओर से मंदिर के विनाश का दस्तावेजीकरण करते हैं। दलील में दावा किया गया है कि मंदिर का निर्माण ब्रह्मांड की शुरुआत में हिंदू पौराणिक व्यक्ति विश्वकर्मा ने किया था। आरोप है कि बाबर की सेना ने मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया और इस्लामिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए इसे मस्जिद में बदल दिया। याचिका में आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की भी आलोचना की गई है कि वह साइट पर नियंत्रण करने में विफल रहा, क्योंकि यह 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। याचिका में मांग की गई कि संभल की शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगाई जाए और हिंदुओं को वहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाए। याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी का कहना है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो हिंसा हुई वह निंदनीय है। उपद्रव करने वालों में स्थानीय लोगों के साथ बाहर से भी बुलाए गए लोग थे। इसका मतलब साफ है कि संभल में जो हिंसा हुई वह पूर्व नियोजित थी। महंत ऋषिराज गिरी का कहना है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और मुस्लिम पक्ष को भी कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए। कोर्ट का जो आदेश होगा वह दोनों पक्षों को मानना चाहिए।

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता

19 नवंबर को संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने याचिका का संज्ञान लिया और पाया कि इस मामले में दूसरा पक्ष भारत सरकार है। लिहाजा कोई भी आदेश पारित करने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुना जाना जरूरी है, इसलिए भारत सरकार और अन्य दूसरे पक्षों को सुने जाने के लिए नोटिस भेजा गया। ताकि वो अपना पक्ष भी कोर्ट के सामने रख सकें। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। कोर्ट का आदेश था कि एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जाएं और अपनी रिपोर्ट तैयार करें। एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव को नियुक्त किया गया। जिन्हें तय समय अवधि में रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। चूंकि मामला संवेदनशील था, इसलिए सेर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के समय डीएम और एसपी को मौके पर पुलिसबल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश आने पर जिला प्रशासन और पुलिस ने 19 नवंबर को ही एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव को सुरक्षा उपलब्ध करा दी। हालांकि कोर्ट और जिला प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई की कई वर्गों ने आलोचना करते हुए कहा गया कि ये न्यायिक अधिकार का दुरुपयोग है। मुस्लिम समुदाय जिसमें जामा मस्जिद प्रबंधन समिति भी शामिल है ने सर्वेक्षण का कड़ा विरोध किया। उन्होंने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का हवाला दिया। यह अधिनियम 15 अगस्त, 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को बदलने पर रोक लगाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन का दावा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद पर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता, क्योंकि यह मस्जिद 1920 से एएसआई द्वारा संरक्षित है। यानी कि जिन इमारतों को संरक्षित किया गया है उन पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। सपा के कार्यकाल में एएसआई के अधिकारियों को संभल से बेदखल कर दिया गया था। लिहाजा अब संभल की अदालत में याचिका दायर कर शाही जामा मस्जिद को एएसआई ने संरक्षित रखने की मांग भी की है। ऐसे में सपा सांसद जियाउर्रहमान का ये कहना कि अदालत ने मस्जिद कमेटी का पक्ष सुने बगैर ही सर्वे का फैसला दिया है, गलत और बेबुनियाद है। क्योंकि मस्जिद कमेटी को शाही जामा मस्जिद पर कोई अधिकार ही नहीं है। खैर 19 नवंबर को सर्वे हुआ, लेकिन पूरा नहीं हो सका, इसलिए 24 नवंबर को फिर सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची।

संभल के विधायक को डर है कि कहीं उनके बेटे का राजनीति में भविष्य बनने से पहले ही बिगड़ न जाए, सांसद और विधायक दोनों अच्छी तरह जानते हैं, कि योगी आदित्यनाथ सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को माफ करना उनके स्वभाव में नहीं है।

सर्वे पूरा हो गया, लेकिन जब सर्वे टीम जाने लगी तब भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस तरह संभल में हिंसा की शुरुआत हो गई।

तुर्क व पठान की लड़ाई में तीन मौत

संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रशासन व पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। जांच में पता चला कि हिंसा सुनियोजित थी और इसके पीछे तुर्क और पठान समुदाय के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसने चार युवकों की मौत हो गई। मरने वाले चारों पठान विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थक बताए गए। जांच से पता चला कि हिंसा के मुख्य कारणों में तुर्क बनाम पठान के मुद्दे को हवा दी गई। इसके कारण दोनों समुदायों के समर्थकों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। हिंसा की चिंगारी उस वक्त भड़की जब तुर्क समुदाय के सांसद समर्थकों ने पठान समुदाय के विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थकों पर गोलियां चला दीं। इस गोलाबारी में चार पठान मारे गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में ये खूनी खेल हुआ। अब तक की जांच में यह साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से कोई हताहत नहीं हुआ और मारे गए सभी लोग संभल के विधायक इकबाल महमूद के समर्थक थे। पुलिस ने संभल हिंसा में 11 मुकदमे दर्ज किए हैं। हिंसा में घायल हुए दारोगा दीपक राठी के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और संभल सदर सीट से सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को नामजद किया गया है। इसके अलावा 3500 अज्ञात लोगों को हिंसा में शामिल बताया गया है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने मीडिया को बताया कि हिंसा की शुरुआत तुर्क और पठान समुदाय के बीच तनाव से हुई, जिसमें बर्क और उनके समर्थकों ने भड़काऊ बयान दिए थे। बर्क को पहले भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 168 के तहत नोटिस दिया गया था, जिसमें उन्होंने जामा मस्जिद के संरक्षण को लेकर भड़काने वाली बातें की थीं।

डरे हैं सांसद और विधायक

पठान और तुर्क पर वर्चस्व की लड़ाई में संभल को सुलगाने वाले संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है। इसलिए दोनों माननीय मीडिया के सामने सफाई देते फिर रहे हैं। सांसद कह रहे हैं कि वो तो घटना वाले दिन संभल में ही नहीं थे। विधायक कह रहे हैं कि उनका बेटा तो अमन और शांति की अपील कर रहा था। संभल के सांसद भड़काऊ भाषण के जरिये मशहूर होना चाहते हैं। विधायक अपने बेटे का राजनीति में भविष्य देख रहे हैं, लेकिन संभल में हिंसा के बाद सांसद और विधायक का बेटा पुलिस के रडार पर आया तो दोनों को सपा के कद्दावर नेता आजम खान का चौपट भविष्य नजर आने लगा, इसलिए अब सांसद और विधायक सफाई देते फिर रहे हैं। आजम खान की तरह ही जियाउर्रहमान बर्क भी भड़काऊ भाषण देकर कद्दावर नेता बनना चाहते हैं, लेकिन पहली ही एफआईआर होने पर उन्हें पुलिस का एक्शन डराने लगा है। क्योंकि सांसद हो या विधायक, यदि योगी आदित्यनाथ के राज में कानून हाथ में लेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। ये बात सांसद और विधायक दोनों अच्छी तरह जानते हैं। विधायक को डर है कि कहीं उनके बेटे का राजनीति में भविष्य बनने से पहले ही बिगड़ न जाए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को माफ करना उनके स्वभाव में नहीं है।

कौन है हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन

हरि शंकर जैन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्होंने 1978-79 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से अपनी कानूनी प्रैक्टिस की शुरुआत की, बाद में हरिशंकर जैन प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली चले आए और सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरु की।

अतुल सिन्हा
टीवी जर्नलिस्ट

उत्तर भारत में वर्षों से मंदिर-मस्जिद विवाद चल रहे हैं। 500 साल बाद बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि मंदिर विवाद समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, संभल की शाही जामा मस्जिद, अजमेर की दरगाह, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, कुतुब मीनार दिल्ली की कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, मध्य प्रदेश की कमाल मौला मस्जिद, भोजशाला परिसर, जौनपुर उत्तर प्रदेश की अत्ताला मस्जिद, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश की शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और बदायूं उत्तर प्रदेश की शम्सी शाही मस्जिद विवाद के कोर्ट केस चर्चा में हैं। इन सभी विवादों में दो चेहरे सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। यह जोड़ी हमेशा हिंदू पक्ष की ओर से अदालतों में मोर्चा संभालती दिखाई देती है। अयोध्या के विवादित ढांचा मामले में बड़ी जीत दिलाने के बाद काशी विश्वनाथ धाम से जुड़ी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील पिता-पुत्र हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने बड़ी जीत दिलाई है। जैन पिता-पुत्र ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। वकालत के पेशे में दोनों जाने-पहचाने नाम हैं। हिंदुओं का पक्ष प्रमाणित रूप से अदालतों में रखने वाले पिता हरि शंकर जैन और उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन की जोड़ी का मुख्य लक्ष्य हिंदू धर्मस्थलों को आजाद कराना है। यह जोड़ी अब तक सैकड़ों केस लड़ चुकी है, जिसमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, आगरा के ताज महल और नई दिल्ली स्थित कुतुब मीनार भी इसमें शामिल हैं।

कौन हैं वरिष्ठ वकील हरि शंकर जैन

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं। उन्होंने 1978-79 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से अपनी कानूनी प्रैक्टिस की शुरुआत की। बाद में हरिशंकर जैन प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली चले आए और सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की। अब वो दिल्ली में ही रहते हैं। हरिशंकर जैन बताते हैं कि हिंदू हितों के पक्ष में काम करने के लिए उनकी मां विभावती देवी ने उन्हें काफी प्रेरित किया। एक इंटरव्यू में हरिशंकर जैन ने बताया था कि उनके पिता नेमचंद्र जैन न्यायिक सेवाओं में थे, लेकिन वह उनके हिंदू हितों की कानूनी पैरवी करने के खिलाफ थे। हरिशंकर जैन ने कहा था कि उनके पिता चाहते थे कि वह कोर्ट में जज बनें। जब उन्होंने राम जन्मभूमि

मामले को उठाने का फैसला किया था तो उनके पिता ने 2 दिनों तक खाना नहीं खाया था। हरिशंकर जैन ने बताया था कि मैंने अपनी मां के दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। 1989 में अयोध्या विवाद में हिंदू महासभा के वकील के रूप में नियुक्त होने पर हरि शंकर जैन को राष्ट्रीय पहचान मिली। तब से पिता और पुत्र दोनों ने हिंदू पक्ष से जुड़े 102 से अधिक विवादों में सक्रिय रूप से पैरोकारी की या याचिका दायर की हैं। खास बात ये है कि ज्यादातर मामलों में पिता-पुत्र की जोड़ी ने सफलता हासिल की है, जबकि कुछ केस अभी अदालतों में विचाराधीन हैं। 9 अक्टूबर 1986 को जन्मे विष्णु शंकर जैन ने 2010 में पुणे के बालाजी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट में श्रीराम जन्मभूमि मामले से उन्होंने अपने वकालत के करियर का आगाज किया। साल 2016 में उनको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल गया था। कानून की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ वकालत के गुर सीखे। अपने पिता के बीमार पड़ने पर उन्होंने उनके काम की कमान संभाल ली। विष्णु शंकर जैन अब अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मामले से लेकर कुतुब मीनार बनाने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मामला, ताजमहल के पूर्व में शिवमंदिर होने का दावा, प्लेस आफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देने के मामले को यही दोनों पिता-पुत्र अदालतों में संभाल रहे हैं। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के शेष गुफा होने का दावा और संभल में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा भी इन्हीं पिता-पुत्र की जोड़ी ने किया है। इतना ही नहीं इन दोनों ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द के संशोधन की वैधता को भी चुनौती दी थी। 2021 में वकील पिता-पुत्र की जोड़ी ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सात केस दर्ज किए, जिसमें गंगा नदी, देवी नंदी और मां श्रृंगार गौरी का मामला शामिल था।

अयोध्या के विवादित ढांचे मामले में बड़ी जीत दिलाने के बाद काशी विश्वनाथ धाम से जुड़ी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील पिता-पुत्र हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने बड़ी जीत दिलाई है, जैन पिता-पुत्र ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है।

बाबरी मस्जिद का पक्ष रखने का ऑफर

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक हरि शंकर जैन को श्रीराम जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की पैरवी छोड़ कर मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद की पैरवी करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हरि शंकर जैन ने इसे ठुकरा दिया था। उनका मानना था कि वे पैसों के लिए अपनी अंतरआत्मा नहीं बेच सकते। हरिशंकर जैन को अपनी मां से काफी लगाव था। मां से ही उन्होंने हिंदुत्व और धर्म के बारे में जाना था। 6 दिसंबर 1992 को मां का देहांत हो गया। जिसके बाद वह बुरी तरह से टूट गए थे। इसके बाद भी वो धर्म के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी समझते हैं, उससे पीछे नहीं हटे। लिहाजा मां की तेरहवीं के अगले ही दिन यानी 20 दिसंबर 1992 को वह हिंदू पक्ष की याचिका दायर करने इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए थे। वह इस केस में तब तक डटे रहे जब तक कोर्ट ने भगवान श्रीराम की पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दे दी थी।

सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ चुके चुनाव

हरि शंकर जैन ने एक बार कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला था। इतना ही नहीं उन्होंने 1993 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ना। यह हार कोई अप्रत्याशित नहीं थी, बल्कि हरि शंकर जैन जानते थे कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे। सोनिया गांधी यह चुनाव जीती थी, लेकिन हरिशंकर जैन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी के चुनाव को यह आधार देते हुए चुनौती दी थी कि वह इटली मूल की नागरिक हैं, भारतीय नहीं हैं। इसके साथ ही राजीव गांधी के साथ सोनिया के विवाह की वैधता को भी चुनौती दी थी। उन्होंने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(सी) की वैधता को भी चुनौती दी थी, इसी के तहत सोनिया ने रजिस्ट्रेशन के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल की थी। इस संबंध में विष्णु शंकर जैन का कहना था कि भारत में नागरिकता दो तरह से मिलती है। पहली जन्मजात दूसरी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा कानून के जरिए नागरिकता प्रदान की जाती है। इस आधार पर दूसरे वर्ग के पंजीकृत नागरिक 'असल' में भारतीय नागरिक नहीं माने जा सकते। संविधान के अनुच्छेद 84 की परिभाषा में भारत में जन्मे या भारतीयों के वंशज भारतीय होने की योग्यता रखते हैं। इसलिए केवल वही लोकसभा में चुने जा सकते हैं। ऐसे में सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता अधिनियम सेक्शन 5(1)(सी) के तहत दी गई नागरिकता पहले वर्ग के समान

- **हरिशंकर जैन ने कांग्रेस व सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, उन्होंने 1993 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ना था, यह हार कोई अप्रत्याशित नहीं थी, बल्कि हरि शंकर जैन जानते थे कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे।**
- **पिता-पुत्र की यह जोड़ी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, हिंदू महासभा, गोवा की सनातन संस्था, भगवा रक्षा वाहिनी और हिंद साम्राज्य पार्टी जैसे कई संस्थाओं से जुड़ी है, यह जोड़ी कानूनी जागरुकता से हिंदू क्रांति लाना चाहती है।**

नहीं मानी जानी चाहिए। इस सेक्शन को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। विष्णु शंकर जैन का कहना है कि सिटीजन ऑफ इंडिया' और 'इंडियन सिटीजन' दोनों अलग-अलग हैं। सोनिया गांधी 'इंडियन सिटीजन' हैं और उन्हें मतदाता के रूप में भी पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए था। विष्णु शंकर जैन का कहना है कि पहले बिना सुनवाई के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और फिर 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पिता-पुत्र की यह जोड़ी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, हिंदू महासभा, गोवा की सनातन संस्था, भगवा रक्षा वाहिनी और हिंद साम्राज्य पार्टी जैसे कई संस्थाओं से जुड़ी है। यह जोड़ी कानूनी जागरूकता से हिंदू क्रांति लाना चाहती है।

कोर्ट में हरिशंकर जैन का महत्व

1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा तोड़ा जा चुका था। पूरा परिसर सील कर दिया गया था। लिहाजा श्री रामलला की पूजा भी बंद करनी पड़ी थी। सबसे पहले हरिशंकर जैन ने ही इस बात को समझा कि परिसर सील होने से श्रीरामलला की पूजा बंद हो गई तो हमारा दावा कमजोर हो जाएगा। वह सुप्रीम कोर्ट गए और अपील की कि हिंदुओं को श्रीरामलला की पूजा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उनके अकाट्य तर्कों के कारण सुप्रीम कोर्ट को श्रीरामलला की पूजा कि अनुमति देनी पड़ी और जन्मभूमि की सील को हटाया दिया गया। इसके बाद लगातार 30 वर्षों तक पूजा होती रही और जिसका केस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अंततः श्रीराम जन्मभूमि मामले में हिंदुओं की विजय हुई। ठीक ऐसा ही 30 साल बाद हुआ, जब वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग की आकृति मिली। इसके मिलने के तुरंत बाद विष्णु शंकर जैन मंदिर पक्ष के वकीलों के साथ अदालत पहुंचे और शिवलिंग की आकृति मिलने के साक्ष्य को सील करने का आदेश हासिल किया। इसके बाद कथित मस्जिद के वजूखाने को सील कर दिया गया जो अभी तक वह सील है। इसलिए जुमे की नमाज अदा करने वाले लोगों से कहा जाने लगा कि वो कहीं और जाकर नमाज पढ़े। दिलचस्प संयोग है कि हरिशंकर जैन ने 1992 में जन्मभूमि की सील हटवाकर सफलता की तरफ कदम बढ़ाया था और अब 2022 में विष्णु शंकर जैन ने ज्ञानवापी को सील कराने में सफलता पाई है। हरिशंकर जैन के महत्व का अंदाजा एक घटना से समझा जा सकता है। 17 मई को ज्ञानवापी प्रकरण में वादी पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने हरिशंकर जैन का स्वास्थ्य ठीक न होने की बात कहते हुए सुनवाई की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की। वादी पक्ष की ओर से कोर्ट में विष्णु शंकर जैन के अलावा भारत के सालिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ ही रंजीत कुमार, सीएस विद्यानाथन जैसे दिग्गज वकील उपस्थित थे, लेकिन इनमें से किसी के पास मुकदमे की पूरी फाइल नहीं थी। यह फाइल सिर्फ हरिशंकर जैन के पास थी लिहाजा कोर्ट को सुनवाई टालनी पड़ गई थी। ●

शिवावतार हैड़ाखान बाबा

यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के अभ्यास से अनेक प्रकार की सिद्धियां स्वतः हस्तगत हो जाती हैं, जिनका वर्णन योग दर्शन, गोरक्ष-शतक, याज्ञवल्कय संहिता व योग वासिष्ठादि ग्रंथों में किया गया है, श्री मुनीन्द्र महाराज तो इन सब सिद्धियों के प्रदाता एवं योग शास्त्र के प्रवर्तक रहे।

डॉ.सतीश चंद्र अग्रवाल
पूर्व आयकर आयुक्त

भारतवर्ष में अनेक ऐसे संत हुए हैं जिनमें दिव्य यौगिक शक्तियां रहीं और उनके द्वारा अद्भुत अलौकिक जनकल्याण के कार्य सपन्न हुए। शिवपुराण में उल्लेख है कि विष्णु भगवान के अवतारों की भांति भगवान शिव के भी कई अवतार साधु-संतों के रूप में हुए हैं। ऐसे ही एक सिद्ध संत श्री हैड़ाखान महाराज कुमाऊं क्षेत्र में अवतीर्ण हुए। हल्द्वानी से गौलापार 30 किलोमीटर पहाड़ी पर प्रसिद्ध हैड़ाखान आश्रम है। यह गौला नदी के तट पर स्थित है। गौला नदी के दूसरी ओर चोटी पर कभी शिव पार्वती ने यात्रा से लौटते हुए कुछ समय विश्राम किया था। इसी छोटा कैलास की तलहटी में एक देव निर्मित प्राकृतिक गुफा है। समीपस्थ हैड़ाखान नामक गांव है। यहां पर त्रिफला अर्थात हरड़, बहेड़ा व आंवला में से जिसको हरड़ कहते हैं, उसके अनेक वृक्ष हैं। इसलिए गांव का नाम हैड़ाखान पड़ गया। सन 1880 में कल-कल निनाद करती गौला नदी के किनारे गुफा में एक योगी को ध्यानावस्थित देखा गया। हैड़ाखान गांव की गुफा में प्रथम बार देखे जाने के कारण वे हैड़ाखान बाबा के नाम से ही जाने जाते रहे। बाद में उन्हें मुनीन्द्र महाराज भी कहा गया। सघन वृक्षों व सुंदर पक्षियों की चहचहाट से युक्त यह स्थल अति सुरम्य, शांत एवं मन को प्रफुल्लित करने वाला है। बाबाजी का परिधान भारतीय संस्कृति के अनुरुप सफेद कुर्ता, टोपी, धोती ही रहा। वे बहुत धीरे ओर मधुर वाणी में वार्तालाप करते थे। शारीरिक बल अतुलनीय था। बड़ी-बड़ी चट्टानों को सहज ही खिसका देते थे। वन के हिंसक जीवों से उन्हें कोई भय नहीं होता था।

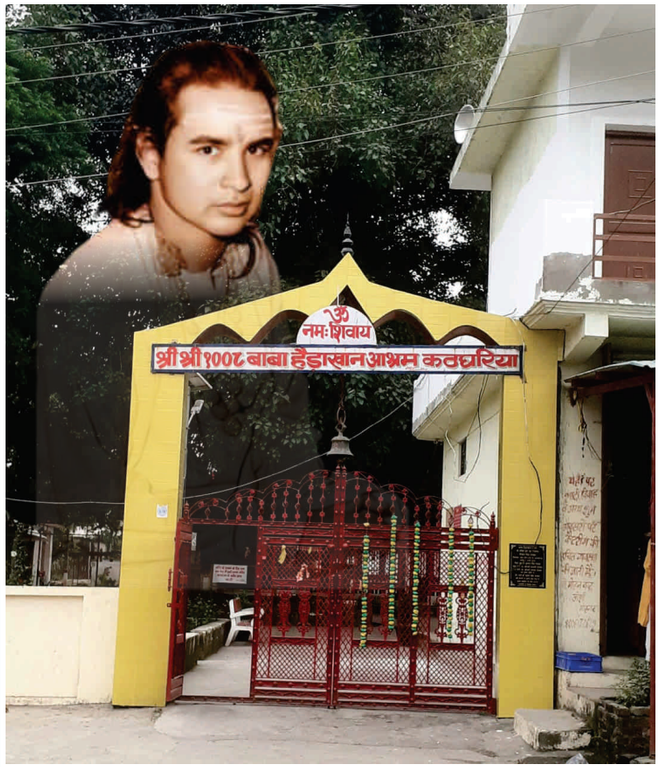

शेर भी प्रणाम करते थे बाबा को एक बार बाबा हैड़ाखान की गुफा से हटकर एक पर्णकुटी में बिराजे हुए थे। उस स्थान पर आपने पहले पंचाग्नि तप किया था। ग्रामीणों ने देखा कि एक विशालकाय सिंह प्रातःकाल आपको प्रणाम करने आया करता है। तभी कुछ महात्मा अतिथि आ गए। प्रातःकाल के समय सिंह को अपनी ओर आता देखकर भय से कांपने लगे। हैड़ाखान महाराज ने उन्हें समझाया, भय की आशंका निर्मूल है- वह प्रणाम कर के लौट जाएगा। सिंह जब बिलकुल पास आ गया तो उन्होंने आंखे मीच लीं। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो सिंह को वापस जाते हुए देखा। कहा जाता है कि सिद्ध योगी प्रच्छन्नावस्था में रहते हैं और लोक कल्याण के लिए ही सिद्धियों का आश्रय लेते हैं। भगवद् भजन में भी सिद्धियां सहायक होती हैं। उनका स्थूल कलेवर दिव्य स्वरूप धारण कर लेता है, जिस पर प्रकृति के किसी तत्व का प्रभाव नहीं होता। वे योग बल से विष को अमृत में बदल सकते हैं। प्रारब्ध के लेख को पलट सकते हैं। उनकी कृपादृष्टि से ग्रह-नक्षत्रों के दोष दूर हो सकते हैं। इसी प्रकार उनके संसर्ग से हिंसक जीव भी हिंसा वृत्ति त्याग देते हैं।

कठघरिया में हैड़ाखान आश्रम

अल्मोड़ा निवासी तत्कालीन विद्वान ज्योतिर्विद पंडित रामदत्त जी का कहना था कि मुनीन्द्र महाराज (बाबाजी) के संबंध में देखी सुनी गई आश्चर्यजनक घटनाओं पर शंका या अविश्वास करना अनुचित है। यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के अभ्यास से अनेक प्रकार की सिद्धियां स्वतः हस्तगत हो जाती हैं,

लगभग 1927 में हैड़ाखान महाराज पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट में काली नदी पार करते हुए अदृश्य हो गए थे, हैड़ाखान महाराज के भक्तों में अल्मोड़ा शीतलाखेत के शिरोमणि पाठक एवं गौलापार हल्द्वानी के गुमानी भगत का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है।

जिनका वर्णन योग दर्शन, गोरक्ष-शतक, याज्ञवल्कय संहिता व योग वासिष्ठादि ग्रंथों में किया गया है। श्री मुनीन्द्र महाराज तो इन सब सिद्धियों के प्रदाता एवं योग शास्त्र के प्रवर्तक रहे। हल्द्वानी में श्री हैड़ाखान महाराज का कालाढूंगी रोड पर कठघरिया में आश्रम है, साथ ही श्री हैड़ाखान बाबा राजकीय इंटर कालेज भी है। करीब 100 वर्ष पूर्व एक दिन अल्मोड़ा क्षेत्र के अंग्रेज कमिश्नर दौरा करते हुए कठघरिया आए। उन्होंने श्री मुनीन्द्र महाराज को सिद्धासन में ध्यानमग्न देखा। कदम्ब के वृक्ष के नीचे मुनीन्द्र महाराज के दर्शन मात्र से वह इतना प्रभावित हुआ कि हाथी से उतर कर प्रार्थना के भाव से अपलक देखता रहा। कुछ देर बाद आसपास के लोगों से महाराज के बारे में पूछा तो उन्होंने सिद्ध सिद्धेश्वर महाराज की विभूतियों का परिचय कराया। इसके बाद ही अंग्रेज कमिश्नर ने 60 बीघा लगान माफ भूमि महाराज को अर्पित कर दी। वर्तमान में इसी भूमि पर केदारेश्वर मंदिर, हैड़ाखान का विग्रह, दुर्गा, हनुमान व भैरव आदि के मंदिर हैं तथा इंटर कालेज व उसका प्रांगण है, जिसमें प्रतिवर्ष रामलीला का मंचन होता है। विचित्र बात यह है कि जिस कदम्ब के वृक्ष के तले महाराज जी बैठते थे उसके साथ ही पीपल और वट के पेड़ भी उग आए और अब तीनों एक होकर विशाल वृक्ष के रूप में शोभायमान हैं। वृक्ष के तले में चबूतरे पर महाराज जी की 'चरण पादुका' स्थापित हैं। जहां भक्तजन धूप-दीप व पुष्प आदि से अर्चना वंदना करते हैं। केदारेश्वर महादेव में प्राकृतिक शिवलिंग है, जैसा कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ जी का है। वैसा ही तिकोने आकार, श्यामवर्णी शिलाखंड है-केवल थोड़ा छोटा है। महाराज जी कहा करते थे जो व्यक्ति केदारनाथ जी दर्शन के लिए न जा सकें वह यहां दर्शन पूजन कर ले तो उसे वही पुण्य मिलेगा जो केदारनाथ जी का होता है। शिवलिंग के प्राकट्य के बारे में कहा गया है कि एक दिन बाबाजी के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो अचानक महाराज जी के मुख से शब्द निकले कि केदारेश्वर भगवान प्रकट होना चाहते हैं। आपने बच्चों को वहां से मिट्टी हटाने की आज्ञा दी और कुछ देर बाद वहां श्री केदारेश्वर प्राकृतिक शिवलिंग दिखाई दिया। उस लिंग के आसपास की जमीन साफ कराई गई और एक सुंदर छोटा मंदिर बनवाया गया। अभी 4-5 वर्ष पूर्व मंदिर को बड़ा कर दिया गया है, ताकि कुछ लोग बैठकर अभिषेक कर सकें।

हैड़ाखान महाराज साक्षात अवतार थे

उसी कालखंड में परम तपस्वी सिद्ध संत सोमवारी महाराज भी हुए जो पदमपुरी, काकड़ीघाट, खैरना, कैंची की गुफाओं में साधनारत रहे। मुनीन्द्र महाराज और सोमवारी बाबा एक दूसरे को बहुत आदर देते थे। जब कभी मुनीन्द्र महाराज सोमवारी बाबा के आश्रम में आते थे तो सोमवारी बाबा दौड़कर 'पिताजी-पिताजी' कहते हुए प्रणाम करते और अपने आसन पर बैठाते थे। सत्संग में सोमवारी बाबा कहा करते थे कि जिस सद्गृहस्थ का एक रोटी का टुकड़ा भी मुनीन्द्र महाराज पा लेते हैं उसके भाग्य की सराहना देववृन्द भी करते हैं। वे भक्तों से कहते थे कि हैड़ाखान महाराज साक्षात अवतार हैं। दोनों महापुरुषों में बहुत प्रेम था। पनियाली वाले सीताराम बाबा व हल्द्वानी के लटुरिया बाबा भी हैड़ाखान और सोमवारी बाबा के साथ तीर्थ यात्राओं में भी जाते थे-यह बात स्वयं सीताराम बाबा ने भी भक्तों को बताई। एक लामा साधू भी कठघरिया आश्रम में बहुत समय तक साधनारत रहे। कठघरिया धाम से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर लामाचौड़ नामक स्थान है। स्पष्ट है कि उस समय तिब्बत के लामा संत यहां साधना के लिए आया करते थे। हैड़ाखान महाराज ने भी नेपाल और तिब्बत में यात्राएं कीं तथा बहुत समय वहां बिताया। लामा रूप में उनका एक चित्र भी उपलब्ध है। उत्तराखंड के सभी संत महात्मा कठघरिया धाम दर्शन एव ध्यान साधना हेतु समय-समय पर आते रहे हैं। इसी क्रम में मूलतः बिहार के निवासी संत श्री महेंद्र महाराज का भी आगमन हुआ। उन्होंने फाल्गुन शुक्ल की पंचमी संवत 2014 अर्थात मार्च 1958 में कठघरिया धाम में हैड़ाखान महाराज की प्रतिमा स्थापित करवाई। एक दिन पूर्व रात्रि में भजन कीर्तन व अखंड रामायण पाठ चल रहा था तभी एक दिव्य प्रकाश पुंज आकाश में दृश्यमान हुआ, फिर वह प्रकाश धीरे-धीरे नाचे आकर आश्रम की परिक्रमा करता हुआ अदृश्य हो गया।

गुफा व मंदिर बांध के डूब क्षेत्र में

श्री मुनीन्द्र महाराज के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण वैदिक विधि-विधान के साथ संपन्न हुई। जिस स्थान पर श्री विग्रह स्थापित किया गया वहां नींव के लिए खुदाई के समय सुगंधित भस्म मिली जो इस बात का संकेत है कि पूर्व में उस जगह यज्ञ किए गए होंगे। प्राण प्रतिष्ठा व हवन के पश्चात विशाल भंडारा हुआ। पांच वर्ष की अल्पायु में दादा जी के साथ मुझे भी भंडारे का प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मानस पटल पर अभी भी वे दृश्य अंकित हैं जब रिक्शे और तांगे से सैंकड़ों लोग कठघरिया जा रहे थे। सड़क कच्ची थी फिर भी हिचकोले खाते हुए आश्रम तक आना जाना बड़ा आनंददायक रहा। सन 1970 के दशक में एक और युवा संत इस क्षेत्र में आए, जिन्हें भोले बाबा कहा गया। कुछ लोग उन्हें प्राचीन हैड़ाखान महाराज का ही रूप मानते हैं। हैड़ाखान महाराज पिथौरगढ़ जिले के अस्कोट में काली नदी पार करते हुए अदृश्य हो गए थे-लगभग 1927 में। हैड़ाखान महाराज के भक्तों में अल्मोड़ा शीतलाखेत के शिरोमणि पाठक एवं गौलापार हल्द्वानी के गुमानी भगत का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भोले बाबा का सन 1984 में चिलियानौला, रानीखेत में देहावसान हो गया। उन्होंने हैड़ाखान

- **हैड़ाखान बाबा का परिधान भारतीय संस्कृति के अनुरुप सफेद कुर्ता, टोपी, धोती ही रहा, वे बहुत धीरे और मधुर वाणी में वार्तालाप करते थे, शारीरिक बल अतुलनीय था, बड़ी-बड़ी चट्टानों को सहज ही खिसका देते थे, वन के हिंसक जीवों से उन्हें कोई भय नहीं होता था।**
- **1880 में कल-कल निनाद करती गौला नदी के किनारे गुफा में एक योगी को ध्यानावस्थित देखा गया, हैड़ाखान गांव की गुफा में प्रथम बार देखे जाने के कारण वे हैड़ाखान बाबा के नाम से ही जाने जाते रहे, बाद में उन्हें मुनीन्द्र महाराज भी कहा गया।**

मंदिर व आश्रम को वृहद रूप दिया, जहां आज भी अनेक साधक ध्यान साधना करने के लिए आते हैं। चिलियानौला में अस्पताल और मंदिर भी उन्हीं की देन है। ज्ञात हुआ है कि जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत हैड़ाखान मंदिर, गुफा व आश्रम सभी बांध के डूब क्षेत्र में समा जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो शिवावतार हैड़ाखान महाराज का एक लीला क्षेत्र विलुप्त हो जाएगा।

महाराष्ट्र में राहु का प्रकोप

जिस तरह राहुल गांधी हिंदुओं व हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलते हैं ठीक उसी तरह विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गए, भाजपा ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ नैरेटिव सेट किया कि वो औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य बन गए हैं, उद्धव को चुनौती दी कि वो राहुल गांधी से हिंदू सम्राट बाला साबेह ठाकरे कहलवा दें।

उदय भान सिंह
लेखक

महाराष्ट्र में भाजपा की बम्पर जीत ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के होश उड़ा दिए। राहुल गांधी के साथ मिलकर पहला चुनाव लड़ने वाली शिवसेना (उद्धव) को 20 पर, कांग्रेस खुद 16 पर और एनसीपी (शरद) 10 सीटों पर यानी कुल 46 सीटों पर सिमट गई। जबकि भाजपा के साथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली एनसीपी (अजीत) ने 41 सीटों पर, शिवसेना (शिंदे) ने 57 सीटें और खुद भाजपा ने 132 यानी कुल 230 सीटें जीत कर महाराष्ट्र का नया इतिहास लिख दिया। यहां एक कहावत राहुल गांधी के लिए सटीक बैठती है वो है, 'हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे।' यानी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी लगातार हार का रिकार्ड बना रहे हैं। वो जिसके साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ते हैं उसकी लुटिया डूब जाती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मीडिया में चर्चा है कि 'चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को फोन किया। बातचीत शुरू ही हुई थी कि राहुल गांधी ने उद्धव से कह दिया कि मुझे तो चुनाव हारने की आदत है तुम अपना देख लो...।' अब चुनाव विषलेशक, विषलेशण कर रहे हैं कि कांग्रेस लगातार चुनाव क्यों हार रही है? इनमें से ज्यादातर का मत है कि कांग्रेस में राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ कहने भर के लिए कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कांग्रेस में चलती राहुल गांधी की है। राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई, अडाणी, जातिय जनगणना से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जबकि जनता की इन मुद्दों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। दूसरा राहुल गांधी जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी तौर पर हमला करेंगे, यानी 'चौकीदार चोर है', लेकिन अब राहुल के लिए चौकीदार ईमानदार हो गया क्या? क्योंकि 2019 के बाद उनके मुंह से चौकीदार चोर है का नारा नहीं सुना। अब पीएम मोदी को 'पनौती' और 'जेबकतरा' बताया जा रहा है। इससे भी राहुल गांधी का ग्राफ नीचे गिरा है। चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि हरियाणआ और महाराष्ट्र ने राहुल गांधी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि कांग्रेस अब परजीवी पार्टी हो गई है। वो क्षेत्रीय दलों की मदद से चुनाव में कुछ हासिल कर सकती है, लेकिन अपने दम पर क्षेत्रीय दलों को ज्यादातर नुकसान ही पहुंचाती आ रही है। यूपी में सपा को नौ सीटों पर कांग्रेस ने समर्थन दिया जिसका परिणाम ये हुआ कि अखिलेश यादव अपनी तीन सीटें गवां बैठे। सिर्फ दो सीटों पर उपचुनाव जीत पाए। हरियाणा में जीत के अहंकार में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। हरियाणा, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की शर्मनाक हार के बाद गठबंधन के नेता राहुल गांधी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगे हैं।

कांग्रेस में राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ कहने भर के लिए कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कांग्रेस में चलती राहुल गांधी की है, राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई, अडाणी, जातिय जनगणना से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जबकि जनता की इन मुद्दों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है।

- **महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मीडिया में चर्चा है कि चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को फोन किया, बातचीत शुरु ही हुई थी कि राहुल गांधी ने उद्धव से कह दिया कि 'मुझे तो चुनाव हारने की आदत है तुम अपना देख लो...।'**
- **राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला करते हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं करते, 2019 में राहुल का नारा था 'चौकीदार चोर है', लेकिन अब राहुल के लिए चौकीदार ईमानदार हो गया, क्योंकि 2019 के बाद उनके मुंह से चौकीदार चोर है का नारा नहीं सुना।**

इंडिया गठबंधन में दरार?

हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार के बाद इंडिया गठबंधन में दरारें दिखाई देने लगी हैं। कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंपने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इससे कांग्रेस और टीएमसी के बीच तलवारें खींच रही हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कहा कि कांग्रेस को अहंकार त्याग कर ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा मान लेना चाहिए। अगर भाजपा को सत्ता से बाहर करना है तो विपक्ष को एकजुट होकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करना चाहिए। क्योंकि ममता ही एकमात्र नेता हैं जो भाजपा को हरा सकती हैं। विपक्ष में नेतृत्व का अभाव है और ममता बनर्जी उस खाली स्थान को भर सकती हैं। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान से कांग्रेस असहज हो गई। लिहाजा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी को उसकी हैसियत बताते हुए कह दिया कि टीएमसी कुए के मेढ़क जैसी है। जो आसमान को अपने कुएं जैसा देखती है। वैसे भी टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है बल्कि एक क्षेत्रीय पार्टी है। साथ ही टीएमसी का लगातार राजनीतिक आधार सिकुड़ता जा रहा है। यदि ममता बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की इच्छा रखती हैं तो उन्हें खुद सामने आकर अपनी इच्छा जाहिर करनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने ममता की इच्छा को मुंगेरीलाल के हसीन सपना करार दिया। इंडिया गठबंधन में फूट का इफेक्ट झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखाई दिया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को ममता बनर्जी सहित सपा नेता अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आदि ने कोई महत्व नहीं दिया। कांग्रेस के दोनों नेता झारखंड में अलग-थलग से नजर आए।

उद्धव घर के रहे न घाट के

महाराष्ट्र के 2019 में हुए विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो भाजपा ने 105, शिवसेना ने 56, कांग्रेस ने 44 और एनसीपी ने 54 सीटें जीत हासिल की थी। 2019 में भाजपा और शिवसेना गठबंधन को 161 सीटें मिली थी, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने पर अड़ गए, नतीजा ये हुआ कि दशकों पुराना गठबंधन टूट गया और उद्धव ठाकरे विपरीत विचारधारा की एनसीपी तथा कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र के सीएम बन गए, लेकिन ढाई साल में ही उनकी पार्टी का विभाजन हो गया और अल्पमत के कारण उद्धव ठाकरे की सत्ता चली गई। सिर्फ सत्ता ही नहीं गई बल्कि बाला साहेब ठाकरे से विरासत में मिली शिवसेना और पार्टी का निशान भी दोनों भी हाथ से निकल गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्याग कर कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया। जबकि बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस से गठबंधन की नौबत आएगी मैं अपनी शिवसेना को खत्म कर दूंगा। बाला साहेब ठाकरे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से गठबंधन कर बाला साहेब की दिवंगत आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। अपने पूर्वजों के आदर्श, विचारधारा व सिद्धांतों से भटकने की सजा उद्धव ठाकरे को मिली है। महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे किसी तरह 8801 वोट से अपनी सीट बचा पाएं। 2019 के विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे को 89,248 मिले थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 67,427 वोटों से हराया था, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे 63,324 वोटों पर सिमट गए। यानी इस बार उन्हें उतने वोट भी नहीं मिले जितने वोटों से 2019 का चुनाव जीता था। जीत भले ही एक वोट से हो जीत तो जीत ही होती है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के पौत्र और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में सिर्फ 8801 वोट से जीत हासिल करना कोई गर्व करने की बात नहीं हो सकती। इससे एक सवाल हर किसी के जहन में आ रहा होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव) की यह दशा क्यों हुई? इसका जवाब यह है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के हिंदू विरोधी एजेंडे का शिकार हो गए।

हिंदुत्व के मुद्दे से भटके उद्धव

जिस तरह राहुल गांधी हिंदुओं और हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलते हैं ठीक उसी तरह विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गए। भाजपा ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ नैरेटिव सेट किया कि वो औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य बन गए हैं। उद्धव को चुनौती दी कि वो राहुल गांधी से हिंदू सम्राट बाला साबेह ठाकरे कहलवा दें। गृह मंत्री अमित शाह ने ताल ठोक कर कहा कि उद्धव ठाकरे उन दलों के साथ हैं जिन्होंने औरंगाबाद का नाम बदलने, राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और पाकिस्तान के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया था। महा विकास अघाड़ी, औरंगजेब फैन क्लब है, जबकि महायुति छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर के सिद्धांतों का पालन करती है। भाजपा नेताओं के इन सवालों से उद्धव ठाकरे इसलिए भी घिर गए क्योंकि महा विकास अघाड़ी के पक्ष में कट्टरपंथियों ने फतवा जारी किया। मुसलमानों की 17 मांगों का महा विकास अघाड़ी ने समर्थन किया। इससे साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गए हैं। चूंकि उद्धव ठाकरे गठबंधन का हिस्सा थे इसलिए वो कांग्रेस या एनसीपी नेताओं द्वारा हिंदुत्व के खिलाफ दिए जाने वाले बयानों का विराध भी नहीं कर पाए। फिर बाला साहेब ठाकरे तो महाराष्ट्र में जीवन भर एनसीपी और कांग्रेस से ही लड़ते रहे थे। इससे शिवसैनिकों और उद्धव समर्थक मराठों को लगा कि बाला साहेब की विरासत का उद्धव ठाकरे इस्लामीकरण तो नहीं कर रहे हैं? शायद इसलिए ही आदित्य ठाकरे को भी मुश्किल से जीत हासिल हुई।

हार का साइड इफेक्ट

महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी की शर्मनाक हार के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। करारी हार के बाद महा विकास अघाड़ी में भी दरार के संकेत मिलने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भीतर से महा विकास अघाड़ी से अलग होने की आवाज उठने लगी है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या शरद पवार और राहुल गांधी से उद्धव ठाकरे का मोह भंग हो गया है? क्या बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को अपनी गलती का एहसास हो रहा है? क्या वह सच में महा विकास अघाड़ी का साथ छोड़ेंगे? क्या भविष्य में होने वाले स्थानीय निकाय, पंचायत और सहकारिता के चुनाव शिवसेना अकेले लड़ेगी? महाराष्ट्र चुनावों में शर्मनाक हार के बाद शिवसेना (उद्धव) के अंदर से आवाज उठने लगी है कि उद्धव ठाकरे को समय रहते महा विकास आघाड़ी से अलग हो जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिवसेना (उद्धव) को अकेले महाराष्ट्र में फिर से खड़े होने की जरूरत है। लेकिन कार्यकर्ताओं की इस मांग पर अभी तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना के किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया है। खुद उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिवसेना (उद्धव) में अंदरखाने कहा जा रहा है कि महा विकास अघाड़ी के साथ रहने से शिवसेना को फायदा कम और नुकसान बड़ा हुआ है। भाजपा से नाता तोड़ने के बाद शिवसेना के पास न तो पार्टी का नाम बचा है और न चुनाव निशान बचा है। विधानसभा में तो सीटों की संख्या भी आश्चर्यजनक रूप से घटी हैं। महा विकास अघाड़ी की शर्मनाक हार से शिवसेना चिंतित है। वो बीएमसी चुनाव में अकेले दम पर बहुमत हासिल करने की प्लानिंग कर रही है। इस तरह उद्धव गुट की शिवसेना ने स्थानीय चुनावों में अलग रास्ते पर चलने का संकेत दे दिए हैं।

एआई इंजीनियर सुसाइड

दहेज उत्पीड़न के मामले में जो फंसता है वो कोर्ट के चक्कर लगाकर थक जाता है, पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता है और जब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं बचती तो सुसाइड कर लेता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष सिस्टम से इतना परेशान हो गया था कि उसने जिंदगी की बजाय मौत को चुना।

पुरुषों के हकों के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं जिनकी समाज में कभी बात ही नहीं होती, बरखा त्रेहन का कहना है कि पुरुषों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं, अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है।

शालिनी चौहान
नई दिल्ली

सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी द्वारा दर्ज किए गए झूठे 9 मामलों और 3 करोड़ रुपये की मांग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ये केस मिसाल है कि हमारा दहेज विरोधी कानून कितना क्रूर है, कैसे इसका दुरुपयोग हो सकता है और कैसे इस अंधे कानून ने न जाने कितने नौजवानों और उनके परिवारों को बर्बाद कर दिया। दहेज उत्पीड़न के मामले में जो फंसता है वो कोर्ट के चक्कर लगा लगाकर थक जाता है। पुलिस के आगे हाथ जोड़-जोड़ कर रोता रहता है और जब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं बचती तो सुसाइड कर लेता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष सिस्टम से इतना परेशान हो गया था कि उसने जिंदगी की बजाय मौत को चुना। दहेज का कानून इसलिए बनाया गया था कि महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाया जा सके। लेकिन अब किसी भी पारिवारिक विवाद में इस कानून का इस्तेमाल पति और उसके परिवार को फंसाने के लिए होता है। इसलिए बेंगलुरु में प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड से पूरा देश सन्न है। इंजीनियर के सुसाइड केस को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है। 34 साल के सुभाष बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। उन्होंने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा और वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने अपनी मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया की प्रताड़ना के साथ फैमिली कोर्ट की जज को भी जिम्मेदार बताया है। जिन्होंने कथित तौर पर केस सेटलमेंट के लिए उनसे 5 लाख रुपये की मांग की थी।

सुभाष की 5 साल पहले जौनपुर की निकिता सिंघानिया से शादी हुई थी और उनका एक 4 साल का बच्चा है। फैमिली कोर्ट ने उन्हें बच्चे के गुजारे के लिए पत्नी को हर महीने 40 हजार रुपये देने का आदेश दिया था। पत्नी निकिता सिंघानिया ने उनके और उनके वृद्ध माता-पिता व अन्य परिवार वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत 9 केस जौनपुर में दर्ज करा रखे थे। अतुल सुभाष बेंगलुरु नौकरी करते थे, लिहाजा मुकदमों की तारीखों पर उन्हें बेंगलुरु से जौनपुर के चक्कर लगाने पड़ते थे। अतुल सुभाष की मौत के बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग आक्रोश जता रहे और आरोप लगा रहे हैं तलाक अथवा भरण-पोषण के मामलों में कई बार अदालतें मनमाने तरीके से गुजारे भत्ते की रकम तय कर रही हैं। यह एक तरह से पुरुषों का उत्पीड़न है। देश में आक्रोश को देखते हुए उनकी मौत की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार की तहरीर पर बेंगलुरु के मराठहल्ली पुलिस स्टेशन में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया, उनके साले अनुराग सिंघानिया और उनकी पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश की एक न्यायिक अधिकारी का नाम भी तहरीर में शामिल है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 3(5) के तहत केस दर्ज कर लिया है। तहरीर में आशंका जताई गई है कि न्यायिक अधिकारी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं। गवाहों पर दबाव बना सकती हैं।

सुसाइड नोट के अंश?

अतुल सुभाष के सुसाइड नोट में सबसे महत्वपूर्ण न्याय की मांग है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि उनका उत्पीड़न करने वालों को दंडित नहीं किया गया, तो वे भविष्य में अन्य पुरुषों को परेशान करना जारी रखेंगे। सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे सभी मामलों की सुनवाई लाइव होनी चाहिए। इस देश के लोगों को मेरे मामले के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें कानूनी व्यवस्था की भयावह स्थिति तथा इन महिलाओं द्वारा कानून के दुरुपयोग के बारे में पता होना चाहिए। 'कृपया इस सुसाइड नोट और मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को मेरे बयान और सबूत के रूप में स्वीकार करें।' 'रीता कौशिक उत्तर प्रदेश में न्यायाधीश हैं। मुझे डर है कि वे दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर सकती हैं, गवाहों पर दबाव डाल सकती हैं और अन्य मामलों को भी प्रभावित कर सकती हैं। मेरे अनुभव के आधार पर, बेंगलुरु की अदालतें यूपी की अदालतों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक कानून का पालन करती हैं। मैं न्याय के हित में कर्नाटक में मामलों को चलाने और मुकदमा चलने तक उन्हें बेंगलुरु में न्यायिक और पुलिस हिरासत में रखने का अनुरोध करता हूं।' नीचे न्याय क्यों होता हुआ दिखाई देता है, इस पर निर्णय दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह पुरुषों पर भी लागू होगा।

मेरी पत्नी या उसके परिवार को मेरे शव के पास न आने दें, जब तक मेरे उत्पीड़कों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक मेरा 'अस्थि विसर्जन' मत करना, अगर कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि भ्रष्ट जज और मेरी पत्नी तथा दूसरे उत्पीड़क दोषी नहीं हैं, तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी नाले में बहा देना।

'मेरे बच्चे की कस्टडी मेरे माता-पिता को दीजिए जो उसे बेहतर मूल्यों के साथ पाल सकेंगे।' मेरी पत्नी या उसके परिवार को मेरे शव के पास न आने दें। जब तक मेरे उत्पीड़कों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक मेरा 'अस्थि विसर्जन' मत करना। अगर कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि भ्रष्ट जज और मेरी पत्नी तथा दूसरे उत्पीड़क दोषी नहीं हैं, तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी नाले में बहा देना। मेरे उत्पीड़कों को अधिकतम सजा दीजिए, हालांकि मुझे हमारी कानूनी व्यवस्था पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर मेरी पत्नी जैसे लोगों को जेल नहीं भेजा गया तो उनका हौसला और बढ़ेगा और वे भविष्य में समाज के अन्य बेटों पर भी झूठे मामले दर्ज कराएंगे। न्यायपालिका को जगाने और उनसे आग्रह करने के लिए कि वे मेरे माता-पिता और मेरे भाई को झूठे मामलों में परेशान करना बंद करें। इन दुष्ट लोगों के साथ कोई बातचीत, समझौता और मध्यस्थता नहीं की जाएगी तथा दोषियों को दंडित किया जाए। मेरी पत्नी को सजा से बचने के लिए केस वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाए, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करती कि उसने झूठे मामले दर्ज कराए हैं। शायद मेरे बूढ़े माता-पिता को अदालतों से औपचारिक रूप से इच्छामृत्यु की मांग करनी चाहिए अगर उत्पीड़न और जबरन वसूली जारी रहती है। आइए इस देश में पतियों के साथ माता-पिता को भी औपचारिक रूप से मार दें और न्यायपालिका के इतिहास में एक काला युग बनाएं। अब कथाएं सिस्टम द्वारा नियंत्रित नहीं होंगी। समय बदल गया है। मेरा अनुमान है कि मेरी पत्नी अब सहानुभूति पाने के लिए मेरे बच्चे को कोर्ट में लाना शुरू कर देगी, जो उसने पहले नहीं किया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मैं अपने बच्चे से न मिल सकूं। मैं कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि इस नाटक की अनुमति न दी जाए।

सिर्फ लड़कियों की सुनवाई

उनकी तस्वीरें, उनके लिखे सुसाइड नोट का एक-एक शब्द लोगों को रुला रहा है। इस सुसाइड के बाद पुरुषों के हकों के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं जिनकी समाज में कभी बात ही नहीं होती। बरखा त्रेहन का कहना है कि 'पुरुषों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं...ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं, अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल जैसे लाखों लड़के, लाखों पुरुष सुसाइड कर चुके हैं।' बरखा त्रेहन का कहना है कि 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया गया। सिस्टम फेल रहा। किस तरह से पक्षपात होता है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। दरअसल पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर ही एआई इंजीनियर अतुल ने पहले 90 मिनट का वीडियो बनाया, 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा फिर अपना जीवन समाप्त कर लिया। उनका केस जौनपुर में चल रहा था जहां ससुराल वाले रहते थे, अतुल मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। एक्टिविस्ट और फिल्ममेकर दीपिका भारद्वाज का कहना है कि 'मैं इसे सुसाइड नहीं कहूंगी, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान उन लोगों को झकझोरने के लिए दिया है जो शायद इस देश में पुरुषों की दुर्दशा को लेकर अंधे और बहरे हो चुके हैं।' अतुल अकेले नहीं हैं। इसकी सूची बहुत बड़ी है, जिन्होंने हाल में वीडियो बनाकर सुसाइड किया है, कई मामले ऐसे भी हैं जिन्होंने लाइव सुसाइड किया है। सोशल मीडिया पर लोग गुजारा भत्ता को लेकर अलग-अलग अदालतों की तरफ से सुनाए गए कुछ अजब-गजब फैसलों का भी जिक्र कर रहे हैं। पति बेरोजगार हो तब भी गुजारा भत्ता देना ही होगा। पत्नी अगर पति से ज्यादा कमाती है, तब भी उसे गुजारा भत्ता मिलेगा। यहां तक कि पति की मौत के बाद पत्नी अपने सास-ससुर से भी मैंटिनेंस का दावा कर सकती है। कभी-कभी कोई अदालत ऐसी भी टिप्पणी कर देती है कि भीख मांगों, कर्ज लो या चोरी करो, चाहे कुछ भी करो, मैंटिनेंस तो देना ही होगा। ये तो सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की बानगी भर है। इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी संजीदा नजर आई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुजारा भत्ता से संबंधित गाइडलाइंस निर्धारित कर दी हैं।

एससी ने तय की गाइडलाइंस

भरण-पोषण के मामलों में गुजारा भत्ता तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों के लिए 8 पॉइंट वाली गाइडलाइंस तय की है, जिसके आधार पर उन्हें गुजारे भत्ते की रकम तय करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि स्थाई गुजारा-भत्ता की राशि पति को दंडित न करे बल्कि पति-पत्नी के लिए एक सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के मकसद से तय की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइंस के बाद 'चाहे भीख मांगो, उधार लो या फिर चोरी करो, मैंटिनेंस तो देना ही होगा।' जैसे फैसलों पर लगाम लगने की उम्मीद है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2020 में "रजनीश बनाम नेहा" केस में भी गुजारे भत्ते को लेकर अदालतों के लिए गाइडलाइंस तय की थी। जिसमें देश की शीर्ष अदालत ने गुजारा भत्ता तय करने के लिए जो गाइडलाइंस बनाई थी उसमें 'पति और पत्नी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने।' 'भविष्य में पत्नी और बच्चों की बुनियादी जरूरतें को ध्यान रखने।' 'दोनों पक्षों की योग्यता और रोजगार की स्थिति को परखाने।' 'आय और संपत्ति के साधन को नजर अंदाज न करने।' 'ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर क्या है,' 'क्या उसने परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है?' 'जो पत्नी काम नहीं कर रही है, उसके लिए कानूनी लड़ाई के लिए उचित राशि कितनी हो।' 'पति की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई और गुजारा भत्ता के साथ अन्य जिम्मेदारियों का भी आकलन किया जाना आवश्यक है।' कोर्ट का कहना है कि गुजारा भत्ता की रकम कितनी हो, इसकी कोई तय गाइडलाइंस नहीं है। यह केस पर निर्भर है और केस टू केस अलग हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतें जब गुजारे भत्ते की राशि तय करें तो उन्हें किसी पिछले फैसले पर विचार करना चाहिए। मैंटिनेंस अमाउंट तय करते वक्त संबंधित पक्षों की स्थिति, आवेदक की जरूरत, प्रतिवादी की आय और संपत्ति, दावेदार की वित्तीय जिम्मेदारियों, संबंधित पक्षों की उम्र और रोजगार की स्थिति, नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण और बीमारी या अक्षमता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मैंटिनेंस से जुड़े आदेशों का पालन भी सिविल कोर्ट के फैसलों की तरह होना चाहिए। आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित पक्ष को हिरासत में लिए जाने से लेकर संपत्ति की जब्ती जैसी कार्रवाई हो। अदालतों के पास अधिकार होगा कि वह ऐसे मामलों में अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सके। ●

ये मोदी का भारत है ट्रूडो

भारत की कूटनीति की चर्चा आजकल विश्व पटल पर एक नजीर बनती जा रही है, इजराइल-फिलीस्तीन-हमास युद्ध हो या रूस-यूक्रेन युद्ध सभी को लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मात्र नेता हैं जो इन युद्धों को रुकवाने में सक्षम हैं।

प्रदीप डीएस भट्ट
लेखक, मेरठ

कहावत है जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आजकल ऐसा ही कुछ अंतरराष्ट्रीय पटल पर देखने को मिल रहा है। जिस भी देश के नेता को अपने देश में अपनी गिरती साख बचानी हो या विपक्ष का ध्यान भटकाना हो तो वह भारत से उलझ जाता है। देर सवेर ही सही भारत उसको ऐसी धोबी पछाड़ मारता है कि उस देश का नेता अच्छी भली सत्ता गवां देता है या अर्थ दंड का ऐसा झटका लगता है जिससे वह भारत के सामने सरेंडर कर अपनी जान बचाता है। अगर यकीन नहीं हो तो पाकिस्तान और मालदीव की हालात देख लें। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है तो उसकी स्थिति तो और भी ज्यादा दयनीय है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए वह अरसे तक हाथ पांव मारता रहा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। बैक डोर से हाथ-पांव जोड़े तब जाकर भारत ने उसे ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए एफएटीएफ को इशारा किया। किंतु पाकिस्तान तो पाकिस्तान है वो सुधरने से तो रहा। वैसे भी जो सुधर जाए उसे पाकिस्तान नहीं कहते हैं।

9-10 सितंबर, 2023 को जब भारत ने जी-20 का आयोजन किया था तब उसकी थीम थी 'वसुधैव कुटुम्बकम' यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इस सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे विश्व के 20 पावर फुल देशों के प्रतिनिधियों ने भारत की उत्कृष्टता के दर्शन भी किए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एवं रूस के राष्ट्रपति अपरिहार्य कारणों से इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विदाई के समय कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो विमान की खराबी के कारण तय समय के बाद भी भारत में रुके रहे। ऐसी स्थिति में मेजबान भारत ने उनकी समान्य से अधिक सहायता नहीं की। कारण मिस्टर ट्रूडो कनाडा में रह रहे सिख अलगाववादियों का पक्ष लेते रहे हैं। इस तरह भारत ने ट्रूडो को उनके अवांछनीय व्यवहार के लिए कनाडा में भी धोया और भारत में भी।

बैक डोर से हाथ-पांव जोड़े तब जाकर भारत ने उसे ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए एफएटीएफ को इशारा किया। किंतु पाकिस्तान तो पाकिस्तान है वो सुधरने से तो रहा। वैसे भी जो सुधर जाए उसे पाकिस्तान नहीं कहते हैं।

ट्रूडो की रेटिंग रसातल पर

पंजाब में रह रहे पंजाबियों की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि मुंडा कनाडा सैटल हो जाए या रैपर बन जाए। खैर कुछ दिनों पहले जस्टिन ट्रूडो को फिर खुजली मची और उन्होंने कनाडा में अपनी गिरती साख बचाने के लिए भारत पर फिर से बे-सिर पैर के आरोप लगा दिए जैसे कि निज्जर की हत्या में भारत की खुफिया ऐजेंसी रॉ के एक्स एजेंट शामिल हैं। यहां तक कह दिया कि हत्या भारत के लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है जिसे सूचनाएं रॉ ने मुहैय्या कराई हैं। मिस्टर ट्रूडो यहीं नहीं रुके वरन भारत के राजदूत सहित छह राजनयिकों को कनाडा की राजधानी से जाने के लिए कह दिया। भारत ने इस बार तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कनाडा में अपने राजदूत संजय वर्मा को भारत लौटने का आदेश तो दिया ही साथ ही भारत में कनाडा के छह राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का फरमान भी जारी कर दिया। निश्चित रूप से कनाडा ने भारत से इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी, सो जस्टिन ट्रूडो इस खबर से पूरी तरह बोखला गए। जल्द ही कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और वर्तमान रेटिंग के अनुसार ट्रूडो की रेटिंग रसातल की ओर अग्रसर है! कोढ़ में खाज वाली स्थिति तब पैदा हो गई जब लिबरल पार्टी ऑफ कैनेडा के प्रमुख ने ट्रूडो को स्वयं 28 अक्टूबर तक त्याग-पत्र देने के लिए कह दिया। ट्रूडो को ये झटका कुछ ज्यादा ही जोर से लगा।

कनाडा में भी तुष्टीकरण की राजनीति

जस्टिन ट्रूडो ने जब जून-2023 में कनाडाई नागरिक निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था तब अंतरराष्ट्रीय पटल पर काफी हो हल्ला मचा था। ये विषय अलग है कि कनाडा खुद भी निज्जर को आतंकवादी मानता रहा है, वरना क्या कारण रहे जो कनाडा ने उसकी हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगा रखा था। चूंकि बात चुनाव में वोटों की है तो जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में रह रहे लगभग 2.1 लाख सिखों के वोटों की दरकार है। जबकि सिखों से ज्यादा वहां अन्य भारतीय बसते हैं, जिनका वोट प्रतिशत सिखों से ज्यादा है। किंतु कनाडा भी तुष्टीकरण की राजनीति करता है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की स्थिति तब और खराब हो गई जब न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता जगमीत सिंह ने 2022 में जस्टिन ट्रूडो को दिया गया राजनीतिक समर्थन यह कहते हुए वापस ले लिया था कि वो यह समझौता तोड़ रहे हैं क्योंकि ट्रूडो बेहद कमजोर, स्वार्थी और एक महाभ्रष्ट नेता हैं। वोट की खातिर ट्रूडो कनाडा के हर छोटे बड़े गुरुद्वारे में सरोपा प्राप्त कर रहे हैं। आखिर क्यों? जगमीत सिंह चाहते हैं कि ट्रूडो निज्जर की हत्या में भारत को घसीटे, लेकिन ट्रूडो आज तक निज्जर की हत्या में कोई ठोस सबूत नहीं दे सके। यहां तक कि निज्जर का मृत्यु प्रमाण पत्र भी। जस्टिन ट्रूडो की दोगली नीति का एक उदाहरण और है। कनाडा में पाकिस्तानी कट्टरपंथीयों द्वारा हिंसक वारदातें की जाती हैं 2020 में एक बलूच महिला करीमा बलूच की हत्या कर दी गई। इसी कनाडाई पुलिस की रिपोर्ट है कि करीमा डूब कर मरी थी, इसी प्रकार एक बलूच पत्रकार की भी पाकिस्तानियों द्वारा हत्या कर दी गई और कनाडाई पुलिस ने उसे भी रफादफा कर दिया।

कनाडा-भारत का कारोबार?

भारत ने स्वतंत्रता के बाद जब अपना संविधान तैयार किया तो उसमें ये वाक्य कनाडा के संविधान से लिया था। 'संघवाद के केंद्र प्रसारक रूप जिसमें संविधान में केंद्र राज्यों से मजबूत होता है।' कनाडा की कुल आबदी 39,854,546 है यानी दुनिया की आबादी का लगभग 0.49 प्रतिशत। इसमें 15 लाख भारतीय हैं, जिनमें सिखों की जनसंख्या 2.1 लाख है। जनसंख्या के हिसाब से कनाडा विश्व का 38वां देश है जहां घनत्व प्रत्येक 4 पर 1 किलोमीटर है। लगभग 80 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। भारत की आईटी कंपनियों में से इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी एवं टेक महिंद्रा, कनाडा में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। जहां तक भारत से कनाडा के निर्यात का प्रश्न है तो भारत से फार्मास्यूटिकल उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, इस्पात, मोती, विद्युत उपकरण, कार्बनिक रसायन, रबड़, प्लास्टिक, चाय, कॉफी, ऑप्टिकल फाइबर, चिकित्सा उपकरण के साथ डेयरी उत्पाद निर्यात करता है। वहीं कनाडा से भारत दाल, वुड्स पल्प, न्यूजप्रिंट, पोटाश, ऐसबेस्टस, आइरन, स्क्रैप, कॉपर खनिज व केमिकल आयात करता है। दोनों देशों के बीच 2023-24 में 8.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। आज जब युद्ध से ज्यादा व्यापार महत्वपूर्ण है तब कनाडा क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर उतारू है। भारत तो कनाडा की जगह कई और देश से व्यापार बढ़ा लेगा, लेकिन क्या कनाडा भारत से ये सब अफोर्ड कर सकता है? 145 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत की कितनी खपत है वो सभी देश भलीभांति समझते हैं किंतु कनाडा फिर भी खांम-खां पंगा ले रहा है।

भारत के लिए राष्ट्र सर्वोपरि

अभी हाल ही में ट्रूडो ने खुद माना कि उन्होंने निज्जर हत्याकांड में जो आरोप भारत पर लगाए हैं उनके सबूत के तौर पर उनके पास कुछ नहीं है। इस पर भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा को धोबी पछाड़ दिया तो वह रोता हुआ 'फाइव आइज' यानी अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और कनाडा के खुफिया गठबंधन की शरण में गया और शिकायत की कि मोदी ने जोर से मारा है। बाकी देश तो शांत रहे किंतु अमेरिका ने जरूर पन्नू के विषय में थोड़ा हल्ला किया कि सीआरपीएफ का एक अफसर पन्नू की हत्या कराने की साजिश में शामिल है। पहले तो ये एक साजिश है, जो पूरी नहीं हुई। भारत सरकार ने इस मामले में आवश्यक जानकारी अमेरिका के साझा भी की, लेकिन इस बीच ये मसला सोशल मीडिया में वायरल हो गया और फिर उस अफसर के फेवर में जिस तरह की मुहिम चली उससे भारत सरकार भी अचंभित रह गई। अब कनाडा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वो भारत से कैसे पेश आए जिससे बिगड़ी बात बन जाए। भारत की कूटनीति की चर्चा आजकल विश्व पटल पर एक नजीर बनती जा रही है। इजराइल-फिलीस्तीन-हमास युद्ध हो या रूस-यूक्रेन युद्ध, सभी को लगता है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी एक मात्र नेता हैं जो इन युद्धों को रुकवाने में सक्षम हैं। भारत किसी एक पक्ष में कभी नहीं रहा 2014 के बाद जिस तेजी से स्थितियों ने करवट ली है उसमें भारत अब राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत का अक्षरशः पालन करता है। एक तरफ वह अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर क्वाड समूह बनाता है जिसका उद्देश्य चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है। क्वाड का गठन चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीतियों को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। वहीं भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, भारत के अलावा साऊथ अफ्रीका है। इन चार देशों की जीडीपी का विश्व में 43 प्रतिशत हिस्सा है। विश्व के तेजी से बदलते पॉवर ऑर्डर को देखते हुए हर देश इसमें शामिल होकर अपने को सुरक्षित करना चाहता है। पाकिस्तान इसका सदस्य बनने के लिए छटपटा रहा है किंतु उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिली है।

- **सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका के उकसावे में खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका की कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि भारत सरकार उसे मरवाना चाहती है इसलिए कोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित भारत को समन जारी करे।**
- **भारत व कनाडा के बीच 2023-24 में 8.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, आज जब युद्ध से ज्यादा व्यापार महत्वपूर्ण है तब कनाडा क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर उतारू है, भारत तो कनाडा की जगह कई और देश से व्यापार बढ़ा लेगा, लेकिन क्या कनाडा भारत से कुछ अफोर्ड कर पाएगा?**

टूडो जोकर से ज्यादा कुछ नहीं

कनाडा में अक्टूबर, 2025 में चुनाव होने हैं। जिस तरह से ट्रूडो की लोकप्रियता घट रही है उससे उन्हें आभास हो गया है कि वो अगले चुनाव में सत्ता से बाहर होने वाले हैं। खैर मसला ये है कि ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर कनाडा एक जिम्मेदार देश है उसे किसी भी देश पर अनाप शनाप आरोप लगाना शोभा नहीं देता। आरोप लगाने से पहले उसे सोचना चाहिए। क्योंकि जरा सी गलत बयानी से अंतरराष्ट्रीय संबंध बिगड़ जाते हैं, जिन्हें फिर से बनाने में दशकों लगते हैं। ताजा उदाहरण भारत-चीन सीमा विवाद से समझा जा सकता है, जहां चीन की एक गलती से जून 2020 से जारी तनाव अब जाकर थोड़ा कम हुआ है। जहां तक कनाडा का मसला है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब से ट्रूडो सत्ता में आए हैं उनके बयानों से भारत ही नहीं वरन अमेरिका, चीन के अलावा कई और देश भी असहज हुए हैं। ये बात अलग है कि बिना अमेरिका की सह के ट्रूडो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। अमेरिका सबका है और किसी का नहीं। आजकल अमेरिका गा रहा है कि भारत-अमेरिका संबंध हिमालय की तरह बढ़ रहे हैं जबकि सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका के उकसावे में खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका की कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें उसने कहा कि भारत सरकार उसे मरवाना चाहती है इसलिए कोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित भारत को समन जारी करे। कनाडा की पुलिस भी ट्रूडो से परेशान है वर्ना क्या कारण है कि निज्जर की हत्या में वो जो भी टिप्पणी करती है उसमें विरोधाभास होता है। कनाडाई पुलिस अपनी भद्द कैसे पिटवा रही है उसका उदाहरण है कि इसी साल जून में कनाडाई पुलिस ने रहस्योद्घाटन किया कि 1985 में हुए बम विस्फोट में एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया था। विस्फोट में 300 लोग मारे गए थे जिसकी जांच कनाडाई पुलिस अब भी कर रही है। निश्चित रूप से ये हास्यास्पद है कि कनाडाई पुलिस 39 वर्षों में भी अंतरराष्ट्रीय हादसे की जांच में नाकाम रही है। ये जांच कब तक चलती रहेगी इसका कोई उत्तर कनाडाई पुलिस के पास नहीं है।
कनाडाई पुलिस 39 साल में एक जांच नहीं कर पाई, फिर उसने एक वर्ष में कैसे पता लगा लिया कि निज्जर की हत्या में भारत, रॉ और लॉरेंस विश्नोई गैंग शामिल है? हद तो तब हो गई जब ट्रूडो ने कनाडाई संसद में निज्जर की हत्या पर एक मिनट का मौन रखने का ऐलान कर दिया। जब उनकी ही सरकार के सदस्यों ने विरोध किया तो कार्यक्रम कैंसिल किया। भई या तो आप पहले गलत थे या अब। अब इस बात की समझ आ जाए तो उसे ट्रूडो थोड़े ही कहेंगे? भाई उत्तर प्रदेश पुलिस से ही कुछ सीख लेते या भारत सरकार को रिक्वेस्ट करके उत्तर प्रदेश पुलिस से एक टीम बुला लेते तो कनिष्क और निज्जर हत्याकांड की जांच 39 दिनों में निपट जाती, सबूत के तौर पर यूपी पुलिस दोनों घटना में शामिल लोगों के पैरों पर गोली मारती और कनाडाई पुलिस को सौंप देती। हां अगर कोई साजिशकर्ता ज्यादा उछलता तो उसकी गाड़ी भी पलट जाती। वैसे भी भारत की नजर में ट्रूडो एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं हैं जो विश्व पटल पर अपनी जोकरी से सबका मनोरंजन करते रहते हैं।

फाइव आइस बनाम थ्री आइस

मैं पहले ही ऊपर बता चुका हूं कि अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने फाइव आइस ग्रुप बना रखा है जिसका काम दूसरे देशों की जासूसी कर सूचना आपस में शेयर करना है। अब भारत, चीन, ब्राजील, रूस और साउथ

अफ्रीका भी वही काम करेगा, जो फाइव आइस करती है। इसे थ्री आइस नाम दिया गया है। भारत की तरफ से कनाडा को 26 अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया है, किंतु कनाडा ने अभी तक सिर्फ 5 अनुरोध ही स्वीकारे हैं। गुरजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, अर्शदीप सिंह एवं लखविंदर सिंह लांड़ा सहित कई आतंकियों के प्रत्यार्पण के केस पिछले दस सालों से कनाडा में पेंडिंग हैं, कनाडा उन पर कब एक्शन लेगा कोई नहीं जानता। भारत जहां अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध चाहता है वहीं पड़ोसियों को भारत की तरक्की की आग में जलने से फुर्सत नहीं है। पाकिस्तान का ध्येय वाक्य ही है कि हम नहीं सुधरेंगे, पाकिस्तान के विभाजन के बाद बंग्लादेश बना, लेकिन भारत के साथ ये दोनों ही देश गद्दारी करने से बाज नहीं आए। आप इसे यूं समझ सकते हैं, जैसे भारत एक हार्ड वेयर है जिसके अंदर सनातन का सॉफ्टवेयर बनकर ऊपर से ही आया है जबकि बाकी जबरदस्ती उस सॉफ्टवेयर को अनस्टाल कर अपने बनाए सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं। परिणाम सामने है इसलिए भारत की आवश्यकता है कि वह अन्य देशों के साथ गठजोड़ कर अंदर बाहर सब कुछ साधने की कोशिश करता रहे। हां अगर कनाडा को ये मुट्ठीभर चरमपंथी ज्यादा भाते हैं तो बेहतर हो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के एक हिस्से को खालिस्तान घोषित कर दें।

बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जो वीभत्सता हुई उस पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर विरोध किया उससे अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों में एक क्लियर संदेश गया कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना ही भारत के हित में है।

निज्जर हत्याकांड के सबूत नहीं

जस्टिन ट्रूडो की गलतियों का पिटारा जिसमें से न जाने कब कौन सा कबूतर निकल आए जो रायता फैला दे। पिछले वर्ष यूएई के खिलाफ कनाडा ने कुछ आपत्तिजनक कह दिया लिहाजा यूएई ने कनाडा में पढ़ने वाले अपने छात्रों को वापस बुला लिया जिससे कनाडा की जीडीपी को क्षति हुई। 2024 के आंकड़ों के अनुसार 13 लाख भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। जिसमें से 3.37 लाख अमेरिका एवं 4.27 कनाडा गए। अब सोचिए अगर भारत अपने 4.27 लाख छात्रों को वापस बुला ले तो क्या होगा? कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त रहे संजय कुमार वर्मा के अनुसार हर वर्ष सुनहरे भविष्य के लिए भारतीय छात्रों का उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना आम बात है। किंतु शिक्षा पूरी होने पर नौकरी न मिलने पर छात्र चाय समोसे, पकौड़े बेच रहे हैं। ऐसा इसलिए कि वहां के शिक्षण संस्थानों में अमूमन हफ्ते में एक दिन क्लास लगती है, लिहजा छात्र पार्ट टाईम काम करते हैं लेकिन जब शिक्षा पूरी होने पर सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलता तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। 2022 से ओहोयो में पदस्थ उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा कहते हैं कि हर हफ्ते दो बच्चों के शव भारत भेजे जाते रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक गंभीर विषय है जिस पर भारतीय माता-पिता को चिंता करने की आवश्यकता है। बेहतर होगा कि वो बच्चों की हायर एजूकेशन के साथ ये भी सुनिश्चित करें कि बच्चे जिंदा भी रहें। इस मुद्दे पर मोदी सरकार को चिंता के साथ चिंतन की आवश्यकता है। ये बात हमें समझ आती हैं, किंतु ट्रूडो को नहीं आती। तो फिर ऐसे शख्स का पद पर रहने का क्या औचित्य है। इसलिए उनकी पार्टी उनसे सख्त नाराज है।

ट्रंप की जीत भारत के हित में

आज भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है उस अनुपात में उसके दुश्मनों की संख्या बढ़नी भी तय है। जो सामने तो भारत का गुणगान करते हैं किंतु पीठ पीछे प्रगति पथ में बाधा खड़ी करने में लगे रहते हैं। खैर मेरी छटी इंद्री मुझे सचेत कर रही है और एक संभावना भी बता रही है कि हो सकता है निज्जर की हत्या पाकिस्तान की बदनाम इंटेलिजेंट ऐजेंसी आईएसआई द्वारा की गई हो? हो सकता है इसका इशारा अमेरिका ने दिया हो? क्योंकि अमेरिका भविष्य में चीन, रूस और भारत की तिकड़ी के साथ आने से अपने आपको असहज महसूस कर रहा है। हो सकता है मेरा अंदाजा सही हो। वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि पानी में आग लगा कर जमालो दूर खड़ी तमाशा देखे। भारत-कनाडा एक दूसरे का सिर फोड़ने में व्यस्त रहें और अमेरिका-पाकिस्तान को मोहरा बना कर अपना उल्लू सीधा करता रहे। अंत में अब जब 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का परिणाम घोषित हुआ तो जैसी उम्मीद थी कमला हैरिस चुनाव हार गई और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राजनीति में अपनी

डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में जैसे ही सत्तानशी होंगे कई देशों की आफत तय है, इसका नमूना तुलसी गेबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त करना है, ट्रंप के राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही चीन, कनाडा और पाकिस्तान जैसे देशों में शोक छा गया था।

जिजीविषा के दम पर पुनः ट्रंप साबित हुए। अगर अमेरिकी राजनीति पर एक दृष्टि डालें तो पाएंगे कि ऐसा पहली बार हुआ जब कोई राष्ट्रपति गैप देकर विजयी हुआ। इन चार वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोपों का दौर चला। किंतु डोनाल्ड तो डोनाल्ड ठहरे आखिर जीत कर ही माने। डोनाल्ड की जीत के लिए जितने यज्ञ अनुष्ठान भारत में हुए उससे डोनाल्ड की भारत में लोकप्रिता को देखकर कोई भी नेता गर्व कर सकता है। वैसे इसका कारण भी है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बांग्लादेश में हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जो वीभत्सता हुई उस पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर विरोध किया उससे अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों में एक क्लियर संदेश गया कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना ही भारत के हित में है। वैसे भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस का कार्यकाल ऐसा नहीं रहा जिससे भारतीय समुदाय उनकी तरफ आकर्षित होता। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में जैसे ही सत्तानशी होंगे कई देशों की आफत आनी तय है। इसका नमूना उन्होंने तुलसी गेबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है। ट्रंप के राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही चीन, कनाडा, पाकिस्तान जैसे देशों में शोक छा गया था। रही सही कसर तुलसी, रामास्वामी की नियुक्ति से कनाडा एकदम बैकफुट पर आ गया। जस्टिन हैरान परेशान हैं इसलिए भारत के साथ हुए विवाद को कवर करने के उद्देश्य से 10 नवंबर को अर्श दीप उर्फ अर्श दीप डल्ला को आनन-फानन में गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रैंपटन के हिंदू मंदिर में हुए खालिस्तनियों के हमले में शामिल कट्टरपंथी इंद्रजीत गोसाल को भी गिरफ्तार किया, किंतु बाद में छोड़ भी दिया। भारत ने भी देरी किए बिना अर्श दीप के प्रत्यर्पण की मांग कर जस्टिन को असहज कर दिया। इसके साथ जब कि 31 अक्टूबर को ही कनाडा की जासूसी ऐजेंसी सीईसी द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के अलावा भारत को भी इस सूची में रखा था जिनसे कनाडा को खतरे की बात कही गई थी। जहां तक भारत का प्रश्न है तो ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मोदी-ट्रंप की दोस्ती 2029 तक किस किस को पानी पिलाने वाली है कोई नहीं जानता बस अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं भी लगा रहा हूं आप भी लगाइए ।

राहुल गांधी फिर फेल

लोकसभा चुनाव में बढ़त मिलने से कांग्रेस लीडर सांसद राहुल गांधी बोखला गए और दावा करने लगे थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, लेकिन हरियाणा व महाराष्ट्र के नतीजों ने तो कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन का कॉन्फिडेंस तोड़ा है।

म

अरुण कुमार
मुंबई

हाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत और महा विकास अघाड़ी की करारी हार ने कांग्रेस को एक बार फिर से अस्तित्व बचाए रखने के लिए विवश कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, महाराष्ट्र में महायुति के खिलाफ जो नैरेटिव सैट किया जा रहा था वो औंधे मुंह गिर गया। देश की सबसे बूढ़ी पार्टी कांग्रेस को अब नए सिरे से पुनरुत्थान की जरूरत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कई मायनों से महत्वपूर्ण था। मसलन इस चुनाव ने साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में अजित पवार की एनसीपी असली एनसीपी है, 2024 में यह भी साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी (शरद) का मुस्लिम तुष्टीकरण ले डूबा। महाराष्ट्र चुनाव ने ये भी साबित कर दिया कि अब शरद पवार का राजनीतिक जलवा नहीं रहा। भाजपा ने अकेले दम पर 132 सीटें जीत कर जता दिया कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत लगाकर भी उसके विजयी रथ को रोकने में नाकाम है। पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र के नतीजों ने लोकसभा चुनावों में हासिल की गई इंडिया गठबंधन की बढ़त को भी ठंडा कर दिया। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संविधान को बचाने और जाति जनगणना कराने के दावों की भी हवा निकाल दी। कुल मिला कर राहुल गांधी एक बार राजनीति में फेल हो गए।

कॉन्फिडेंस किसका टूटा?

राहुल गांधी हाथ में लाल किताब लेकर कहते थे कि 'संविधान और आरक्षण खतरे में है।' 'चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाति जनगणना कराकर ही रहूंगा' जैसे जुमलों का लोकसभा चुनाव में लोगों ने खूब समर्थन किया था। लोकसभा चुनाव में बढ़त मिलने से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी बोखला गए और दावा करने लगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। लेकिन हकीकत में कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन का टूटा है। महाराष्ट्र में भाजपा की भारी जीत में महिला मतदाताओं की अहम भूमिका रही है। कांग्रेस ने दीवार पर लिखी भाजपा की इबारत पढ़ने की कोशिश नहीं की, जबकि इससे पहले मध्य प्रदेश में भाजपा ने लाडली बहना योजना के साथ उसे पटखनी दी थी। हालांकि कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में महालक्ष्मी योजना का वादा किया था, जिसमें 3,000 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया गया था, लेकिन कांग्रेस इसे मतदाताओं तक विश्वास के साथ पहुंचाने में नाकाम रही। सुप्रिया सुले और प्रियंका गांधी वाड्रा की जोड़ी इस महालक्ष्मी योजना के जरिए थोड़ा बहुत लाभ उठा सकती थीं, लेकिन महा विकास अघाड़ी भाजपा विरोधी मतदाताओं का ध्यान अपनी योजना की ओर खींचने में विफल रहा। इसके विपरीत भाजपा अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में लाने में भी सफल रही, जो आगे की लड़ाई में कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकती है।

लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर कांग्रेस का रवैया लापरवाह हो गया। कांग्रेस को अति आत्मविश्वास हो गया था कि वो अब आगे बढ़ रही है, लेकिन यही हरियाणा और महाराष्ट्र में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई।

विपक्ष का चुनाव प्रबंधन फ्लॉप

कांग्रेस भले ही हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़े, लेकिन हकीकत में भाजपा और कांग्रेस सहित बाकी विपक्ष के बीच चुनावी रणनीति में भारी अंतर है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद भाजपा ने पहले दिन से ही अपनी कमजोरियों की समीक्षा की और जहां भी कमजोरी नजर आई उस पर काम शुरू कर दिया था। लोकसभा चुनाव की रणनीति में जहां भी गड्ढा मिला उसे पाटने का काम किया। इसके विपरीत लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर कांग्रेस का रवैया लापरवाह हो गया। कांग्रेस को अति आत्मविश्वास हो गया था कि वो अब आगे बढ़ रही है, लेकिन यही हरियाणा और महाराष्ट्र में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। हरियाणा में तो कांग्रेस लड़ाई मे नजर भी आ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में तो वो मैदान में खेलते हुए दिखाई भी नहीं दी। जबकि चुनावी मैदान में आक्रामकता से लड़ने के लिए भाजपा तैयारी के साथ उतरी। भाजपा एक के बाद एक सधे कदमों और पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ी। जिसका कांग्रेस के पास कोई काट नहीं था। लिहाजा सत्तारूढ़ गठबंधन के आक्रामक हमलों से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को खुद ही जूझना पड़ा।

प्रचार में भी फिसड्डी रही कांग्रेस

महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 108 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसका केंद्रीय नेतृत्व जीत के लिए मैदान में गंभीरता से नहीं उतरा, सिर्फ रस्म अदा करने के लिए राहुल गांधी 7 और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 9 रैलियां मात्र 16 रैलियां कीं। वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने तीन रैलियां और एक रोड शो किया। जब तक प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका प्रचार अभियान महिला मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में लाने पर केंद्रित हो सकता था, लेकिन उनकी कोई भूमिका ही नहीं रही, क्योंकि वो 13 नवंबर तक वायनाड में अपनी पहली चुनावी लड़ाई लड़ती रहीं। इसके विपरीत भाजपा ने महायुति सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना को नियंत्रित करने के लिए असंतुष्ट मतदाताओं को धीरे-धीरे अपने पक्ष में करने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद से ही अभियान शुरू कर दिया था। इस सबसे शायद शिवसेना (उद्धव), एनसीपी (शरद) और कांग्रेस बेखबर रही। कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा भी नहीं था जो महा विकास अघाड़ी के अभियान को मजबूती दे सकता और उसे एक मजबूत विकल्प बना सकता। जबकि भाजपा ने कल्याणकारी योजनाओं, विकास, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों का चुनावी गुलदस्ता बनाकर जनता के सामने पेश किया। वैसे भी महा विकास अघाड़ी ने भाजपा के मुद्दों का मुकाबला करने या उसे खारिज करने का ठोस प्रयास भी नहीं किया। चाहे वह बेरोजगारी, ग्रामीण संकट, कृषि संकट, मुद्रास्फीति या भष्ट्राचार हो, इन्हें लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास कोई ठोस प्लानिंग ही नहीं थी।

कांग्रेस का वोट बैंक खिसका

महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव की तरह राहुल गांधी के सबसे मजबूत चुनावी नारे 'संविधान बचाओ', 'जाति जनगणना' के नारे पर ही केंद्रित था, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुछ बढ़त दिलाने वाले ये नारे महाराष्ट्र के मतदाताओं पर बेअसर रहे। राहुल गांधी ने नागपुर और कोल्हापुर में चुनाव के दौरान दो संविधान सभाएं कीं, लेकिन जब नतीजे आए तो यहां कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। यानी 'संविधान बचाओं और जाति जनगणना' की आक्रामक मांग पर भी कांग्रेस मतदाताओं को आकर्षित करने में नाकाम रही। इसके विपरीत आरएसएस और भाजपा के 'एक हैं तो सेफ हैं' और 'बटेंगे तो कटेंगे' के नारे को आगे बढ़ाने में सफल रहे। कांग्रेस अपनी वैचारिक लड़ाई में महाराष्ट्र के मतदाताओं को मनाने में विफल रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के 'गुजरात बनाम मुंबई' और 'अडानी समूह' द्वारा महाराष्ट्र के कारोबार को गुजरात ले जाने का मुद्दा भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ, खासकर मुंबई में मिली करारी हार को इसका पैमाना माना जा सकता है। चाहे विदर्भ हो या मराठवाड़ा कांग्रेस ने अपना अहम वोट बैंक भी खो दिया है। प्याज किसानों से लेकर सोयाबीन किसानों तक, किसान कांग्रेस का महत्वपूर्ण वोट बैंक होता था।

- **भाजपा ने महायुति सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना को नियंत्रित करने के लिए असंतुष्ट मतदाताओं को धीरे-धीरे अपने पक्ष में करने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद से ही अभियान शुरु कर दिया था।**
- **'संविधान बचाओं और जाति जनगणना' की आक्रामक मांग पर भी कांग्रेस मतदाताओं को आकर्षित करने में नाकाम रही, इसके विपरीत आरएसएस और भाजपा के 'एक हैं तो सेफ है' और 'बटेंगे तो कटेंगे' के नारे को आगे बढ़ाने में सफल रहे।**

कांग्रेस द्वारा किसानों के मुद्दे उठाना और उनके लिए आंदोलन करना इस किसान मतदाता का दिल जीत सकता था, लेकिन पार्टी अपने क्षत्रपों के बीच अंदरूनी कलह और नेतृत्व की होड़ में उलझी रही, जो अपने ही इलाकों तक सीमित थे। नतीजतन यह महत्वपूर्ण वोट बैंक भी उसके हाथ से खिसक गया।

हिंदुत्व का कार्ड चला

'एक हैं तो सेफ हैं' और 'बटोगे तो कटोगे' जैसे नारों ने दलितों और मराठों को भी भाजपा की तरफ देखने के लिए विवश कर दिया। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता चुनाव हार गए। इनमें से ज्यादातर मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण कराड दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा के डॉ. अतुल बाबा सुरेश भोसले से हार गए। तेओसा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राजेश श्रीरामजी वानखड़े ने कांग्रेस की दिग्गज यशोमति चंद्रकांत ठाकुर को हराया। इसी तरह संगमनेर विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना (शिंदे) उम्मीदवार अमोल खताल ने कांग्रेस के दिग्गज बालासाहेब थोराट को बड़े अंतर से हराया, जबकि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले मामूली अंतर से किसी तरह जीत हासिल कर पाए। कांग्रेस नेताओं के बीच अहंकार और पेशेवर प्रतिद्वंद्विता के कारण नेता अपनी ढ़पली बजाकर अपना अलाग लाप रहे थे। क्योंकि राहुल गांधी का नाना पटोले की ओर झुकाव यह संदेश दे रहा था कि वे सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। इससे नेताओं के बीच क्लेश और बढ़ गया, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अपनी योजना पर अड़े रहे और अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं से संपर्क छोड़ दिया। इस तहर पटोले पार्टी के चुनाव अभियान में अकेले पड़ गए।

मजबूरी का गठबंधन

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महा विकास अघाड़ी के पास सीएम का कोई चेहरा नहीं था। महा विकास अघाड़ी के नेता सिर्फ परिस्थितियों के कारण गठबंधन से बंधे हुए लग रहे थे। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता था, रैलियों और रोड शो की एक बड़ी सीरीज से चुनाव में मतदाताओं के बीच उपस्थिति दर्ज की जा सकती थी, लेकिन अगाढ़ी की 'गाड़ी' कछुआ गति से चलती दिखाई दी और नतीजे आते आते उसके 'टायर पंचर हो गए।' महा विकास अघाड़ी का शुरुआत से ही यह उतार-चढ़ाव भरा सफर रहा। इसमें सौहार्द और एकता गायब थी। हर पार्टी ने अपने-अपने पैबंदों को दुरुस्त करती रही। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी जुबानी जंग देखने को मिली। करीब तीन दर्जन सीटों पर बागी एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। उद्धव ठाकरे खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराने के लिए तड़पते रहे, लेकिन कांग्रेस को लग रहा था कि वो सत्ता में आएगी तो सीएम उसका होगा, इसलिए नाम पटोल ज्यादा उछल रहे थे। अंत में नतीजे आए और भाजपा और उसके सहयोगियों को जिस तरह की जीत मिली वो अप्रत्याशित थी। क्योंकि महा विकास अघाड़ी के घटक दल शिवसेना (उद्धव) सबसे ज्यादा 20 सीटें जीत पाई, बाकी कांग्रेस और एनसीपी (शरद) की जो हालत हुई उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। महाराष्ट्र के इन चुनाव नतीजों ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर मोहर लगा दी है। ●

फर्जी संगठनों से सावधान

सबसे बड़ी चुनौती तो धोखाधड़ी करने वाले संगठनों की पहचान करना है? इन संगठनों की पहचान करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वे आमतौर पर बहुत आकर्षक फर्जी वेबसाइटों और विज्ञापनों के माध्यम से अपने आपको पेश करते हैं।

आजकल शिक्षा और प्रतिस्पर्धा की दुनिया में कई ऐसे संगठन सामने आ रहे हैं, जो बिना किसी सरकारी मान्यता या पंजीकरण के विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, किताबें प्रकाशित कर रहे हैं और अवार्ड बांट रहे हैं। ये संगठन न केवल छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि समाज में एक गलत संदेश भी फैला रहे हैं। ऐसे धोखाधड़ी करने वाले संगठनों के बारे में जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। किंतु सबसे बड़ी चुनौती तो इन धोखाधड़ी करने वाले संगठनों की पहचान करना है? इन संगठनों की पहचान करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वे आमतौर पर बहुत आकर्षक फर्जी वेबसाइटों और विज्ञापनों के माध्यम से अपने आपको पेश करते हैं। इनके द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएं अक्सर बिना किसी मान्यता के होती हैं और विजेताओं को दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र तथा पदक किसी भी सरकारी या प्राधिकृत संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। आम तौर पर ये संस्थाएं लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपना नेटवर्क बनाएं हुए है और भोली भाली नवांकुर प्रतिभाओं को ठग रही हैं। ऐसे भी संगठन समाज में हैं जो सौंदर्य प्रतियोगिता के नाम पर महिलाओं का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता कराने वाले संगठन मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड तथा मॉडलिंग में करियर बनाने का सपना दिखाते हैं और मोटी रकम वसूलकर छोटी-मोटी प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देते हैं। इस तरह की प्रतियोगिताओं में युवतियां आसानी से शिकार बन जाती हैं। ऐसे ही युवाओं को मिस्टर का खिताब देकर फिल्मी दुनिया का हीरों बनाने का ख्वाब दिखाया जाता है। इनसे पहले आवेदन फार्म के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, फिर ऑडिशन के नाम पर फीस ली जाती है, ऑडिशन में ज्यादा से ज्यादा युवाओं का सलेक्शन किया जाता है, फिर ट्रेनिंग व ड्रेल के नाम पर जेब ढ़ीली की जाती है। इसके बाद प्रतियोगिता में विजेता वही बनता है जिसे आयोजक चाहते हैं। इस तरह की इवेंट कराने वाली संस्थाओं का अपना सिंडीकेट है। जो जिले और मंडल से लेकर प्रदेश और देश भर में काम करता है। इवेंट कराने वाली इन संस्थाओं के अवार्ड की मान्यता सिर्फ इनके सिंडीकेट द्वारा कराई जाने वाली प्रतियोगिताओं तक सीमित हैं। इसके बाहर विजेताओं के अवार्ड की कोई कीमत नहीं है। लिहाजा सौंदर्य प्रतियोगिता के नाम पर लूटने वालों की पहचान करना भी आवश्यक है।

अमित पाठक शाकद्वीपी
साहित्य संगम बुक्स

अवार्ड बेचने का धंधा

ऐसी बहुत सी संस्थाएं प्रतियोगिता करा रही हैं जो बिना पंजीकरण के कार्य कर रही हैं। ये संगठन न तो उद्यम पंजीकरण में हैं और न ही जीएसटी पोर्टल पर, फिर भी फर्जी तरीको से निम्न गुणवत्ता की पुस्तक प्रकाशित कर रही है या अन्य प्रतिस्पर्धाओं के नाम पर ठगी कर रही हैं। कुछ सस्थाएं तो बिना किसी आयोजन के भी प्रशस्ति पत्र बांट रहें हैं। इस तरह की सस्थाएं अमूमन अत्याधुनिक नामों से वेबसाइट्स बनाती हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता। फ्री पोर्टल या ब्लॉग बना कर ये अपने आपको बेहतर और वास्तविक बताने का भरपूर प्रयास करते हैं। जबकि ऐसा करने के पीछे केवल लोगों को बहला कर उनसे आर्थिक लाभ लेना एक मात्र उद्देश्य होता है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों से ये संस्थाएं हजारों रुपये वसूली हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अवार्ड देने के नाम पर हजारों रुपये की वसूली करती हैं जबकि किसी गली मोहल्ले में भी इनकी कोई वास्तविक पहचान नहीं होती न ही कोई मुख्यालय या प्रमाणिक पता सार्वजनिक होता है। इनके प्रमाण पत्र पर भी कोई ऐसा विवरण नहीं होता कि इनकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

ऐसे भी संगठन हैं जो सौंदर्य प्रतियोगिता के नाम पर महिलाओं का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, सौंदर्य प्रतियोगिता कराने वाले संगठन मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड तथा मॉडलिंग में करियर बनाने का सपना दिखाते हैं और मोटी रकम वसूलकर छोटी-मोटी प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देते हैं।

इन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती। हर दूसरे दिन कोई नई प्रतियोगिता नए नामों से कराते रहते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप समूह बना कर भोली-भाली स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को मंच संचालक बना कर ये स्वयं छिपकर सारा लाभ उठाते हैं। इन्हीं सब तरीकों से ये अपने जीवन यापन के लिए लोगों को मूर्ख बना कर कर धन जुटाने में लगे हैं। कुल मिलाकर ये संस्थाएं अवार्ड बेचने का धंधा कर रही हैं। जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है।

शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव

धोखाधड़ी करने वाले संगठनों का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी शिक्षा प्रणाली पर पड़ रहा है। ये संगठन छात्रों को भ्रमित करते हैं, जिससे वे अपना समय और पैसे बर्बाद करते हैं। कई बार ये संगठन ऐसे प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जिन्हें भविष्य में नौकरी के लिए महत्वपूर्ण मानकर उपयोग किया जा सकता है, जबकि वास्तव में ये प्रमाण-पत्र किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा नहीं दिए गए होते। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य युवाओं का आर्थिक और मानसिक शोषण करना होता है। ऐसे ठग युवाओं के असुरक्षित भविष्य का फायदा उठाते हैं। प्रतिस्पर्धाओं के नाम पर लाखों रुपये की वसूली करते हैं, जबकि इनके द्वारा दिए गए अवार्ड्स का कोई मूल्य नहीं होता। बहुत से भोले भाले छात्र तो अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए इन संगठनों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब ये संगठन नकली प्रमाण-पत्र और पदक वितरित करते हैं, तो समाज में एक गलत संदेश फैलता है कि शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। छात्र समझते हैं कि बिना मेहनत किए भी वे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, जो एक अत्यंत हानिकारक धारणा है। यह शिक्षा के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

धोखाधड़ी के खिलाफ कड़े कानून

भारतीय संविधान के अनुसार, धोखाधड़ी और धोखाधड़ी करने वाले संगठनों के खिलाफ कड़े कानून हैं, लेकिन इन संगठनों का पता लगाना और उन्हें कानूनी कार्रवाई की जद में घसीटना बहुत चुनौतीपूर्ण है। अक्सर ये संगठन अपने पते और पहचान को छिपाने में सफल हो जाते हैं। धोखाधड़ी से बचने के लिए युवा कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। मसलन युवाओं और उनके अभिभावकों को इन संगठनों के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि बिना मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र और पदक का कोई मूल्य नहीं होता। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ अभियान चला कर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करे। शिक्षण संस्थानों को भी ऐसे संगठनों के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, ताकि छात्र सही और गलत जानकारी में अंतर कर सकें। सामाजिक संगठनों के सदस्यों को भी इन धोखाधड़ी करने वाले संगठनों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और एकजुट होकर इनका सामना करना चाहिए।

कोई संस्था यदि अपना कोई पंजीकरण संख्या साझा नहीं करती है तो समझिए कि वो अवैध है जिससे आपको आर्थिक क्षति पहुंच सकती है, यदि पंजीकरण संख्या मिलता है तो उसका वेरिफिकेशन पोर्टल पर डाल करें ताकि पता चल सके कि उक्त संस्था को कौन-कौन से अधिकार है।

कैसे बचें धोखाधड़ी से ?

किसी भी आकर्षित करने वाले नाम की संस्था से जुड़ते समय संस्था के संचालक से पहला प्रश्न उनकी पात्रता और पंजीयन पर पूछा जाए। उनसे उनकी सरकार की भिन्न-भिन्न इकाइयों से प्राप्त मान्यताओं को भली भांति जांच की जाए और परखा जाए। कोई संस्था यदि अपना उद्यम पंजीकरण संख्या या जीएसटी संख्या नहीं साझा करें तो समझिए कि वह अवैध संस्था है जिससे आपको आर्थिक व मानसिक क्षति पहुंच सकती है। एक बार पंजीकरण संख्या प्राप्त होने पर उस उद्यम का वेरिफिकेशन पोर्टल पर अथवा जीएसटी पोर्टल पर डाल कर यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त संस्था को प्रकाशन या मुद्रण या अन्य कौन-कौन से अधिकार प्राप्त है। यदि चीजे अनुकूल हो तभी किसी संस्था में धनराशि जमा कराएं। धनराशि जमा करने के लिए हमेशा यूपीआई एप्स का प्रयोग करें ताकि रसीद सुरक्षित रहें और धोखाधड़ी की अवस्था में साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकें। ऑनलाइन पैसे लेकर पुस्तक न भेजने या किसी भी प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं करने या अवैध प्रशस्ति-पत्र जारी किए जाने पर इसकी सूचना कंज्यूमर फोरम या साइबर सुरक्षा पोर्टल पर साझा करें। कोशिश करें कि संस्था के प्रमुख का नाम और नंबर आपके पास होना चाहिए। पुस्तक प्रकाशन की स्थिति में उसका आईएसबीएन संख्या प्राप्त करें। मैगजीन में प्रकाशन पर उसका आईएसएसएन संख्या अवश्य चैक करें। संस्था का एमएसएमई में उद्यम पंजीकरण संख्या अवश्य चैक करें। संस्था का जीएसटी पोर्टल में जीएसटी पंजीकरण संख्या अवश्य देखें। इस तरह की सावधानियां बरत कर किसी भी धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।

प्रतियोगिता के नाम पर ठगी

यूथ स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसा नाम पढ़कर या सुनकर लगेगा कि ये कोई राष्ट्रीय स्तर की संस्था होगी, लेकिन ये संस्था फर्जी है और इसके पदाधिकारियों के खिलाफ राजस्थान के सीकर थाने में पुलिस केस दर्ज है। इस संस्था पर नेशनल खेल प्रतियोगिताओं के नाम पर सात राज्यों के 872 बच्चों से 12 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी का आरोप है। यूथ स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया युवा व खेल मंत्रालय केंद्र सरकार व इंडियन ओलंपिक संघ अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर भी इस संस्था ने आठ साल पहले खाटूश्याम में फर्जी तरीके से नेशनल खेल प्रतियोगिता करा दी थी। 12 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी करने वाली स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सात बच्चों को नेपाल में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में खिलाने के लिए 20-20 हजार रुपये हड़प लिए। लेकिन किसी को खेलने के लिए नेपाल नहीं भेजा गया। इस तरह देश की प्रतिभाओं को लूटने वालों का सिंडिकेट हर जहग है। लिहाजा इनसे बचाव के लिए सवाधानी ही सबसे बेहतर तरीका है।

ध्याणियों को मां राजराजेश्वरी का आशीर्वाद

9 माह की ये यात्रा चमोली, रुद्रप्रयाग, पंचकेदार, पंचबदरी, पंच प्रयाग समेत कई जिलों के गांवों का भ्रमण करेगी, मां राजराजेश्वरी चंडिका देवी की डोली सगर व सिमली गांव की विवाहित बेटियों और बहनों की ससुराल जाएगी, जहां देवी उनकी कुशलक्षेम पूछकर आशीर्वाद देंगी।

उत्तराखंड के चमोली जिले के सिमली और सगर गांव के बीच से 100 साल बाद मां राजराजेश्वरी चंडिका देवी की देवरा यात्रा निकलना एक ऐतिहासिक आयोजन है। जो इस क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए तो विशेष महत्व रखती है। पिछली बार यह यात्रा 1924 में निकली थी और इस बार 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी के अवसर पर सिमली गांव से इसे प्रारंभ किया गया है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य मां राजराजेश्वरी चंडिका की डोली को विभिन्न गांवों और धार्मिक स्थलों पर ले जाना है। यात्रा का मकसद देवी के आशीर्वाद को लोगों तक पहुंचाना और उनके घर-परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करना है। खासतौर पर यह यात्रा सिमली व सगर गांव की ध्याणियों (विवाहित बहन-बेटियों) की ससुराल जाकर उनकी कुशलक्षेम पूछने की परंपरा निभाती है। 100 वर्ष बाद पुनः आयोजित हो रही यह यात्रा 9 माह तक चलेगी और पंचकेदार, पंचबदरी और पंच प्रयाग सहित अन्य प्रमुख स्थलों का भ्रमण करेगी। यात्रा जिस भी आबादी वाले क्षेत्र से गुजर रही है वहां भव्य स्वागत की तैयारी पहले से ही कर ली जाती है। स्वागत के साथ ही पूजा अर्चना कर श्रद्धालु अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों में देवी के प्रति गहरी आस्था स्पष्ट नजर आती है। यात्रा समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह बिष्ट का कहना है कि यह यात्रा 9 माह में चमोली, रुद्रप्रयाग, पंचकेदार, पंचबदरी और पंच प्रयाग समेत कई अन्य जिलों के गांवों का भ्रमण करेगी। मां राजराजेश्वरी चंडिका देवी देवरा यात्रा के दौरान देवी की डोली सगर व सिमली गांव की विवाहित बेटियों और बहनों के ससुराल भी जाएगी, जहां देवी उनकी कुशलक्षेम पूछकर आशीर्वाद देंगी।

कमल कपूर
वरिष्ठ पत्रकार

चंडिका देवी मंदिर काली को समर्पित

राजराजेश्वरी चंडिका देवी मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है । यह चमोली जिले के कर्णप्रयाग के पास सगर व सिमली गांव के बीच पिंडर नदी के तट पर पीपल के प्राचीन पेड़ के नीचे स्थित है। चंडिका देवी का यह मंदिर देवी काली को समर्पित है। इस मंदिर को राजराजेश्वरी चंडिका देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यह उत्तराखंड के प्राचीन मंदिर से एक है लिहाजा यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु चंडिका देवी के दर्शन कर सुख-समृद्धि का वरदान मांगते हैं। पहले इस मंदिर में बकरे और भैंसों की बलि दी जाती थी, लेकिन अब नारियल चढ़ाए जाते हैं। इस मंदिर का धार्मिक महत्व भी बहुत है। कर्णप्रयाग की यात्रा के दौरान पर्यटक इस पवित्र व प्राचीन मंदिर के दर्शन करने जरूर जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चंडिका देवी काली का सबसे उग्र रूप हैं, लेकिन वे सबसे अधिक देखभाल करने वाली और दयालु मां भी हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थनाएं वास्तव में सच हो जाती हैं। पर्यटन के लिहाज से भी सिमली का चंडिका देवी मंदिर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां का वातावरण सुंदर और शांत है। यहां पूरे साल मौसम सुहावना रहता है, इसलिए यहां साल भर पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। लेकिन चंडिका देवी मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई तक होता है।

गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी

उत्तराखंड को देवी-देवताओं की भूमि माना जाता है। यहां भगवान शिव और शक्ति साक्षात विराजमान माने जाते हैं। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड में शिवालयों के साथ देवी के कई शक्तिपीठ हैं, जो अपनी पौराणिक मान्यताओं के साथ आध्यात्म के लिए श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। ऐसा ही मां राजराजेश्वरी चंडिका देवी का प्राचीन सिद्धपीठ है। चूलागढ़ पर्वत पर स्थित सिद्धपीठ चंडिका देवी मंदिर अपनी वास्तुशैली के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर में विराजमान देवी स्थानीय ग्रामीणों की आराध्य देवी भी हैं। राज राजेश्वरी चंडिका देवी को गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी भी माना जाता है, लिहाजा जहां-जहां राजाओं ने अपना राज्य विस्तार किया, उन क्षेत्रों में मां राजराजेश्वरी का मंदिर स्थापित किया। श्रीनगर गढ़वाल के देवलगढ़, कीर्तिनगर के रानीहाट में भी त्रिपुरा सुंदरी स्वरूप राजराजेश्वरी मंदिर हैं। राजराजेश्वरी मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि इस मंदिर में 10 महाविद्या में से एक त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप विराजमान है। लोकमान्यता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार 14वीं शताब्दी में टिहरी रियासत पर राज करने वाले कनकवंश के राजा ने किया था। चूलागढ़ में राजा निवास करते थे, यहां मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक विशाल चबूतरा है। कहते हैं कि चबूतरे पर ही राजा सत्यसिंध की सभा लगती थी जिसमें अहम फैसले लिए जाते थे। इस मंदिर में पूजा-अर्चना का कार्य राजा ने मान्द्रा गांव के नौटियाल वंश को सौंपा था। जबकि मंदिर की सेवा के लिए गडारा गांव के चौहान परिवार को चुना था। तब से वर्तमान तक यहां पूजा अनुष्ठान का इन्हीं दो परिवार के लोग करते हैं। साथ ही यहां ढोल, दमाऊं बजाने का कार्य 'गड़वे' अर्थात माता के दास करते हैं। इसी मंदिर में लाखों वर्ष पुराना एक खड्ग भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मां दुर्गा देवासुर के साथ युद्ध के दौरान जब आकाश मार्ग से यहां से गुजर रही थीं, तो उनका अज्ञात धातु से बना एक शक्ति शस्त्र खड्ग (तलवार जैसा हथियार) चूलागढ़ की पहाड़ी पर गिर गया था, जो आज भी मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। भारतीय पुरातत्व विभाग भी इस खड्ग को लाखों वर्ष पुराना मानता है। इस घटना का जिक्र स्कंदपुराण के केदार खंड में भी किया गया है।

मां दुर्गा देवासुर के साथ युद्ध के दौरान जब आकाश मार्ग से यहां से गुजर रही थीं, तो उनका अज्ञात धातु से बना एक शक्ति शस्त्र खड्ग (तलवार जैसा हथियार) चूलागढ़ की पहाड़ी पर गिर गया था, जो आज भी मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है।

ध्याणियों को साक्षात दर्शन

देवभूमि उत्तराखंड में चमोली जिले के सिमली में पिंडर नदी के सुरम्य तट पर विराजमान राजराजेश्वरी चंडिका देवी भी अपने भक्तों और ध्याणियों को साक्षात दर्शन देने निकली हैं। चंडिका देवी 7 सितंबर को गर्भगृह से बाहर भक्तों के बीच आई और 12 अक्टूबर को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ब्रह्ममबंधन, दुर्गा सप्तशती पूजा, अभिषेक के बाद देवरा यात्रा पर निकल गई। देवरा यात्रा में देवी चंडिका का पहला प्रथम विश्राम रतूड़ा गांव में हुआ। रतूड़ा गांव से चंडिका देवी का प्राचीन रिश्ता है। रतूड़ा गांव में ही देवी चंडिका की सहधर्मिणी देवियां नागिना या नैणी देवी, नंदा देवी, ज्वालपा देवी, सरस्वती देवी समेत कई अन्य देवी देवताओं का प्रवास भी है। लिहाजा इस यात्रा में चंडिका देवी और क्षेत्र के तमाम कुल देवी-देवताओं का भावपूर्ण महामिलन भी 100 वर्षों बाद श्रद्धालुओं को देखने को मिला। सिमली का चंडिका देवी मंदिर यानी राजराजेश्वरी चंडिका माता मंदिर शक्ति की प्रमुख देवी काली माता को समर्पित है। यहां के जिस पैतो मंदिर में इस समय चंडिका देवी विराजमान हैं, वह स्थान मूल रूप से गोविंद मठ है, जिसमें गोल गोविंद, गुणसाई, चंडिका देवी और राज राजेश्वरी देवी की मूर्तियां विराजमान हैं। यहां कुल 4 बड़े मंदिर हैं, जबकि कुछ छोटे मंदिर भी हैं। ऐरवाले (देवी के पश्वा) और ब्रह्मावा सुंदर गांव, जाख, सेनू और सिमली गांव से आते हैं। जबकि बालदेव (बाल रूप में गोविंद भगवान के पश्वा) कंडवाल गांव के होते हैं। गोल गोविंद भगवान के बाल रूप में यात्रा के साथ कंडवाल गांव के पंडित ले जाते हैं और वे सिमली गांव की तरफ से ऐरवाले रूप में इस यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी ऐरवाले नृत्य करते हैं। लेकिन कंडवाल गांव के लोग नृत्य नहीं करते हैं। चार गांवों-जाख, सुंदर गांव, सिमली और सेनू के प्रधान इस यात्रा में बड़ी भूमिका में रहते हैं।

यह यात्रा पिछली बार 1924 में निकली थी और इस बार 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी के अवसर पर सिमली गांव से इसे प्रारंभ हुई है, यात्रा का उद्देश्य मां राजराजेश्वरी की डोली को धार्मिक स्थलों पर ले जाने व लोगों तक आशीर्वाद पहुंचाने से है।

चंडिका देवी नदी में बहकर सिमली पहुंची

चंडिका देवी मंदिर से जुड़े पंडित अवकाश प्राप्त अध्यापक महानंद गैरोला कहते हैं कि कई साल पहले रतूड़ा गांव के पंडित ब्रह्म मुहूर्त में स्नान लिए अपने गांव की तलहटी में बहने वाली पिंडर नदी जाया करते थे। एक दिन रतूड़ा गांव के किसी पंडित को वहां नदी किनारे चंडिका देवी की काष्ठ मूर्ति मिली। जो बगौली की ओर से बहकर आई थी। पंडित मूर्ति को लेकर अपने गांव रतूड़ा पहुंचे। रतूड़ा के तत्कालीन ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी हुई कि वह मूर्ति चंडिका देवी की है तो गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव वालों ने पंडित से देवी की मूर्ति को वापस वहीं पिंडर नदीं में विसर्जित करने के लिए कहा। क्योंकि हमारे देश में पौराणिक काल से ही देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को समुद्र, नदी, ताल-तालाबों के पवित्र जल में विसर्जित करने की प्राचीन परंपरा रही है, उसी तरह रतूड़ा के पंडित ने भी चंडिका देवी की मूर्ति को पिंडर नदी में ससम्मान विसर्जित किया और घर लौट आए। यानी चंडिका देवी को रतूड़ा गांव में स्थान नहीं मिला। पंडित द्वारा प्रवाहित की गई देवी की काष्ठ प्रतिमा नदी में बहकर सिमली में पिंडर के तट पर गोल गोविंद, गुणसाई मंदिर पर किनारे लग गई। इस तरह भगवती चंडिका देवी नदी में बहकर सिमली गांव में पिंडर नदी के तट पर पहुंची तो देवी, सेनू, जाख, सुंदर गांव और सिमली के लोगों के सपने में आई। देवी ने उनको सिमली के मंदिर में स्थापित करने को कहा देवी ने ये भी कहा कि यहां बलि का भोग भी होगा। तब से मां चंडिका यहीं विराजमान है। इससे पहले इस मंदिर में गोल गोविंद के रूप में भगवान विष्णु की साधारण पूजा होती थी। बाद में यहां चंडिका देवी का मंदिर बना। यहां देवी का मुंह पश्चिम की तरफ किया गया है। फिर कई सालों बाद पुजारी के सपने में आकर देवी ने भ्रमण को कहा उस समय लोग खेती-बाड़ी में व्यस्त रहते थे और उनके पास देवी के साथ भ्रमण के लिए लंबा समय नहीं था। इसलिए लोगों ने देवी की बात मानी और भ्रमण के लिए पैता किया गया। पैता मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें देवी आज भी रह रही है। हर बार भ्रमण पर जाने से पहले देवी कुछ महीनों या सालों तक पैता मंदिर में रहती हैं। पैता मंदिर का मुंह भी पश्चिम दिशा की तरफ है। पैता गढ़वाली बोली-भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ किसी पूर्व निर्धारित और सुनिश्चित यात्रा पर जाने से पहले यात्रा का सामान पेटी बांधकर किसी विशेष स्थान पर सुरक्षित रखने से होता है। ●

प्रेरक कथा

क्या नकल करना उचित या अनुचित?

हम अपनी व्यक्तिगत विशिष्ट शैली का विकास करने की बजाय दूसरे सफल व्यक्तियों की नकल करने का अधिक प्रयास करते रहते हैं, कई बार दूसरे सफल व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास ही हमारे स्वाभाविक विकास में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है।

सीताराम गुप्ता
पीतमपुरा, दिल्ली

पाश्चात्य विचारक एमर्सन ने कहा है कि 'इमिटेशन इज सूइसाइड' अर्थात अनुकरण करना आत्महत्या के समान है। वैसे अनुकरण या नकल करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक क्रिया है। सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण अथवा नकल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम केवल स्वयं के अनुभवों या प्रयोगों से कितना सीख पाएंगे? जवाब मिलेगा बहुत कम। आयुर्विज्ञान का क्षेत्र हो या अभियांत्रिकी का क्षेत्र सैद्धांतिक व तकनीकी ज्ञान के साथ इंटर्नशिप के महत्व को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। यह भी एक प्रकार से अनुकरण द्वारा ही सीखने की प्रक्रिया है। अनुकरण अथवा नकल द्वारा हम आसानी से दूसरों के अनुभवों का लाभ उठाकर अधिक से अधिक सीख सकते हैं, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में नकल करना भी हमारे लिए या किसी के लिए अच्छा नहीं। अब परीक्षाओं को ही ले लीजिए। परीक्षाएं जीवन की कसौटी होती हैं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती ही कही जा सकती है कि आजकल परीक्षाओं के दौरान ही सबसे ज्यादा नकल करना आम बात हो गई है। कमजोर विद्यार्थी पास होने के लिए तथा सामान्य विद्यार्थी अधिक अंक पाने के लिए नकल का सहारा लेने से नहीं चूकते। विद्यार्थी ही नहीं अन्य व्यक्ति भी नकल के मामले में उनसे कम नहीं हैं। कोई किसी की दिनचर्या की नकल करने का प्रयास करता है, तो कोई किसी की जीवन शैली की नकल करने का। कोई किसी के केश विन्यास की नकल कर रहा है तो कोई किसी के कपड़ों-जूतों की। अपराध, आतंक, भ्रष्टाचार व अनैतिक कार्यों में लिप्त लोग तो नकल के मामले में सबसे आगे पाए जाते हैं। मिर्जा 'गालिब' का एक शेर है...।

हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे,
कहते हैं कि 'गालिब' का है अंदाजे-बयां और।

- **बदकिस्मती ही कही जा सकती है कि आजकल परीक्षाओं के दौरान ही सबसे ज्यादा नकल करना आम बात हो गई है, कमजोर विद्यार्थी पास होने के लिए तथा सामान्य विद्यार्थी अधिक अंक पाने के लिए नकल का सहारा लेने से नहीं चूकते।**
- **हर व्यक्ति के अंदर एक सर्जक, एक कलाकार छुपा होता है, लेकिन क्योंकि हम अपनी कलात्मकता को प्रकट करने या अपने भावों को व्यक्त करने की अपनी व्यक्तिगत विशिष्ट शैली से अपरिचित होते हैं, अतः हम हमेशा ही सामान्य बने रहते हैं।**

अर्थात दुनिया में और भी कई बहुत अच्छे सुखनवर (कवि) हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि 'गालिब' का वर्णन करने का तरीका या शैली और ही है। वह सबसे अलग है, अद्वितीय है और यही अंदाजे-बयां अथवा बयान का अनोखापन मिर्जा 'गालिब' को उर्दू का सबसे बड़ा शायर बना देता है। हर व्यक्ति के अंदर एक सर्जक, एक कलाकार छिपा होता है, लेकिन क्योंकि हम अपनी कलात्मकता को प्रकट करने या अपने भावों को व्यक्त करने की अपनी व्यक्तिगत विशिष्ट शैली से अपरिचित होते हैं। अतः हम हमेशा ही सामान्य बने रहते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत विशिष्ट शैली का विकास करने की बजाय दूसरे सफल व्यक्तियों की नकल करने का अधिक प्रयास करते रहते हैं। कई बार दूसरे सफल व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास ही हमारे स्वाभाविक विकास में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। प्रश्न उठता है कि नकल करना कहां तक उचित या अनुचित है? यह अच्छी बात है अथवा खराब? कम से कम परीक्षाओं में नकल करना तो अनुचित और खराब बात ही है। इसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं। जब हम नकल करके उत्तीर्ण होते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हममें योग्यता नहीं है। जिसका परिणाम ये होता है कि जब हम वास्तविक जीवन में कर्म के क्षेत्र में उतरते हैं तो सफलता नहीं मिलती। हमारा अज्ञान न केवल मानसिक रूप से परेशान करता रहता है अपितु व्यावहारिक रूप में भी बाधाएं खड़ी करता रहता है। बार-बार लोगों से सुनने को मिलता है कि रिश्वत दे कर पास हुए थे या नकल करके डिग्री हासिल की है। उस समय मन में आता है कि काश हमने नकल करने की बजाय मेहनत से पढ़ाई कर ली होती, लेकिन 'अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत।'

फिल्मों का समाज पर प्रभाव

फिल्मी दुनिया का तो हर वर्ग वो चाहे किशोर हों, युवा हो, अधेड़ हो, स्त्री अथवा पुरुष ही क्यों न हो, सभी पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। फिल्मों की हर चीज हमारे जीवन पर प्रभाव छोड़ती है। फिल्मों की रील लाइफ ही नहीं रीयल लाइफ भी हमारे सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। इसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव सोसाइटी पर पड़ रहे हैं, लेकिन अच्छे कम और बुरे प्रभाव ज्यादा असर कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया के नकल के प्रभाव से न केवल साहित्य, संस्कृति व कलाओं का घोर बाजारीकरण या व्यवसायीकरण हुआ है अपितु नैतिक मूल्यों, जीवन मूल्यों व संबंधों की गरिमा का भी ह्रास हुआ है। जहां फिल्मी दुनिया की नकल का दुष्प्रभाव नहीं है वहां हर क्षेत्र में मौलिकता देखी जा सकती है। जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व मौलिकता है। वास्तव में नकल मौलिकता की शत्रु है। जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो मौलिकता का बड़ा महत्व है। मौलिकता में नवोन्मेष होता है, सर्जनात्मकता होती है। जीवन में उन्नति के लिए नवोन्मेष तथा सर्जनात्मकता दोनों ही अनिवार्य हैं। **अनुकरण अथवा नकल नवोन्मेष तथा** सर्जनात्मकता दोनों का ही गला घोंट देते हैं। मौलिकता का ये अर्थ भी नहीं है कि हम नयेपन के नाम पर ऐसी ऊल-जलूल हरकतें करें जो हमें संकट में डाल सकती है अथवा जिनसे समाज व राष्ट्र कमजोर हो। वहीं मौलिकता ग्राह्य हो सकती है जिससे हमारे विकास के साथ हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास भी संभव हो सके।

मौलिकता में एक आकर्षण होता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कितने कलाकार हैं जिन्होंने दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन अथवा अन्य महान अभिनेताओं की नकल करके फिल्म इंडस्ट्री में अपना स्थान बनाया है? शायद एक भी नहीं। जो लोग इनकी नकल करके दिखाते हैं वे लोगों का सस्ता मनोरंजन करने वाले दोयम दर्जे

फिल्मों की रील लाइफ ही नहीं रीयल लाइफ भी हमारे सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, इसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव सोसाइटी पर पड़ रहे हैं, लेकिन अच्छे कम और बुरे प्रभाव ज्यादा असर कर रहे हैं।

के मिमिक्री कलाकार ही होते हैं। जो सचमुच महान कलाकार होते हैं वे अपनी नकल भी नहीं करते अपितु अपनी कला की शैली में वैविध्य उत्पन्न करने के प्रयास में लगे रहते हैं।

अच्छाई की नकल कर सकते हैं

जो दूसरों की नकल करते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और न उनका अनुकरण अथवा अनुसरण ही करता है। मौलिकता में न केवल एक आकर्षण होता है अपितु उसका अनुकरण भी किया जाता है। यदि आप में मौलिकता है तो लोग आपसे बात करेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। ये आपको भी अच्छा लगेगा कि लोग आप में रुचि ले रहे हैं। जो दूसरों के रहन-सहन, खानपान व कपड़ों-जूतों अथवा हेयर स्टाइल आदि की नकल करते हैं लोग उनको नकलची बंदर कहकर न केवल उनका मजाक उड़ाते हैं बल्कि उनसे दूर भी रहने का प्रयास करते हैं। यदि कोई हमारी उपेक्षा करता है अथवा हमारा मजाक उड़ाता है तो ये हमारे लिए सबसे दुख और शर्म की बात होती है। अब सवाल ये कि क्या नकल करना अच्छी बात हो सकती है? जी हैं नकल करना अच्छी बात भी हो सकती है यदि हम केवल अच्छी बातों की नकल करें। नकल ही करनी भी हो तो अच्छे लोगों की अच्छी बातों की नकल करनी चाहिए। यदि हमें वास्तव में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना है तो गांधी जी की नकल करनी चाहिए जिसमें कोई बुराई नहीं। हर व्यक्ति, हर समाज व हर राष्ट्र में कुछ न कुछ अच्छाइयां व कुछ न कुछ बुराइयां होती ही हैं। इसलिए नकल करनी ही है तो अच्छाइयों की कीजिए, बुराइयों की नहीं। अपने विरोधियों अथवा प्रतिद्वंद्वियों की भी अच्छाइयों की नकल करना हमारे हित में होगा। नकल करने में ये महत्वपूर्ण नहीं कि किस व्यक्ति की नकल की जा रही है बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि किन आदतों, कुशलताओं, कला अथवा सिद्धांतों की नकल की जा रही है। नकल तरक्की के लिए हो बेईमानी या दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। कहा गया है कि नकल के लिए भी अक्ल की आवश्यकता होती है। इसी वाक्य में नकल करने अथवा नकल न करने का पूरा दर्शन छिपा है। सामान्यतः लोग इसका ये अर्थ निकालते हैं कि नकल, चीटिंग, पायरेसी अथवा बेईमानी के लिए अक्ल की जरूरत होती है। जो जितना अक्लमंद होता है वह उतनी ही अच्छी तरह से नकल, चीटिंग, पायरेसी अथवा बेईमानी करने में सक्षम होता है और लाभांवित भी होता है। यह धारणा ही मिथ्या है। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है इसका सीधा सा अर्थ है कि जो जितना अक्लमंद होता है वह उतनी ही अच्छी तरह से जानता है कि किसकी नकल करनी चाहिए और कितनी तथा किसकी नकल नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। जिसमें ऐसा विवेक उत्पन्न हो जाता है वह सही व्यक्ति अथवा सिद्धांत की नकल करता है न कि चीटिंग, पायरेसी अथवा बेईमानी करता है। इसे आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि परिवार में बच्चे अपने सभी नित्य कर्मों को बड़ों के अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। पशुओं के बच्चे पैदा होने के कुछ समय बाद ही कुलांचे भरने लगते हैं, वहीं मनुष्य का बच्चा लगभग एक साल का होने पर ही अनुकरण के द्वारा चलना सीखता है। अगर किसी बच्चे को परिवार या समाज से अलग रख दिया जाए, तो वह किसी का भी अनुकरण नहीं कर सकेगा। लिहाजा वो असहाय और अज्ञानता की स्थिति में ही रह जाएगा। शिशु को किसी भी क्रिया को सीखने के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं होती, वह केवल अन्य लोगों का अनुकरण कर सीखता है। अनुकरण के द्वारा ही हम अपनी मातृभाषा सीख पाते हैं। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की जीवन-शैलियां देखकर उनकी नकल करना चाहते हैं। केवल अनुकरणीय का अनुकरण कीजिए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए।

दिल्ली में सांसों का संकट

आखिर दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली की जनता खुद इसके लिए जिम्मेदार है, प्रदूषण का स्तर भले ही 'एयर क्वालिटी इंडेक्स,' (एक्यूआई) में मापा जाता हो, लेकिन दिल्ली में 'पॉलिटिकल पॉल्यूशन इंडेक्स' (पीक्यूआई) तो सारी सीमाएं तोड़ कर बेकाबू हो चुका है।

ओमप्रकाश मंजुल
पूरनपुर पीलीभीत

मुफ्त की बिजली, पानी और सवारी के चक्कर में दिल्ली बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। शायद अब ये दिल्ली वालों की समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि दिल्ली की फिजा में इस समय दमघोंटू हवा हावी है। लेकिन मजाल है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इसकी जिम्मेदारी ले ले। इतिहास गवाह है कि पिछले 11 वर्षों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे, अब आतिशी मार्लेना सीएम हैं। भले ही दिल्ली का सीएम बदल गया हो, लेकिन कुछ नहीं बदला है तो वो है, भाजपा की केंद्र सरकार पर आरोप लगाना तथा दिल्ली के एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे जैसे परंपरागत आरोप। बरसात में दिल्ली में पानी भरता है, तो हरियाणा जिम्मेदार होता है। यमुना में गंदगी आती है तो इसके लिए यूपी और हरियाणा दोनों जिम्मेदार होते हैं। 2022 से पहले दिल्ली में जब वायु प्रदूषण होता था तो पंजाब में पराली जलाने से होता था। 2022 से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है लिहाजा दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण के लिए दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना अब यूपी, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार तक को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में दम घोंटने वाली हवा पर कैसे काबू किया जाए, इसका न तो दिल्ली की आतिशी सरकार और न ही केंद्र सरकार कोई हल निकाल रही है बल्कि एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर टाइम पास कर रहे हैं और दिल्ली की जनता प्रतिबंध पर प्रतिबंध झेल रही है। मसलन डीजल पेट्रोल के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। निर्माण कार्य नहीं होंगे, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब बंद रहेंगे, दफ्तरों का टाइम बदल दिया गया। दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, दूसरे राज्यों की रोडवेज बसों पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली की जनता सिर्फ प्रतिबंधों के लिए वोट देती है? शायद दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान ही नहीं करना चाहती, वो सिर्फ मुफ्त की रेबड़ी बांट कर सत्ता में बने रहना चाहती है, लेकिन ये बहानेबाजी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। दिल्ली की जनता को अब और बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि दो महीने बाद ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काम करने के बजाये सीएम आतिशी मार्लेना सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं। उन्हें समझना चाहिए कि बयानबाजी से प्रदूषण कम नहीं होता बल्कि और ज्यादा फैलता है।

दिल्ली दुनिया की टॉप प्रदूषित सिटी

दीपावली से अब तक दिल्ली की धुंध (स्मॉग) दिल्ली के साथ दूरदर्शन पर भी छाई हुई है। इस जहर से दिल्ली एक दमघोंटू-गैसचैंबर बन चुका है। दिल्ली में लोगों का अंदर-बाहर, सर्वत्र जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हर किसी के जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए दिल्ली की जनता खुद जिम्मेदार है? इससे भी बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली में 'पॉलिटिकल पॉल्यूशन इंडेक्स' (पीक्यूआई) सारी सीमाएं पार कर बेकाबू हो चुका है। हालांकि प्रदूषण का स्तर एक्यूआई में मापा जाता है, यानी 'एयर क्वालिटी इंडेक्स', जो सबसे गंभीर स्तर को पार कर चुका है। इस धुंध की घुटन से सर्वाधिक मरण दिल, अस्थमा, सांस, एलर्जी और आंखों के रोगियों का होता है। छात्रों के स्कूल-कालेज बंद हो जाते हैं, जैसा फिलवक्त हो रहा है। एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में खुले में पड़े प्रतीक्षारत दूर-दराज से आए मरीजों तथा उनके तीमारदार भी इस जहर का कहर सहने को अभिशप्त हैं। दिल्ली की धुंध की भयंकरता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि आज बिना सिगरेट पिए ही हर व्यक्ति की नाक से लगभग 30 सिगरेटों का धुआं शरीर में जाकर जहर घोल रहा है। धुआं, धुआंमापक यंत्र यानी स्मॉग मीटर सर्वोच्च रीडिंग की अति पार कर चुका है। यानी खतरनाक से भी गंभीर खतरनाक रीडिंग पर सूई घूम रही है। वैज्ञानिकों ने इसे सामान्य के सापेक्ष लगभग 20 गुना अधिक बताया है। अभी इसके और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि वायु-प्रदूषण बढ़ने वाला अधिकांश समय अभी आगे आने वाला है। आलम यह है कि 'देश का दिल' कही जाने वाली, राजधानी दिल्ली आज दुनिया का सर्वाधिक भयंकर प्रदूषित शहर बन चुका है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु प्रदूषण की 6 श्रेणियां मानता है। इनमें सर्वाधिक घातक श्रेणी को ,'सबसे अधिक गंभीर श्रेणी' नाम दिया गया है। दिल्ली न केवल इस सबसे अधिक गंभीर श्रेणी में है, वरन दुनिया के पीएम-10 का लेवल औसत 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होता है, लेकिन दिल्ली पीएम-10 का स्तर 399.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच कर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन चुका है।

आरोपबाजी में बीते 10 साल

दिल्ली की जनता को निशुल्क या कम शुल्क में शुद्ध हवा-पानी देने का वादा और दावा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निकट और धुंधली दृष्टिवश निर्मित धुंध के इस साम्राज्य को वे पड़ोसी-हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा पराली और पुवाल जलाने को कारण बताते हैं। खुद दीवाली, छठ पूजा और वर्ष भर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमानत मिलने की खुशी में पटाखे और फुलझड़ियां जला कर खुशी का इजहार कर वोट बटोरने की जुगत लगाते रहते हैं। जबकि बकौल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय उक्त प्रांतों से कुल मिलाकर लगभग 20 प्रतिशत स्मॉग ही दिल्ली की तरफ आता है, शेष 80 प्रतिशत स्मॉग दिल्ली का ही होता है। इसमें दिल्ली के ट्रेंचिंग ग्राउंड की आग से उठने वाला धुंआ भी शामिल है। हालांकि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या एक-दो साल की नहीं है बल्कि एक दशक से है। गाजियाबाद से दिल्ली तक लगभग 15-20 किलोमीटर तक धुंध, धुंआ और कोहरे के बादल, कूड़े-कचरे के पहाड़ से उठते धुंए से आच्छादित क्षेत्र से जब हम गुजरते हैं, तब लगता है जैसे पुराणों में वर्णित, पाताल लोक या किसी अंधलोक में पहुंच गए हों। (संभव है दिल्ली की अन्य दिशाओं में भी गाजियाबाद से दिल्ली तक 15-20 किलोमीटर के दायरे में जो स्थिति है वही होगी, क्योंकि मैं उधर कभी नहीं गया।) वैसे भी केजरीवाल ने झूठी भाषणबाजी और आरोपबाजी से इतर बाकी दिल्ली की समस्या से संबंधित किसी क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया। वो शुरू से ही समस्या का समाधान न करके इसका राजनीतिकरण करते रहे। जो नीतियां केजरीवाल की रही, उन्हीं लाइनों पर आजकल उनकी बनाई हुई चीफ मिनिस्टर आतिशी मार्लेना चल रही हैं। जहां तक आतिशबाजी की बात है, तो उनका तो नाम ही 'आतिशी' है।

- **2013 का साल देश में बड़ी आपदाओं का रहा है, पहली त्रासादी में 16 जून, 2013 को उत्तराखंड में बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को तबाह कर दिया, दूसरी त्रासदी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के रूप में आई, जिसने दिल्ली बर्बाद कर दी।**
- **धुंध की घुटन से सर्वाधिक मरण दिल, अस्थमा, सांस, एलर्जी और आंखों के रोगियों का होता है, छात्रों के स्कूल-कालेज बंद हो गए हैं, एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में खुले में पड़े प्रतीक्षारत दूर-दराज से आए मरीजों तथा उनके तीमारदार भी इस जहर का कहर सहने को अभिशप्त हैं।**

2013 की दो बड़ी त्रास्दी

2013 का साल देश में बड़ी आपदाओं का रहा है। पहली त्रासादी 16 जून, 2013 को उत्तराखंड में बादल फटने से आई, विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को तबाह कर दिया। इस बाढ़ में हजारों की संख्या में लोग बह गए जिनमें से कई लोगों के शव कभी मिले ही नहीं। केदारनाथ की त्रासदी को देश शायद कभी भूल पाए। केदारनाथ का भ्रमण तीर्थ-यात्रा के रूप में किया जाता, तो शायद 16 जून की विभीषिका कभी न होती, पर लोग तो इसे पिकनिक समझने लगे और केदारनाथ जाकर धूर्तता और अय्यारी करने लगे। देवात्मा हिमालय पर जाकर ये करोगे, तो प्रभु या प्रकृति कहर तो बरपाएगी ही। इसी तरह 2013 में दूसरी त्रासदी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के रूप में आई। दिल्ली की जनता ने मासूम और भोली सी सूरत देखकर अरविंद केजरीवाल के हाथों में अपना भविष्य सौंप दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के कंधों का इस्तेमाल कर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया। केजरीवाल ने रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे को आमरण अनशन पर बैठाया तभी साफ कर दिया था कि रामलीला मैदान के आंदोलन से जो पार्टी निकलेगी वो भी भ्रष्ट और मक्कार हो सकती है। फिर भी दिल्ली की जनता ने

मुख्यमंत्री सहित दिल्ली के लगभग सभी मंत्री ऐसे हैं, जिनकी मवाली, बवाली, रिश्वती दूसरों को पीटने और दूसरों से पिटवाने वाले, बलात्कारी, फर्जी डिग्री होल्डर, दूसरों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले, मक्कार, ढोंगी, झूठे और दूसरों की मानहानि करने वालों में गणना होती है।

अरविंद केजरीवाल जैसे झूठे, मक्कार, महत्वाकांक्षी और नशे के सौदागर के गिरोह को वोट देकर जो पाप किया, उसकी सजा तो दिल्ली की जनता को मिलनी ही चाहिए। अपने आपको 'आम' आदमी बताकर जनता को गुमराह करने वाले आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता सत्ता में आते ही आम से बहुत 'खास' बन गए। अपवाद को छोड़कर केजरीवाल के सभी विधायक करोड़पति हैं। उनकी महानता का गुणानुवाद करना कठिन है।

दिल्ली ने जो बोया है वही काट रही

मुख्यमंत्री सहित दिल्ली के लगभग सभी मंत्री ऐसे हैं, जिनकी मवाली, बवाली, रिश्वती दूसरों को पीटने और दूसरों से पिटवाने वाले, बलात्कारी, फर्जी डिग्री होल्डर, दूसरों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले, मक्कार, ढोंगी, झूठे और दूसरों की मानहानि करने वालों में गणना होती है। यही कारण है कि इस समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित ज्यादातर मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमें चल रहे हैं, ज्यादातर मंत्री जमानत पर हैं। इनकी अक्ल की झलक गत वर्षों में दूरदर्शन पर तब देखने को मिली थी, जब इनके पर्यावरण मंत्री गोपालराय नाक के छिद्रों अर्थात नथनों के नीचे मास्क चढ़ाए हुए पर्यावरण पर ज्ञान दे रहे थे। लिहाजा पाप का फल सभी को मिलता है। 'अश्वत्थामा मारा गया' जैसे संदिग्ध सत्य पर भी धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ क्षण नरक में बिताने पड़े, जबकि धर्मराज के साथ मात्र जीवनभर रहने के फलस्वरूप उनका कुत्ता भी उनके साथ स्वर्गगामी बन गया। फिर दिल्ली की जनता को अपनी करनी का फल क्यों नहीं मिलता? प्रदूषण बढ़ने का पाप पड़ोसी प्रदेशों हरियाणा, पंजाब मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भी है, पर उन्होंने केवल 20 प्रतिशत प्रदूषण ही बढ़ाया है। इसलिए उन्हें धुंध का कहर रूपी जहर भी 20 प्रतिशत ही मिलता है। जबकि इस पाप में दिल्ली की भागीदारी 80 प्रतिशत है। इसलिए उस पर जहर का कहर भी 80 प्रतिशत है। यानी दिल्ली ने जो बोया है वही काट रही है।

अपेक्षित सुधार जरूरी

संशोधित विधेयक में चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का दर्जा मिलने पर भविष्य में होने वाले चुनाव में अनियमितता होने पर पता चलेगा कि क्या कार्रवाई होती है? सरकार द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त निरंकुश होकर कार्य नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का दर्जा मिलने पर दंडित करने का अधिकार होना जरूरी है।

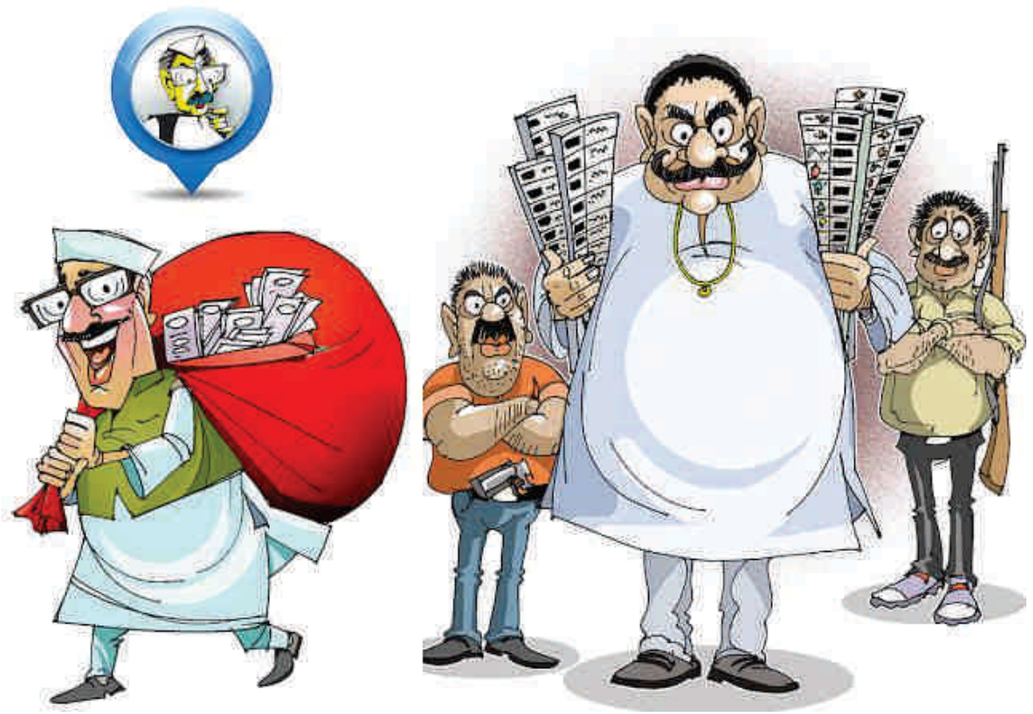

कमल कांत शर्मा

लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की अहम भूमिका होती है। चुनाव के माध्यम से मतदाता अपने और देश के हित में निर्णय लेने वाले जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। चुनाव प्रणाली का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशासन तंत्र के माध्यम से होता है। निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं सहयोगी के तौर पर चुनाव आयुक्त तथा अधिकारी होते हैं। निर्वाचन आयोग भी अन्य सरकारी विभागों की तरह है। इसी लिए सरकार के निर्देश का पालन चुनाव आयुक्त और अन्य अधिकारी करते हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा आपत्तिजनक भाषण देने पर चुनाव आयोग कुछ दिन के लिए प्रचार पर रोक लगाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। चुनाव में निर्धारित सीमा से अधिक धन खर्च करने पर भी किसी को दंडित नहीं किया जा सका है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने और कार्रवाई नहीं होने पर चुनाव आयोग विवादों में रहा है। केन्द्र सरकार ने संशोधित विधेयक के जरिये निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति के समकक्ष कर दिया है। इससे पहले पेश विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कानून बनाने का निर्देश दिया था, सरकार ने विधेयक में संशोधन किया है। विपक्ष ने निर्वाचन आयोग को स्वायत्तता प्रदान करने तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की मांग करते हुए सदन से वाकआउट किया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सरकार द्वारा नामित मंत्री होते हैं। विपक्ष की दलील है कि प्रधानमंत्री और नामित मंत्री की पसंद के आधार पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाती है। नेता प्रतिपक्ष अकेला पड़ जाने के कारण मजबूर हो जाता है और उसकी भूमिका औपचारिकता पूरी करने जैसी रहती है। निर्वाचन आयोग को स्वायत्तता मिलना असंभव नहीं, तो कठिन जरूर है। इसी तरह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी सरकार की मर्जी से होती है और भविष्य में भी यही होगा। संशोधित विधेयक में चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का दर्जा मिलने पर भविष्य में होने वाले चुनाव में अनियमितता होने पर पता चलेगा कि क्या कार्रवाई होती है? सरकार द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त निरंकुश होकर कार्य नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का दर्जा मिलने पर दंडित करने का अधिकार होना जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दागदार छवि के नेताओं को प्रत्याशी बनने से रोकना होगा। यह काम न्यायाधीश का दर्जा मिलने वाले चुनाव आयुक्त के लिए चुनौती होगी।

लोकतंत्र का असली मालिक आम आदमी होता है, यह बात अप्रासंगिक होती जा रही है। असली मालिक सिर्फ वोट का जरिया है। लोकतंत्र के असली मालिक तो बाहुबली जनप्रतिनिधि हैं। सभी राजनीतिक दल धनी और बाहुबली को टिकट देते हैं, क्योंकि उनके चुनाव जीतने की ज्यादा उम्मीद होती है।

- **दागी नेताओं से कब मिलेगा जनता को छुटकारा**
- **कानून बनाने के लिए सरकार को करनी होगी पहल**

कानून का दुरुपयोग कर मुकदमे वापस

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त, 2021 में सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिये थे कि उनके राज्य में सांसदों और विधायकों के खिलाफ विचाराधीन मुकदमों की त्वरित सुनवाई कराई जाये। दरअसल राज्य सरकारें आईपीसी की धारा 321 का दुरुपयोग करके अपने राज्य के सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह भी कहना है कि राज्य सरकारें बिना उच्च न्यायालय की अनुमति के मुकदमे वापस नहीं ले सकती हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से प्रदेश के सांसदों व विधायकों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों का रिकॉर्ड मांगा। हाईकोर्ट ने पहले भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का संज्ञान लिया था, परन्तु सरकार ने विधायकों एवं सांसदों के खिलाफ मुकदमों की सूची उपलब्ध नहीं कराई। अब सवाल यह उठता है कि निर्देश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट द्वारा क्या कदम उठाये जाते हैं? उच्च न्यायालय की बिना अनुमति के कानून का दुरुपयोग करके वापस लिये गये मुकदमों के मामले में क्या निर्णय लिया जाता है? बहुत से माननीयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वालों का मानना होता है कि चुनाव जीतकर सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो जायेंगे और मुकदमे वापस हो जायेंगे। कुछ दशक पहले तक अपवाद के तौर पर ही किसी सांसद एवं विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता था। सांसद व विधायक अपराधियों को संरक्षण देकर रौब जमाते थे, लेकिन कुछ वर्षों से दबंग लोग स्वयं नेतागीरी करने लगे हैं। पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव जीत कर जनप्रतिनिधि बनने वाले अनेक माननीयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। यदि कोई नेताजी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या का उल्लेख करता है तो गर्व से जवाब देते हैं कि मुकदमे दर्ज होना तो नेता की योग्यता की डिग्री है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सांसदों व विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई करके त्वरित निस्तारण किया जायेगा तो चुनाव में सजायाफ्ता लोग उम्मीदवार नहीं बन पायेंगे। ग्राम पंचायत और निकाय चुनाव में भी निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमों का निस्तारण फास्ट ट्रैक कोर्ट से करने का प्रावधान होना चाहिए।

बाहुबली का बोलबाला

सरकार जनहित व राष्ट्रहित के काम करने के दावे करने से नहीं थकती है। समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरने में संदेह बना रहता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि सरकार की योजना के एक रुपये में से 15 पैसे ही पात्र व्यक्ति तक पहुंचते हैं और शेष धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई बार राजीव गांधी का नाम लिये बिना कह चुके हैं कि अब योजना का पूरा रुपया पात्र व्यक्ति तक पहुंचता है और भ्रष्टाचार के मामले में उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत का पालन कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के मामले में स्वयं को अछूता कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन पर घोटाले का एक भी आरोप नहीं लगा। प्रधानमंत्री पद पर पिछले दस साल से अधिक हैं और भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। विडम्बना यह है कि हाल ही में लोकसभा की 543 सीटों में से 88 प्रतिशत करोड़पति और 43 प्रतिशत उम्मीदवार आपराधिक छवि वाले थे। चुनाव में बाहुबल और धनबल का बोलबाला रहता है। वर्ष 2014 में चुनाव जीतकर नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो संसद भवन की देहरी पर माथा टेककर प्रवेश किया था और संसद को लोकतंत्र का मंदिर होने का सम्मान प्रदान किया था। संसद की देहरी पर माथा टेकने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी हैं। धनबल और बाहुबल पर जीतने वाले सांसद सीना तानकर अहंकार के साथ संसद में प्रवेश करते हैं। करोड़पति होना कोई बड़ी बात नहीं है। गांव और कस्बों में अनेक लोग करोड़पति हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित खर्च से शायद ही कोई लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीत सकता है। चुनाव आयोग को पेश हलफनामा हमेशा संदेह के घेरे में रहता है। अमीर व्यक्ति के सांसद व विधायक बनने पर आपत्ति नहीं है। अपराधी छवि के जनप्रतिनिधियों से जनहित की उम्मीद नहीं की जा सकती और यह लोकतंत्र के

चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दागदार छवि के नेताओं को प्रत्याशी बनने से रोकना होगा। यह काम न्यायाधीश का दर्जा मिलने वाले चुनाव आयुक्त के लिए चुनौती होगी।

लिए अपमानजनक तथा चिंता की बात है। ऐसे बाहुबलियों से घिरे अकेले प्रधानमंत्री मोदी जैसे स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति की स्थिति पर सोचने को मजबूर होना पड़ता है। लोकतंत्र का असली मालिक आम आदमी होता है, यह बात अप्रासंगिक होती जा रही है। असली मालिक सिर्फ वोट देने का जरिया है। लोकतंत्र के असली मालिक तो बाहुबली व धनवान जनप्रतिनिधि हैं। सभी राजनीतिक दल धनी और बाहुबली को टिकट देते हैं, क्योंकि उनके चुनाव जीतने की ज्यादा उम्मीद होती है। अपराधी व बाहुबली जनसेवा तथा जनहित की जगह अपने निर्वाचन क्षेत्र के कमजोर वर्ग को डराने, उनकी जमीन पर कब्जा तथा अपने गुर्गों से प्रताड़ित कराते हैं।

मतदाता की विरक्ति यक्ष प्रश्न

राजनीतिशास्त्र के विशेषज्ञों के सामने यक्ष प्रश्न यह है कि चुनाव के प्रति मतदाता विरक्त क्यों है? कई दशक से मतदाताओं का एक वर्ग मतदान के दिन को अवकाश समझकर घर में आराम करता रहा है। इसी लिए मतदान को अधिकार के साथ दायित्व बताया जाता है। मतदान के प्रति उत्साह नहीं होना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। प्रथमदृष्टया राजनीतिक विश्लेषकों का आंकलन है कि मतदाता में निराशा है। ज्यादातर मतदाताओं का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं के निराकरण पर ध्यान नहीं देते हैं। जनप्रतिनिधि अपना हित करते हैं, जनहित की उपेक्षा करते हैं। सरकारी स्तर से लेकर निजी क्षेत्र के संस्थानों ने मतदाता को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये। किशोर अवस्था के बाद युवा वर्ग को मतदाता बनाने पर विशेष बल दिया गया। पहली बार मतदाता सूची में शामिल होने वालों को वोट देने को प्रेरित करने के लिए शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किये गये। मताधिकार के बारे में जानकारी दी गई। शिक्षण संस्थानों से पद यात्राएं निकाली गईं। राजनीतिक दलों ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ की जिम्मेदारी सौंपी। वार्ड स्तर पर पार्टी संगठन को सक्रिय किया गया। मतदाता सूची के प्रत्येक पन्ने में दर्ज नाम के मतदाता से सम्पर्क को पन्ना प्रतिनिधि बनाये गये। सरकारी कार्यालयों के भवनों पर भी मतदाता को जागरूक करने के लिए वाल पेंटिंग की गई। सारी कवायद के बाद भी मतदान का प्रतिशत गिरने से राजनीतिक दलों में बेचैनी होना स्वाभाविक है।

समीक्षा

मां बचपन और सोनला गांव

यह कहानी साबी की ही नहीं है,बल्कि बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जन्मे, पले-बढ़े और पढ़े उन सभी व्यक्तित्वों की है, जो अपने गांव से आधुनिक शिक्षा और सम्मानजनक जीवकोपार्जन को हासिल करने के लिए बाहरी दुनिया की ओर निकले।

अरुण कुकसाल
चामी, पौड़ी गढ़वाल

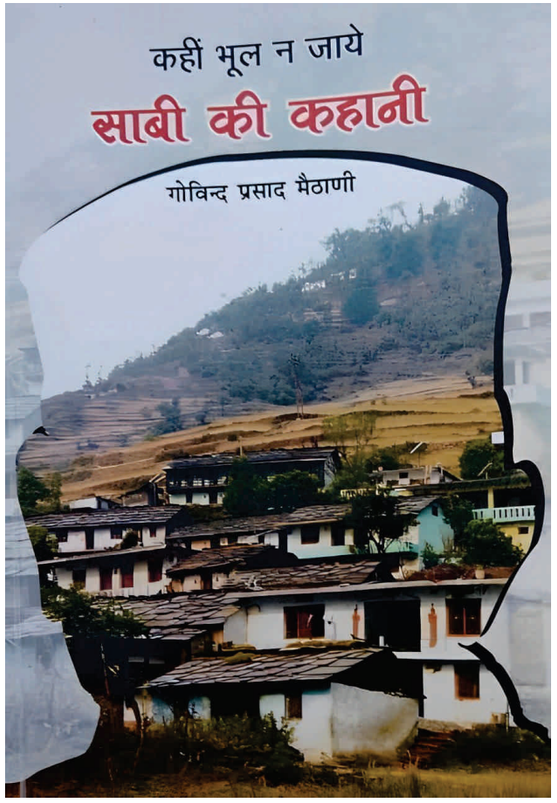

भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे श्री गोविंद प्रसाद मैठाणी की आत्मकथा 'कहीं भूल न जाये-साबी की कहानी' किताब में है। अपने बचपन के 'साबी' नाम को जीवंत करते हुए बेहतरीन किस्सागोई लेखकीय अंदाज में यह खूबसूरत किताब हिमालिका मीडिया फाउंडेशन, देहरादून द्वारा वर्ष-2015 में प्रकाशित हुई है। 'साबी, जीवन में कहां-कहां नहीं भटका और कैसे-कैसे खतरों का बचपन से बुढ़ापे तक सामना नहीं किया? तन-मन की भटकन और मृत्यु से भिडंत उसकी कहानी रही है। सोनला से नंदप्रयाग, नंदप्रयाग से देहरादून वहां से बरेली, श्रीनगर, कानपुर होते हुए मध्य प्रदेश और अन्ततः वापस देहरादून। देहरादून लगता है शारीरिक अटकन की अंतिम कड़ी होगी। भटकनों की इस यात्रा में साबी का मन तो सोनला में ही अटका रहा। अपने गांव के कूड़े का बौंड, ओबरा, हाट्टि, तिबारी, गाड़ का मंगरा, धार का स्कूल, ठौंका का डांडा, धार का पोंगडा, छुणक्यालीं दाथली, पीतल की तमाली, तांबे की गागर, लामसिंग्या बल्द, बचुली भैंसी-कुछ भी नहीं भूला। नौकरी और जीवन की अनेक व्यस्तताओं से भी मन-पंछी फिर-फिर कर सोनला की तिबारी में ही पहुंच जाता है। आज जीवन के घाम का छैल खोला की बांजणी पार करने को है, परंतु 'ज्यूं' है कि वहीं 'रींग' रहा है। हां, अब इस 'ज्यूं' की रींगाट में 'बै' की याद धीरे-धीरे प्रबल होती जा रही है। साबी की 'बै', 'बचपन' और उसका 'गांव' ही उसके 'ज्यूं' के जहाज का अंतिम पड़ाव लगता है।'

मन में समाई यादें अभी ताजा हैं

उक्त कहानी साबी की ही नहीं है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जन्मे, पले-बढ़े और पढ़े उन सभी व्यक्तित्वों की है, जो अपने गांव से आधुनिक शिक्षा और सम्मानजनक जीवकोपार्जन को हासिल करने के लिए बाहरी दुनिया की ओर निकले। भौगोलिक विकटताओं, शैक्षिक पिछड़ेपन और आर्थिक अभावों को पीछे धकेलते हुए वे जीवन और जीविका के क्षेत्र में विख्यात हुए। उनके जीवन को शिक्षा और आर्थिकी ने समृद्ध जरूर किया, लेकिन बाहरी जीवन की नित्य नई जरूरतों, अपेक्षाओं और दायित्वों के भ्रमजाल ने उन्हें जीवन-भर अपने में ही समेटकर रखा। इस जीवनीय प्रक्रिया में आज वे अपने मूल गांव, इलाके और जन-जीवन से बेगाने हुए। जिस समाज और क्षेत्र से वे बाहर निकले थे, वो उनके जीवनीय नेपथ्य में विलीन हो गया। परंतु मन के नाजुक कोने में समाई अनगिनत उनकी यादें आज भी तरो-ताजा हैं।

साबी के बचपन की बेताबी का अंदाज

साबी की यादें नितांत व्यक्तिगत हैं। परंतु साबी इन यादों के खजाने को सार्वजनिक करके नए जमाने को यह संदेश देना चाहता है कि आज के इस सुविधाजनक जीवन की नींव में छिपी उसकी पीढ़ी के त्याग और संघर्ष को नजर-अंदाज न किया जाए। उसे डर है कि नए जमाने की चकाचौंध उसकी पीढ़ी के योगदान को कहीं भूल न जाए, इसलिए साबी उसे आने वाले कल को बताने के लिए बेताब है। यह किताब साबी के बचपन की उसी बेताबी को खूबसूरत अंदाज में बयां करती है। खूबसूरती इतनी अप्रीतम कि उसमें भाषा की जगह भाव ही भाव हैं। वैसे भी मां और बच्चे के बीच भाषा का क्या काम? वहां भाषा को तो चुप रहना ही होता है। मूलतः यह किताब मां, बचपन और सोनला गांव से साबी नाम के बच्चे का वर्षों बाद का आपसी मिलन है। इस मिलन में मां और बचपन अब नहीं है। साथ ही गांव और साबी भी तो वैसे नहीं रहे। गांव और साबी अपने आप से ही दूर हो गए हैं। जीवन में यह क्यों, कब और कैसे घटित हुआ, सोनला गांव एवं उसके साबी को पता ही नहीं चला। आज 'गांव के लिए साबी' और 'साबी के लिए गांव' अंजाना है। पर वो बचपन की यादें हैं कि रोज चली आती हैं, वक्त-बेवक्त साबी से उसके सिरहाने मिलने, बतियाने और उसको सहलाने। ताकि जीवन की नर्म नमी जीवंत रहे। तभी तो कष्टप्रद अतीत की याद भी आज साबी को जीवन का परम आंनद देती हुई लगती है। एक बानगी देखिए-

'चारों तरफ हंयूं ही हंयूं था...। साबी की बै ने कहा 'मास्टर जी को बचन दिया है, जाना तो पडेगा ही' फिर कहा 'अच्छा फूक, रण दे।' साबी ने सुलार बिट्याये और नांगा खुटा ही चल दिया। अपणा खोला का गौळ्या पार कर श्यूराज करौं के खोळा में पहुंचा ही था कि खड़-खड़ कूड़ा की पठाल पड़ी और खचाक उसके सामने गिरी। यदि एक-दो फिट आगे होता तो पठाल गच्च मुंड में पड़ती, तो आज यह किताब ही नहीं बनती।

यह किताब मां, बचपन और सोनला गांव से साबी नाम के बच्चे का वर्षों बाद का आपसी मिलन है, इस मिलन में मां और बचपन अब नहीं है, साथ ही गांव और साबी भी तो वैसे नहीं रहे, गांव और साबी अपने आप से ही दूर हो गए हैं।

साबी को वो ह्यूंदाली रात याद है

अपणा खोला से साबी की बै देख रही थी। वह जोर से भट्याई, 'साबी! न जा, वापस ऐजा'। श्यूराज की बै-चटोल्या बौ भी भैर आई और दौड़ कर साबी को क्वौळी में उठाकर बोली, 'छुट्या बामण कहां जा रहा है,' परंतु साबी उसकी क्वौळी से उतर कर, संस्कार, सीख और बचन से प्रेरित आगे बढ़ गया। कुछ दूर गया ही था कि चड़ा! चड़ ह्यूं के भार से बुड्या तिमला का फांगा साबी की पीठ को छूते हुए धड़ाम से गिर गया। साबी छोटा ही तो था। पूष की रात, पठाल का गिरना, तिमला का फांगा का टूटना, भूत-पिचाश का डर, ठंड से अबोंकी जाना, नन्हीं जान सहन नहीं कर पाया। श्यूराज करौं के ओखला के नीचे गौळ्या से रड़कर दरमानू करौं के बाड़ा में बेहोश होकर गिर गया। बै और चटोल्या बौ ने चट से उठा लिया-परंतु घर के बजाय मास्टर जी के घर पर ही गए। साबी को जब होश आया तो फजल की झंक-मुक दिख रही थी। उसने पास में बै, चटोल्या बौ और मास्टर जी के अश्रुपूरित चेहरों को देखा।...उसने बताया कि मुंड में झन्झन्झाट हुआ। स्वीणा सरीखा आया और स्वीणा में ऐड़ी-आंछरी आई, 'बै' सफेद कपड़े पहने थी और उसके दोनों हाथों के बगल में पंख लगे थे। 'बै' ने साबी को प्यार किया अपने पंखों पर बैठाया और कहीं दूर सर्ग में ले गयी...साबी आज भी उस ह्यूंदाली रात को याद करते रहता है...।

भावना व्यक्त करने का माध्यम

'ऊधौ मोहि ब्रज बिसरत नाहीं...यह मथुरा कंचन की नगरी मनिमुत्ताहल जाही' जैसे चरम वियोग के भाव इस किताब में हैं। जब आदमी बहुत भाव-विभोर होता है, तो उसकी अभिव्यक्ति के स्वर मातृ भाषा के कलेवर में ही बाहर आते हैं। साबी की कहानी भी उसकी मातृ भाषा गढ़वाली के रंग-रूप में उद्घाटित हुई है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि लेखक ने अभिव्यक्ति के प्रवाह को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया है। तभी तो साबी उन्मुक्त और निश्चल भाव से अपनी कथा-व्यथा को कह पाया है। उसके पास अपनी

"साबी, जीवन में कहां-कहां नहीं भटका और कैसे-कैसे खतरों का बचपन से बुढ़ापे तक सामना नहीं किया? तन-मन की भटकन और मृत्यु से भिडंत उसकी कहानी रही है। सोनला से नंदप्रयाग, नंदप्रयाग से देहरादून वहां से बरेली, श्रीनगर, कानपुर होते हुए मध्य प्रदेश और अन्ततः वापस देहरादून। देहरादून लगता है शारीरिक अटकन की अंतिम कड़ी होगी। भटकनों की इस यात्रा में साबी का मन तो सोनला में ही अटका रहा।"

भावनाओं को सबसे बेहतर तरीके से बताने का यही माध्यम था। यही नहीं मैठाणी जी ने इन ठेठ गढ़वाली शब्दों और संबोधनों का कहीं रूपान्तरण भी नहीं किया है। तभी तो उनके गांव की मिट्टी की ताजगी की खुशबू और मौलिकता से पाठक किताब के विराम तक आनंदित होता रहता है। वास्तव में, साबी की कहानी 20वीं शताब्दी के पहाड़ी युवाओं के जीवनीय संघर्ष के जज्बे की कहानी है। साथ ही सांस्कृतिक परिवेश और जड़ों से दूर हुए व्यक्ति की मनोदशा का आत्म-व्याख्यान है। यह किताब हमें उन दुर्गम और घुमावदार पगडंडियों की ओर वापस ले जाती है, जिन पर चल कर हमारे अग्रजों ने जीवन में पद-प्रतिष्ठा के चरम को हासिल किया है। लेकिन जीवनीय सफलता से मिले सुख और सुविधाओं की ओट में कुछ ऐसा है जो निरंतर छूटता गया है। जीवन की नियति देखिए कि उम्र, अनुभव, ज्ञान, हुनर, पद-प्रतिष्ठा और संपन्नता के ऊंचे पड़ाव पर पहुंच कर भी बचपन को फिर से पाने, उसमें जीने या उसे मात्र स्पर्श करने की ललक बढ़ती जा रही है। यह कामना हममें तब तक रहेगी, जब तक जीवन है। परंतु जीवन के उस स्वर्णिम अतीत और सुविधायुक्त वर्तमान के बीच की लकीरें गहरी हो गई है। इन लकीरों से पार पाना संभव नहीं है। परंतु आदमी के 'मन का हंस' तो आज भी यही कहता है 'जैसे उडि जहाज कु पंछी, पुनि-पुनि जहाज पै आवे'। यही जीवन की गति और नियति है। ●

उत्तरांचल दीप
पत्रिका

उत्तराखंड की तेजी से बढ़ती मैगजीन
चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने, नैनीताल रोड हल्द्वानी
देहरादून कार्यालय:-11 लिटन रोड देहरादून (उत्तराखंड)

सदस्यता फार्म

प्रबंधक
उत्तरांचल दीप
हल्द्वानी (नैनीताल)

मान्यवर,
मैं उत्तरांचल दीप पत्रिका की एक वर्ष की सदस्यता लेना चाहता हूं। पत्रिका का वार्षिक शुल्क रुपये 450 नकद, बैंक ड्राफ्ट,चेक संख्या.....भेज रहा हूं। मुझे पत्रिका भिजवाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। मेरा पता इस प्रकार है। चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट **उत्तरांचल दीप** के नाम से स्वीकार होगा।

सदस्य का नामः-

पिता अथवा पति का नामः-

डाक का पताः-

तहसीलः-

जिलाः-

मोबाइल नंबरः-

ई-मेलः-

यदि आपको लेखन में रुचि है तो आप लेख अथवा स्टोरी लिखकर उत्तरांचल दीप पत्रिका के संपादक को भेज सकते हैं। संपदकीय टीम द्वारा आपकी स्टोरी का चयन करने पर आपके लेख को उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। याद रखें कि स्टोरी अथवा लेख आपका मूल होना चाहिए। अच्छी स्टोरी व लेख को उत्तरांचल दीप पत्रिका द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

संपादक

फिल्म

नर्वस थे शोले के गब्बर सिंह

गब्बर सिंह का रोल मिलने पर अमजद खान बेचैन हो गए और बेचैनी भरी आवाज में अमजद खान ने अपनी पत्नी शैला से पूछा कि 'तुम्हें लगता है मैं ये रोल सही से निभा पाऊंगा?' वो बार-बार शैला से यही पूछ रहे थे, शैला बोली, 'बिल्कुल, तुम अच्छे एक्टर हो, मैंने तुम्हारे सभी नाटक देखे हैं।'

अरुण सिंह
मुंबई ब्यूरो

शोले फिल्म में गब्बर सिंह का रोल का आफर मिलने पर क्या अमजद खान नर्वस हो गए थे? क्या उन्हें खुद पर यकीन नहीं रहा था कि वो इस बड़ी फिल्म में गब्बर का रोल ईमानदारी से निभी भी पाएंगे या नहीं? शायद इसलिए रोल का आफर मिलने पर अमजद खान बेचैन हो गए और बेचैनी भरी आवाज में अमजद खान ने अपनी पत्नी शैला से पूछा कि 'तुम्हें लगता है मैं ये रोल सही से निभा पाऊंगा?' वो बार-बार शैला से यही पूछ रहे थे। शैला बोली, 'बिल्कुल, तुम अच्छे एक्टर हो। मैंने तुम्हारे सभी नाटक देखे हैं।' पत्नी की बात सुनकर अमजद बोले, 'लेकिन ये नाटक नहीं है, ये फिल्म है। एकदम अलग चीज है नाटक से।' 'तो क्या हुआ? तुम लव एंड गॉड फिल्म से जुड़े रहे हो। तुम्हारे पिता भी एक्टर हैं। तुम भी कर लोगे।' लेकिन उस वक्त बेचैनी अमजद खान पर इतनी हावी थी कि पत्नी की बातों से उन्हें कोई सुकून नहीं मिला रहा था। वो बोले, 'इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं मैं रोल सही से कर भी सकूंगा कि नहीं।' उसी शाम अमजद खान को फिल्म शोले की शूटिंग के लिए बैंगलोर निकलना था। लेकिन वो मन ही मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे। शोले बहुत बड़ी फिल्म थी। उनके पास विफल होने का कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें हर हाल में अच्छा काम करना था। जब बेचैनी कम नहीं हुई तो अमजद खान ने कुरान को अपने माथे से लगाया और आंख बंद करके दुआ करने लगे। अमजद को ऐसा करते देख उनकी पत्नी शैला बड़ी हैरान हुई। अमजद खान स्पिरिचुअल जरूर थे। लेकिन इस तरह कुरान के साथ कोई दुआ-प्रार्थना करते हुए उन्होंने अमजद को बहुत कम ही देखा था। शैला के लिए अमजद का वो सब करना एक दुर्लभ बात थी। कुछ देर बाद कुरान को उसकी जगह रखकर अमजद खान शैला से बोले, 'मुझे लगता है मैं कर लूंगा।'

अमजद खान एयरपोर्ट के लिए निकल गए। मुंबई एयरपोर्ट से प्लेन टेकऑफ तो हुआ। लेकिन बैंगलोर नहीं पहुंचा। हाइड्रोलिक फेल्योर की वजह से पायलट मुंबई के ऊपर ही प्लेन को घुमाता रहा। कुछ घंटे तक प्लेन यूं ही मुंबई के चारों तरफ उड़ता रहा और फिर वापस मुंबई एयरपोर्ट पर ही आकर लैंड हो गया। अमजद खान एयरपोर्ट पर रुक गए। उन्होंने घर फोन करके नहीं बताया कि उनकी फ्लाइट के साथ क्या हुआ? कोई पांच घंटे बाद घोषणा हुई कि प्लेन की टैक्निकल समस्या दूर कर ली गई है। प्लेन फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन अधिकतर यात्री उस प्लेन में फिर से सवार होने की हिम्मत नहीं जुटा सके। आखिर में चार या पांच लोग ही उस जहाज में फिर से बैठे। उनमें से एक अमजद खान थे। अमजद को हर हाल में बैंगलोर पहुंचना था। कुछ देर बाद प्लेन ने फिर से उड़ान भरी। रास्ते भर अमजद को इस बात की फिक्र नहीं हुई कि उनकी पत्नी और उनका एक महीने का बेटा घर पर अकेले हैं। वो सोच रहे थे कि अगर ये फ्लाइट क्रैश हो गई तो डैनी को गब्बर सिंह के रोल में फिर से साइन कर लिया जाएगा।

अमजद को इस बात की फिक्र नहीं हुई कि उनकी पत्नी और उनका एक महीने का बेटा घर पर अकेले हैं, वो सोच रहे थे कि अगर ये फ्लाइट क्रैश हो गई तो डैनी को गब्बर सिंह के रोल में फिर से साइन कर लिया जाएगा।

धोबी के डायलॉग नकल की

12 नवंबर 1940 को मुंबई में अमजद खान का जन्म हुआ था। अमजद खान का जिक्र हो तो जेहन में पहली छवि शोले के डाकू गब्बर सिंह की ही उभरती है। हालांकि अमजद खान ने फिल्मों में कई और भी शानदार किरदार निभाए थे, लेकिन गब्बर सिंह की छवि से वो कभी उबर नहीं सके थे। उन्हें इस बात का दुख अंतिम समय तक रहा। एक रोचक इत्तेफाक अमजद खान की जन्मतिथि से भी जुड़ा है। जिस दिन अमजद खान का जन्मदिन होता था, ठीक उसी दिन किसी समय में बॉलीवुड के बहुत नामी स्क्रीनराइटर व शायर रहे अख्तर-उल-ईमान का जन्मदिन भी होता था। अख्तर-उल-ईमान 12 नवंबर 1915 को जन्मे थे। लेकिन जो असली इत्तेफाक है वो कुछ यूं है कि अमजद खान की पत्नी शैला इन्हीं अख्तर-उल-ईमान की बेटी हैं। यानी अमजद खान, अख्तर-उल-ईमान के दामाद थे और ससुर व दामाद, दोनों का जन्मदिन एक ही तारीख को होता था। खैर इस लेख में हम अमजद खान के बारे में बात कर रहे हैं तो फिलहाल पूरा फोकस उन्हीं पर रखते हैं। अमजद खान को जब गब्बर सिंह का किरदार निभाने के लिए रमेश सिप्पी द्वारा फाइनल कर लिया गया तो उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी करनी शुरू कर दी। डाकुओं के बारे में अधिक जानने के लिए अमजद ने अभिशप्त चंबल नाम की एक किताब खरीदी। वो किताब लिखी थी जया बच्चन के पिता तरूण कुमार भादुड़ी ने। इस किताब में लिखी जो बातें अमजद खान को पसंद आती थी वो उन्हें पैन से अंडरलाइन कर लेते और अपनी पत्नी शैला से कहते कि तुम भी ये लाइनें पढ़ो। शीशे के सामने खड़े होकर सारा दिन अपने डायलॉग्स बोलने की प्रैक्टिस करते रहते। अमजद को अपने बचपन के दिनों का एक धोबी बहुत अच्छी तरह से याद था। वो धोबी अक्सर अपनी पत्नी को पुकारते हुए बोलता था, 'अरे ओ शांति।' उस धोबी की इसी लाइन से प्रेरित होकर अमजद खान ने 'अरे ओ सांभा' डायलॉग बोला था।

गब्बर का किरदार मामूली नहीं

अमजद खान शोले फिल्म का हिस्सा कैसे बने? वैसे तो ये किस्सा कई लोगों की जानकारी में होगा, लेकिन तब ये किस्सा अधिक लोगों ने नहीं सुना था न पढ़ा था। क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। किस्सा ये है कि रमेश सिप्पी गब्बर सिंह का रोल डैनी से कराना चाहते थे, लेकिन डैनी ने शोले फिल्म में काम करने से इंकार किया तो सिप्पी कैंप में खलबली मच गई थी। शूटिंग शुरू होने में एक महीने से भी कम वक्त रह गया था और गब्बर सिंह कोई मामूली किरदार नहीं था, बल्कि फिल्म का केंद्रीय किरदार था। गब्बर का किरदार निभाने के लिए ऐसा शख्स चाहिए था जो ना सिर्फ अच्छा एक्टर हो, बल्कि एक करिश्माई व्यक्तित्व भी हो। गब्बर सिंह उतना ही मजबूत दिखना चाहिए था जितने कि फिल्म के दूसरे स्टार्स थे। गलत कास्टिंग करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर गब्बर सिंह के लिए किसी गलत एक्टर को चुन लिया जाता तो पूरी फिल्म बर्बाद हो सकती थी। रमेश सिप्पी और उनके पिता गोपालदास परमानंद सिप्पी (जीपी सिप्पी) ने रंजीत और प्रेम चोपड़ा के नामों पर विचार किया। रंजीत के नाम पर तो मुहर लगने ही वाली थी। मगर न जाने क्यों, रमेश सिप्पी के मन को संतुष्टी नहीं मिली और रंजीत को कास्ट करने का विचार ड्रॉप कर दिया। रमेश सिप्पी उस वक्त गब्बर सिंह के कैरेक्टर को लेकर इतने परेशान थे कि वो प्रेमनाथ को भी गब्बर के रोल में इमैजिन करने लगे थे। प्रेमनाथ को साइन करने के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन जब रमेश सिप्पी यथार्थ के धरातल पर वापस लौटे तो उन्हें अहसास हुआ कि प्रेमनाथ के साथ काम करना किसी भी डायरेक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वैसे भी शोले में पहले ही कई बड़े कलाकार थे। एक साथ इतनी स्टार ईगो झेलना भी तो सिरदर्द होता। ऐसे समय में सलीम खान ने अमजद खान का नाम सुझाया था।

थिएटर जगत में मशहूर थे अमजद

अमजद खान के पिता जकारिया खान उर्फ जयंत एक एक समय में हीरो और बाद में मशहूर चरित्र अभिनेता थे। अमजद उनके छोटे बेटे थे। पिता बेशक नामी कलाकार रहे हों, लेकिन अमजद खान तब सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। एक दफा अमजद के पिता ने उन्हें हीरो के तौर पर लॉन्च करने के लिए 'पत्थर के सनम' नाम से फिल्म अनाउंस की थी, लेकिन वो फिल्म कभी बन ना सकी। अमजद ने के.आसिफ को फिल्म 'लव एंड गॉड' में असिस्ट किया था। लव एंड गॉड में अमजद के पिता जयंत ने भी काम किया था और विकीपीडिया की मानें तो वो उनकी आखिरी फिल्म थी। अमजद ने भी एक छोटा सा रोल 'लव एंड गॉड' फिल्म में निभाया था। कुल मिलाकर फिल्म जगत में अमजद खान की तब कोई पहचान नहीं थी, लेकिन थिएटर जगत में वो बहुत मशहूर थे। सबसे पहले 1963 में जावेद अख्तर ने अमजद को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुए यूथ फैस्टिवल के दौरान हुए 'ऐ मेरे वतन के लोगों' नाम के नाटक में आर्मी अफसर का किरदार निभाते देखा था। कुछ साल बाद रमेश सिप्पी ने भी मुंबई में एक नाटक में अमजद खान को देखा था। उस नाटक में रमेश सिप्पी की बहन सुनीता सिप्पी उर्फ सोनी ने अमजद खान की मां का किरदार निभाया था, लेकिन गब्बर सिंह के किरदार के लिए जब माथापच्ची चल रही थी तब ना तो रमेश सिप्पी को और ना ही जावेद अख्तर को अमजद खान का नाम याद आया।

- **सलीम खान ने अमजद के बारे में काफी सुन रखा था, अचानक अमजद से मिलने के बाद गब्बर के किरदार की गुंजाइश सलीम खान को दिखी, उन्होंने अमजद से कहा कि मैं तुमसे कोई वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बड़ी फिल्म में बहुत अच्छा रोल है, मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिला दूंगा, क्या पता तुम्हारी किस्मत से ये रोल तुम्हें मिल जाए।**
- **अमजद को अपने बचपन के दिनों का एक धोबी बहुत अच्छी तरह से याद था, वो धोबी अक्सर अपनी पत्नी को पुकारते हुए बोलता था, 'अरे ओ शांति' उस धोबी की इसी लाइन से प्रेरित होकर अमजद खान ने 'अरे ओ सांभा' डायलॉग बोला था।**

सलीम खान के जरिये मिला रोल

डैनी के शोले फिल्म छोड़ने के कुछ दिनों बाद बांद्रा के बैंडस्टैंड इलाके में सलीम खान और अमजद खान की मुलाकात हुई। सलीम खान अमजद के पिता को जानते थे। अमजद जब छोटे थे तब उनके पिता से मिलने सलीम खान उनके घर जाते थे। उस दिन अमजद खान और सलीम खान की बात हुई तो सलीम खान ने अमजद से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। अमजद ने बताया कि वो थिएटर कर रहे हैं। फिल्मी काम तब कुछ खास नहीं था। सलीम खान ने अमजद के बारे में काफी सुन रखा था। उस दिन अमजद से मिलने के बाद गब्बर के किरदार की गुंजाइश सलीम खान को दिखी थी। उन्होंने अमजद से कहा कि मैं तुमसे कोई वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बड़ी फिल्म में एक बहुत अच्छा रोल है। मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिला दूंगा। क्या पता तुम्हारी किस्मत से या कोशिश से ये रोल तुम्हें मिल जाए। ये फिल्म का सबसे फाइन रोल है। सलीम खान ने रमेश सिप्पी से अमजद का जिक्र किया। अमजद को मिलने के लिए बुलाया। उनसे दाढ़ी बढ़ाने को कहा गया। सलीम-जावेद और रमेश सिप्पी ने अमजद के बारे में काफी विचार किया। अमजद लग तो फिट रहे थे। लेकिन उनकी कोई पहचान तब नहीं थी। सलीम-जावेद की तरफ से तो अमजद फाइनल थे। लेकिन आखिरी फैसला तो रमेश सिप्पी को ही लेना था। इत्तेफाक से उसी दिन एक्टर सत्येन कप्पू भी सिप्पी के ऑफिस आए थे। रामलाल का कैरेक्टर निभाने के लिए उन्हें तब तक साइन किया जा चुका था। सलीम खान ने उस दिन सत्येन कप्पू से पूछा, कप्पू साहब, क्या अमजद खान आपसे अच्छा आर्टिस्ट है? कप्पू जी ने फौरन जवाब दिया, हां मुझसे अच्छा एक्टर है। यंग है। उसकी थिंकिंग भी फ्रैश है। चार दिन बाद अमजद खान का एक स्क्रीनटेस्ट हुआ। सिप्पी के ऑफिस के गार्डन में अमजद खान की कुछ तस्वीरें ली गई। कहने के मुताबिक अमजद खान ने दाढ़ी बढ़ा ली थी। अपने दांत भी उन्होंने काले किए थे। भाषा भी एकदम परफेक्ट थी। इस तरह अमजद खान को गब्बर सिंह के रोल के लिए फाइनल किया गया था। इस लेख में दी गई सभी जानकारियां फिल्म पत्रकार अनुपमा चोपड़ा द्वारा लिखित पुस्तक शोले मेकिंग ऑफ ए क्लासिक से ली गई हैं। ●

मासिक राशिफल

पंडित उपेन्द्र कुमार उपाध्याय
9897450817, 9897791284
ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदरत्न, कथावाचस्पति, यज्ञानुष्ठान विशेषज्ञ
अध्यक्ष-श्री शिवशक्ति ज्योतिष पीठ, बदायूं
निवास प्रभातनगर, निकट इंद्राचौक, सिविल लाइंस, बदायूं (यूपी)

मेष-

इस माह कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। परिवार में अनबन के कारण तनाव का सामना करना पड़ सकता है। दीर्घावधि लाभ के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना लाभदायक रहेगा। बच्चों या कम अनुभवी लोगों के साथ धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। यह माह रोमांस से भरपूर होने की पूरी संभावना है। मशहूर लोगों से मेलजोल नई योजनाएं सुझाएगा। समय का सदुपयोग करना सीखें। इस माह वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। उपायः घर में गंगा जल छिड़के कार्यसिद्ध होंगे।

वृषभः-

इस माह आलस्य आपके शरीर के लिए विष का काम करेगा। किसी सकारात्मक कार्य में खुद को व्यस्त रखें। किसी बीमारी से जूझने के लिए तैयार रहें। इस माह दूसरों पर खर्च कर सकते हैं। धैर्य की कमी रहेगी, इसलिए संयम बरतें, दोस्तों से संभल बात करें, वरना दोस्ती में दरार पड़ने की आशंका है। बदले मौसम के कारण आप अपना कीमती समय बर्बाद करेंगे। जीवनसाथी की सुस्ती आपके कई कामों पर पानी फेर सकती है। उपायः इस माह नीले कपड़े ज्यादा पहने कार्यसिद्ध होंगे।

मिथुनः-

इस माह आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं, तो सुरक्षित परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ समय बीतेगा। मोहब्बत का खुमार सर पर चढ़ने के लिए तैयार है। टाले हुए काम आपको व्यस्त रखेंगे। इस राशि वाले जातकों को खाली समय में आध्यात्मिक अथवा धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। इससे कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। जीवनसाथी आपसे खुश रहेगा। वैवाहिक जीवन से जुड़ी यादें ताजा होंगी। उपायः केतुशांति या गायत्रीमंत्र का जाप सुबह शाम करें कार्यसिद्ध होंगे।

कर्कः-

इस माह हालात पर पकड़ बनाने की कोशिश शुरू कर सकते हैं, आपकी परेशानी साबुन के बुलबुले की तरह फूटने वाली हैं। घर में किसी धार्मिक आयोजन की वजह से खर्च करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार के योग बन रहे हैं। माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। वैवाहिक संबंधों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। काम में मन लगाएं और भावनात्मक बातों से बचें। किसी सुनी-सुनाई बात पर जीवनसाथी तिल-का-ताड़ बना सकता है। उपायः पांच दिन केले का त्याग कर दें कार्यसिद्ध होंगे।

सिंहः-

इस माह खानपान में सावधानी बरतें। थोड़ी सी लापरवाही बीमारी की वजह बन सकती है। इस माह धन संचय का योग बन रहा है। लोगों को दिया पुराना कर्ज लौट सकता हैं। विश्वसनीय लोगों को अपनी बात समझाने में परेशानी महसूस करेंगे। इश्क की मिठास महसूस होगी। यह माह बढ़िया प्रदर्शन और खास कामों के लिए है। जीवनसाथी के साथ खाली समय बिताते हुए आपको अहसास होगा कि उसे और समय देना चाहिए। उपायः हर शनिवार को हरा चारा गाय को खिलाएं कार्यसिद्ध होंगे।

कन्याः-

इस माह मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है, अच्छाई-बुराई सब इसी से जन्म लेती हैं। जीवनसाथी से पैसों से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर बहस हो सकती है। फिजुलखर्ची पर परिवार के ताने सुनने पड़ सकते हैं। परिवार को पर्याप्त समय दें। बहुत सुंदर और प्यारे व्यक्तित्व से मिलने की संभावना है। सहकर्मी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे ज्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। परिवार के साथ समय बिताएंगे। उपायः लहसुन-प्याज नदी में प्रवाह करें कार्यसिद्ध होगा।

तुलाः-

इस माह कुछ आराम करना जरूरी होगा, आप कुछ दिनों में भारी मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। नई गतिविधियां और मनोरंजन के साधन विश्राम में मददगार होंगे। अनचाहा महमान घर आ सकता है जिससे खर्च बढ़ेगा। अगर पार्टी करने का विचार है, तो अच्छे दोस्तों को ही बुलाएं, जो आपका उत्साह बढ़ाएं। दोस्तों की मदद से कठिन काम पूरे होंगे। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगाएं, आपका जीवनसाथी रोमांच के मूड में हैं उसका ख्याल रखें। उपायः छात्रों को लेखन सामग्री बांटे कार्यसिद्ध होंगे।

वृश्चिकः-

इस माह अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए आपका मस्तिष्क खुला रहेगा। जिन लोगों ने किसी से उधार ले रखा है उन्हें हर हालत में उधार चुकाना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। नाती-पोतों से खुशी मिलेगी। जीवनसाथी को फूल देकर प्यार का इजहार करें। आपकी ईमानदारी से काम करने की क्षमता आपको शोहरत दिलाएगी। वाहन चलाते वक्त सावधानी बरते, दुर्घटना का खतरा है। यात्रा का योग बन रहा है, जिससे खर्च बढ़ेगा। उपायः रात को हल्दी-दूध पीकर सोएं कार्यसिद्ध होंगे।

धनुः-

इस माह रचनात्मक कार्य आपको राहत देंगे, घर की आवश्यक सामग्री पर धन खर्च होगा। न्यायलय संबंधी कार्य में सफलता के योग बन रहे हैं। भविष्य की कई परेशानियों से इस माह छुटकारा मिल सकता है। परिजन छोटी-सी बात का बतंगड़ बना सकते हैं। नई साझीदारी इस माह फलदायी रहेगी। यह महीना सृजनात्मक कार्यों के लिए अच्छा है। जीवनसाथी आपका ज्यादा ख्याल रखेगा। नए कारोबार में निवेश के लिए समय अनुकूल है। उपायः ईश्वर में आस्था रखें मानसिक हिंसा से बचें कार्यसिद्ध होंगे।

मकरः-

इस माह कारोबार में उन्नति के योग बन रहे हैं। सकारात्मक विचार मन में रखें, प्रोन्नति हो सकती है। दूसरों के सुख-दुःख बांटने की आदत बनाएं। यदि आप दूसरों के कहने पर निवेश करेंगे, तो आर्थिक नुकसान की संभावना ज्यादा है। पारिवारिक सदस्यों बेवजह विवाद हो सकता है। आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। प्यार के लिहाज से यह माह आपके लिए खास है। वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव के बाद एक-दूसरे के प्यार को सराहने का सही समय है। उपायः चित्तीदार कपड़े पहने कार्यसिद्ध होंगे।

कुंभः-

इस माह सेहत का विशेष ध्यान रखे, दूर तक पैदल घूम सकते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी में पैसे लुटाने से बचें, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। घर के बुजुर्गों की बेजा मांगों से आप परेशान हो सकते हैं। विवाह-प्रस्ताव के लिए सही समय है। आपका प्यार जीवनसाथी के रूप में बदलेगा। नया कार्य करने की आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। अगर घर से बाहर रहकर अध्ययन या नौकरी करते हैं तो खाली समय में अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। उपायः चन्द्रमा की चांदनी में बैठकर खीर खाएं कार्यसिद्ध होंगे।

मीनः-

यह माह आपके जीवन-साथी को खुशी दे सकता है। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, लेकिन व्यर्थ के खर्च बचने की कोशिश करें। रिश्तेदारी में छोटी यात्रा करने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग बन रहे हैं। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। दफ्तर में आपकी तारीफ होगी। परिवार के साथ वार्तालाप करते समय सावधानी बरते। आपके मुंह से निकली कोई बात परिजनों को नाराज कर सकती है। शादीशुदा जिंदगी में सुकून मिलेगा। उपायः अपने गुरु व बच्चों की मन से मदद करें कार्यसिद्ध होंगे।

nupur.com NRITYA
नुपुर नृत्य कला केंद्र हल्द्वानी
में सभी के लिए 01 फरवरी 2021 से पुनः
कक्षाएं आरंभ
हो गई है।
जिसमें क्लॉसिकल डांस, तबला वादन, सेमी क्लासिकल, गिटार, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करते हुए तथा कक्षों (क्लास) को नियमित रूप से सेनेटाइज कर आधुनिक तरीके से देने की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है ।
एडमिशन के लिए संपर्क करें।
www.facebook.com/nupurnrityakalakendra
You Tube: Search: nupurnrityakalakendra
nupurnritya99@gmail.com
www.nupurnritya.com
NEAR KANDPAL ENT. Hospital, SHAKTI SADAN GALI, NAWABI ROAD, HALDWANI (NAINITAL), Uttarakahnd
05946 220841, 91 9760590897
91 9411161794